चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

कौन देता है नक्सलियों को पैसा ?

पेज 3

गडकरी का हेडमास्टर कौन ?

पेज 5

वायदों के भ्रमजाल में मुसलमान

पेज 6

कराहती नदियां

पेज 7

मूल्य 5 रुपये

दिल्ली, 26 जुलाई–1 अगस्त 2010

फोटो– *प्रभात पाण्डेय*

चिदंबरम जी, आप किसके साथ हैं?

केंद्र सरकार में वे कौन से लोग हैं, जो देश को अंधे युद्ध की तरफ़ ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं. एक ओर सात प्रदेशों में विकास का काम ठप है और सारा पैसा ख़र्च भी हो रहा है, दूसरी ओर इन्हीं प्रदेशों में विकास की अनदेखी और ग़रीबों के हितों के लिए लड़ने वालों के नाम पर जाने जाने वाले नक्सलवादियों के पास करोड़ों रुपये नियमित रूप से भेजे जा रहे हैं. नियमित रूप से करोड़ों रुपये देने वालों में देश के पूंजीपतियों के साथ सरकारी संस्थान भी हैं. नक्सलवादियों के बीच ऐसे ग्रुप बन गए हैं, जो इन रुपयों का विनिवेश करते हैं और अपना निजी आर्थिक साम्राज्य बना रहे हैं. भारत सरकार इस पर आपराधिक चुप्पी साधे है. यह रिपोर्ट देश के गृहमंत्री चिदंबरम से जवाब चाहती है.

प्रभात रंजन दीन

नक्सलियों के ख़िलाफ़ सेना उतारने पर आमादा केंद्रीय गृह मंत्रालय नक्सली संगठनों को अरबों रुपये का फंड देने वाले उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की लिस्ट वर्ष 2007 से दबाए बैठा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा. हैरत की बात यह है कि नक्सलियों को फंडिंग करने वालों में सरकारी महकमे और उपक्रम भी शामिल हैं. सरकार की ढिलाई से नक्सलियों को की जाने वाली फंडिंग लगातार बढ़ती ही चली गई, लेकिन नक्सली संगठनों की आर्थिक रीढ़ तोड़ने के बजाय केंद्र सरकार हवा में लाठी भांजने का उपक्रम करती रही है. केंद्र सरकार या केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम की नक्सली मामले में दिखने वाली गंभीरता क्या महज़ दिखावा है? यह गंभीर सवाल सामने इसलिए है, क्योंकि गृह मंत्रालय को 2007 में ही ख़ुफ़िया एजेंसियों की तरफ़ से यह विस्तृत सूचना मुहैया करा दी गई थी कि नक्सली संगठनों को नक्सल प्रभावित राज्यों के किन-किन औद्योगिक घरानों, पूंजीपतियों, व्यापारियों, ठेकेदारों, सरकारी उपक्रमों, जमींदारों और यहां तक कि बीडीओ और सीडीओ तक के यहां से लगातार लाखों रुपये की फंडिंग की जा रही है. लगातार होती इस फंडिंग की वजह से नक्सली संगठन क्रमशः ताक़तवर होते चले गए और कई राज्यों में उनकी समानांतर सरकार क़ायम होती चली गई. नक्सली संगठनों को की जाने वाली फंडिंग की आधिकारिक सूचना पर झारखंड समेत कई राज्यों की पुलिस ने बाक़ायदा एफआईआर दर्ज की और उन सूचनाओं को विस्तार से डेवलप कर ख़ुफ़िया एजेंसियों ने केंद्र सरकार को विस्तृत रिपोर्ट और लिस्ट भी पेश कर दी, लेकिन रहस्यमय बात यह है कि वह लिस्ट केंद्र सरकार ने दबा दी और हवाबाज़ी करती रही. विचित्र, किंतु सत्य यह है कि नक्सलियों के ख़िलाफ़ सेना उतारने पर आमादा दिखने वाले केंद्रीय गृहमंत्री पलनियप्पन चिदंबरम के मंत्रालय में ही वह लिस्ट 2007 से दबी पड़ी है. विडंबना देखिए कि ख़ुद केंद्र सरकार ही आधिकारिक तौर पर यह कहती रही कि नक्सली संगठनों की फंडिंग लगातार बढ़ती जा रही है. ख़ुफ़िया एजेंसी के आला अधिकारियों का कहना है कि 2007 से लेकर 2010 तक की लिस्ट केंद्र सरकार के पास उपलब्ध है. लिहाज़ा, सरकार द्वारा इसे चिंता का विषय बताया जाना महज़ फ़र्ज़ी बयानबाज़ी के अतिरिक्त और कुछ नहीं. औद्योगिक घरानों, व्यापारियों, पूंजीपतियों और माफ़ियाओं ने नक्सली संगठनों को धन देकर अपनी सुरक्षा की गारंटी तो ले ली, लेकिन आम लोगों और अर्धसैनिक बलों की जान पर बन आई. अब सेना की जान लेने पर ख़ुद देश के सियासतदां आमादा हैं.

अमेरिका की पिछलग्गू केंद्र सरकार ने अमेरिका से भी कोई सीख नहीं ली. पूरी दुनिया यह जानती है कि अमेरिका ने आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई छेड़ने के पहले न केवल अमेरिका, बल्कि दुनिया भर में फैले तमाम आतंकवादी संगठनों की आर्थिक नकेल कस दी थी. अमेरिका ने बाक़ायदा घोषणा कर आतंकवादी संगठनों के आर्थिक स्रोत काट डाले. जहां जिस बैंक के खाते का पता चला, उसे सील कर दिया गया और धन का ज़रिया तहस-नहस कर डाला गया. लेकिन भारत में सत्ताधारी नेता डायलॉग तो बड़े-बड़े बोलते रहे, पर नक्सलियों का आर्थिक स्रोत और मज़बूत होता चला गया. नक्सलियों को धन देने वाले उद्योगपतियों के ख़िलाफ़ आज तक कोई बड़ी नक्सली कार्रवाई नहीं हुई, न उनके औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर कोई आंच आई, न उनके उत्पाद लूटे गए या बर्बाद किए गए. जबकि उसी फंड से नक्सली संगठन अत्याधुनिक हथियार ख़रीदते रहे और उनसे आम लोगों और अर्धसैनिक बल के जवानों की बेमानी हत्याएं की जाती रहीं. ऐसे अजीबोग़रीब हालात में देश के लोगों के सामने यह भ्रम पैदा होना लाज़िमी है कि आख़िर नक्सलियों का समर्थक कौन है? आप यह जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव, शिबू सोरेन, नीतीश कुमार एवं ममता बनर्जी समेत कई नेताओं पर नक्सलियों से साठगांठ कर चुनाव में मदद लेने के आरोप सार्वजनिक तौर पर लगते रहे हैं. ये केवल आरोप नहीं हैं, बल्कि इनमें थोड़ी सच्चाई भी है. कामेश्वर बैठा एवं पॉलुस सुरीन जैसे नक्सली कमांडर इन नेताओं के समर्थन से चुनाव भी जीत चुके हैं और अपने समर्थन से कई नेताओं को चुनाव जितवा भी चुके हैं. लेकिन नक्सलियों की फंडिंग मसले पर चुप्पी साध कर देश का ध्यान दूसरी तरफ़ ले जाने वाले सत्ताधारी नेता नक्सलियों के समर्थक नहीं हैं, बल्कि वे औद्योगिक घरानों और पूंजीपतियों का हित साध रहे हैं कि कहीं उनका कोई नुक़सान न हो जाए और वे कहीं क़ानून के शिकंजे में न फंस जाएं. स्पष्ट है कि दोनों तरह के लोग देश की राजनीति पर हावी हैं, वोट के लोभ में नक्सलियों का समर्थन करने वाले नेता और पूंजीपति घरानों का हित साधने में सत्ता का इस्तेमाल करने वाले नेता. मरना आम आदमी को है या सेना और अर्धसैनिक बल के जवानों या अफसरों को.

नक्सलियों को फंडिंग करने वाले औद्योगिक घरानों और पूंजीपतियों की 2007-08 तक की लिस्ट जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की थाती बनी रही है, उसमें से झारखंड की लिस्ट *चौथी दुनिया* को हासिल हुई है. आप यह जानते ही हैं कि नक्सली अभी सबसे अधिक ताक़तवर झारखंड में हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय यह बयान भी देता रहा है कि नक्सली संगठनों को सबसे अधिक धन झारखंड राज्य से ही मिलता है. खनिजों और उद्योग-धंधों में सबसे संपन्न राज्य से कमाई करने वाले उद्योगपति नक्सली संगठनों को भी संपन्न करने में लगे रहे और केंद्र सरकार देश के लोगों का ध्यान दूसरी तरफ़ हटाती रही. राष्ट्रसेवा के नाम पर नेताओं की स्वयंसेवा हावी रही और नक्सली पूरे मध्य भारत पर हावी होते चले गए.

चौथी दुनिया के पास जो 26 पेज की लिस्ट उपलब्ध है, उसमें 550 से अधिक नाम हैं. इनमें रांची ज़िले के 48, गुमला के 22, पलामू के 53, लातेहार के 41, गढ़वा के 71, हजारीबाग के 40, रामगढ़ के 10, चतरा के 22, गिरिडीह के 55, कोडरमा के 5, चाईबासा के 30, जमशेदपुर के 15, सरायकेला के 43, बोकारो के 84, धनबाद के 7 उद्योगपति, पूंजीपति, व्यापारी, ठेकेदार, सरकारी उपक्रम और प्रखंड (ब्लॉक) शामिल हैं. धनबाद ज़िले के टूंडी, तोपचांची और गोविंदपुर ब्लॉक झारखंड में नक्सलियों को सबसे अधिक धन देने वाले सरकारी महकमे हैं. नक्सलियों को धन देने वालों में लकड़ी और कोयले के कई कुख्यात तस्कर भी शामिल हैं. 2007-08 में झारखंड के रांची ज़िले से नक्सलियों को 65 लाख 56 हज़ार रुपये मिले. इसी तरह नक्सलियों ने गुमला से 15 लाख 25 हज़ार, पलामू से 2 करोड़ 22 लाख, लातेहार से 13 लाख 12 हज़ार, गढ़वा से 11 लाख 65 हज़ार, हजारीबाग से 2 करोड़ 19 लाख 59 हज़ार, रामगढ़ से 6 लाख, चतरा से 11 लाख 5 हज़ार, गिरिडीह से 1 करोड़ 14 लाख 76 हज़ार, कोडरमा से 12 लाख, चाईबासा से 4 करोड़ 46 लाख 30 हज़ार, जमशेदपुर से 56 लाख, सरायकेला से 24 लाख 85 हज़ार, बोकारो से 45 लाख 15 हज़ार और धनबाद ज़िले से 64 लाख रुपये की कमाई की. यह पूरी लिस्ट हम विस्तार से प्रकाशित कर रहे हैं. इनमें से कई नाम देखकर आप चौंकेंगे और समझेंगे कि देश की व्यवस्था असलियत में कैसी है. यह केवल झारखंड की लिस्ट है, देश भर की लिस्ट जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की फाइलों में गुम है, उससे नक्सलियों की फंडिंग की गंभीरता और मारक क्षमता के बारे में आप बख़ूबी कल्पना कर सकते हैं.

नक्सलियों को फंडिंग करने वाले औद्योगिक घरानों और पूंजीपतियों की 2007-08 तक की लिस्ट जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की थाती बनी रही है, उसमें से झारखंड की लिस्ट *चौथी दुनिया* को हासिल हुई है. आप यह जानते ही हैं कि नक्सली अभी सबसे अधिक ताक़तवर झारखंड में हैं.

दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के जवानों के मारे जाने के कुछ ही दिनों बाद जब नक्सलियों ने यात्रियों से भरी बस उड़ा दी, तब केंद्रीय गृहमंत्री पलनियप्पन चिदंबरम ने नक्सलियों के साथ सहानुभूति रखने वाले लोगों और बुद्धिजीवियों को जी भरकर धिक्कारा था. एक टीवी चैनल पर दिए इंटरव्यू में चिदंबरम ने कहा था कि माओवादियों से सहानुभूति रखने वाले लोग ही नक्सलियों को काबू में करने के सरकार के प्रयासों में रोड़ा बन रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार के उपकरणों को ऐसे लोग कमज़ोर बना रहे हैं. जो लेखक, बुद्धिजीवी, समाजसेवी या एनजीओ कर्मी नक्सलियों से सहानुभूति रखते हैं, गृहमंत्री की निगाह में वे अव्यवहारिक धरातल पर

(शेष पृष्ठ 2 पर)

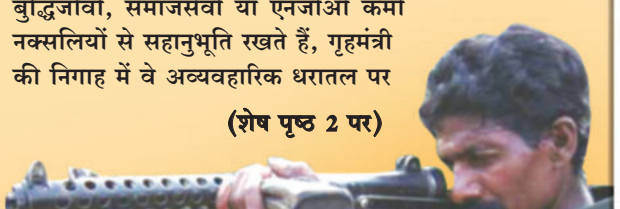

आतंकवाद, शिक्षा सुविधाओं का अभाव और पदोन्नति की सीमित संभावना जैसे तर्कों के आधार पर अधिकारी पूर्वोत्तर के राज्यों में अपनी पदस्थापना को रोकने की हरसंभव कोशिश करते हैं.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

निशाने पर अहलूवालिया

नौकरशाहों की शरणस्थली के रूप में मशहूर योजना आयोग अब केवल नेहरू युग की एक यादगार बनकर रह गया है, लेकिन अगले दो सालों में इसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन हो सकते हैं. और यह जितनी जल्दी हो जाए, उतना ही अच्छा है, क्योंकि आयोग के आलोचकों की संख्या में लगातार इज़ाफा होता जा रहा है. अधिकांश लोग इसके कामकाज और आयोग के कर्ताधर्ता, उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया को निशाने पर ले रहे हैं. उनका तर्क है कि योजना आयोग का ज़मीनी हक़ीक़त से कोई वास्ता नहीं रह गया है. आलोचना के नए दौर की शुरुआत सड़क परिवहन मंत्री कमलनाथ ने की. उन्होंने कहा कि आयोग की सिफ़ारिशें वातानुकूलित कमरों के अंदर कुर्सियों पर बैठकर तैयार की जाती हैं. वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अनिल शास्त्री ने उनकी हां में हां मिलाई तो अब खाद्य सचिव अलका सिरोही भी मैदान में उतर आई हैं. सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को लेकर अलका ने भी मोर्चा खोल दिया है. अहलूवालिया के ख़िलाफ़ इन आलोचनाओं को ख़ुद योजना आयोग की आलोचना के रूप में देखा जा रहा है. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की देखरेख में आयोग को पुनर्गठित करने का जो प्रारूप तैयार किया गया है, उसमें इसका नाम बदलने का भी प्रस्ताव है. इसका नया नाम सिस्टम रिफॉर्म कमीशन हो सकता है. बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ काम कर चुके आयोग के मौजूदा सदस्य अरुण मैरा को यह ज़िम्मेदारी दी गई है. पुनर्गठन का उद्देश्य आयोग को एक ऐसी संस्था के रूप में तब्दील करना है, जिसका दायरा विस्तृत हो, तेज़ी से काम हो और जिसकी सिफ़ारिशें मौजूदा हालात से मेल खाती हों. लेकिन यह तो भविष्य की बात है. फ़िलहाल आलोचकों की बंदूकें तनी हुई हैं और सबके निशाने पर अहलूवालिया ही हैं. इस धींगामुश्ती में नौकरशाह भी एक या दूसरे पक्ष के साथ हां में हां मिलाने को मज़बूर हैं.

अब बचना होगा मुश्किल

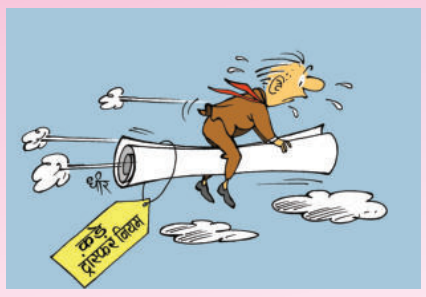

पूर्वोत्तर के राज्यों में पोस्टिंग से बचने के लिए नौकरशाह क्या नहीं करते. इसके लिए वे ऐसे हर नियम–क़ानून का सहारा लेते हैं, जो उनके लिए कारगर हों. नए नियमों की जद में केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर के अधिकारी भी आते हैं और जाहिर है कि इससे दिल्ली में पदस्थापित नौकरशाहों के कान भी खड़े हो गए हैं. आतंकवाद, शिक्षा सुविधाओं का अभाव और पदोन्नति की सीमित संभावना जैसे तर्कों के आधार पर अधिकारी पूर्वोत्तर के राज्यों में अपनी पदस्थापना को रोकने की हरसंभव कोशिश करते हैं. लेकिन गृहमंत्री पी चिदंबरम ने असम, गोवा एवं मिजोरम कैडर के अधिकारियों के स्थानांतरण के नियमों को और कड़ा करने का फ़ैसला किया है, ताकि उक्त अधिकारी अपने मूल कैडर के राज्य में एक निश्चित समय तक काम करने के लिए उपलब्ध हो सकें. सूत्रों के अनुसार, समयबद्ध पदोन्नति के आधार पर वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त आईएएस अधिकारी कुल चौदह साल में केवल छह साल ही दिल्ली में रहेंगे. उन्हें पांच साल तक अरुणाचल और मिजोरम जैसे कठिन इलाक़ों में काम करना होगा तो बाकी तीन साल ग्रेड बी इलाक़ों जैसे गोवा, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में बिताने होंगे. कोई शक नहीं कि सबसे पहले निशाने पर वही अधिकारी हैं, जो लंबे समय से दिल्ली में जमे हुए हैं. संभव है कि जल्द ही बड़े पैमाने पर अधिकारियों का फेरबदल देखने को मिले.

dilipcherian@gmail.com

साउथ ब्लॉक

1977 बैच के लिए ख़ुशख़बरी

सूत्रों के मुताबिक, 1977 बैच के 43 आईएएस अधिकारियों के नाम भारत सरकार में सचिव या इसके समकक्ष पद के लिए सूचित कर लिए गए हैं. इनमें से ज़्यादातर अधिकारी अभी अतिरिक्त सचिव के पद पर हैं. निश्चित तौर पर सालों से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे इन आईएएस अधिकारियों के लिए यह ख़बर महत्वपूर्ण है.

वेरेल्ली बन सकते हैं निदेशक

1993 बैच के आईआरएस अधिकारी अप्पाराव वेरेल्ली को ऊर्जा मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त किया जा सकता है. वेरेल्ली को मलय श्रीवास्तव की जगह पर भेजा जा सकता है. मलय 1990 बैच के एमपी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं. मलय को ऊर्जा मंत्रालय में राज्यमंत्री का पीएस नियुक्त किया गया है.

काम करो वर्ना...

सरकार ने पहली बार शायद इतना कड़ा निर्णय लिया है. तीन आईएएस अधिकारियों को असंतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर दफ्तर से बाहर का रास्ता दिखा दिया है. कैबिनेट की एप्वायंटमेंट कमेटी ने इन तीनों अधिकारियों के समय पूर्व रिटायरमेंट का ऐतिहासिक आदेश जारी कर दिया है. ख़राब कामकाज के आधार पर अब तक किसी भी अधिकारी के साथ ऐसा नहीं हुआ था. कमेटी ने इस आदेश के माध्यम से यह संदेश भी दिया है कि सरकार से बड़ा कोई नहीं है. जिन तीन अधिकारियों पर यह गाज गिरी है, उनके नाम हैं विजेंद्र कुमार (1987 बैच, हिमाचल कैडर), डॉ. देश दीपक (1983 बैच, हिमाचल कैडर) और शालिनी वशिष्ठ (1986 बैच, तमिलनाडु कैडर).

निधि शर्मा जाएंगी मसूरी

ऐसी ख़बर है कि 2000 बैच की आईआरएस अधिकारी निधि शर्मा को मसूरी भेजा जा सकता है. उन्हें वहां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में उप निदेशक के रूप में नियुक्ति मिल सकती है.

चिदंबरम जी, आप किसके साथ हैं?

पृष्ठ 1 का शेष

मनोवैज्ञानिक रूमानियत, फैशन और रॉबिनहुड मनोविकृति से ग्रस्त लोग हैं. गृहमंत्री के इस बयान के दायरे में कौन–कौन लोग आते हैं, यह बहस का विषय नहीं है. बहस का विषय है चिदंबरम की वह चेतावनी, जिसमें उन्होंने कहा था कि समय आने पर ऐसे तमाम लोगों की शिनाख्त की जाएगी... यह कहते हुए पी चिदंबरम नक्सलियों को धन देकर उन्हें ताक़तवर बनाने वाले पूंजीपतियों की शिनाख्त और उन पर कार्रवाई करने की बात बिल्कुल गोल कर गए. फंडिंग करने वाले धनिकों की लिस्ट दबाए बैठे गृह मंत्रालय के ही अलमबरदार हैं पी चिदंबरम, लिहाज़ा उनकी बातों का छद्म साफ–साफ समझ में आता है. चिदंबरम से आगे फांद कर केंद्र की सत्ताधारी कांग्रेस ने अपने प्रवक्ता मनीष तिवारी के ज़रिए नक्सलियों का समर्थन करने वाले लोगों को फिफ्थ कॉलमनिस्ट (भीतर रहकर घात करने वाला) तक बता दिया. लेकिन नक्सलियों को धन देकर उन्हें शक्तिशाली कौन लोग बना रहे हैं और भीतर रहकर घात कौन लोग कर रहे हैं, इस बारे में सत्ता की तरफ़ से शातिराना मौन सधा है.

केंद्रीय ख़ुफ़िया एजेंसी के नक्सल मामले देखने वाले विशेषज्ञ अधिकारियों से नक्सलियों की फंडिंग मसले पर इस संवाददाता की विस्तार से बात हुई. नक्सली संगठनों का बाक़ायदा एक बजट है और केंद्रीय गृहमंत्री भले ही लिस्ट दबाए बैठे रहें, लेकिन ख़ुफ़िया एजेंसी के पास फंडिंग मसले को लेकर सूचनाओं का टोटा नहीं है. 2007–2009 के दरम्यान माओवादियों का बजट 60 करोड़ रुपये था. इसमें से 42 करोड़ रुपये शस्त्र के लिए और दो करोड़ रुपये ख़ुफ़िया सूचनाएं एकत्र करने के लिए रखे गए थे. शेष राशि ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेनिंग, प्रचार एवं प्रकाशन के लिए रखी गई थी. ख़ुफ़िया एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को दी गई रिपोर्ट (लिस्ट) में झारखंड में पकड़े गए माओवादी कमांडर एवं पॉलित ब्यूरो मेंबर मिसिर बेसरा, 2007 में पकड़े गए जोनल कमांडर रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ बीरसेन उर्फ निर्भय, औरंगाबाद (बिहार) के रहने वाले दिल्ली और हरियाणा के अर्बन कमांडर प्रमोद मिश्र एवं कई अन्य नक्सली कमांडरों के इकबालिया बयानों का भी हवाला दिया है. नक्सली संगठन झारखंड, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा की खदानों से केवल धन ही नहीं वसूलते, बल्कि वे उनसे विस्फोटक सामग्री (जिलेटिन एवं डायनामाइट वग़ैरह) भी प्राप्त करते हैं. विडंबना यह है कि अभी हाल ही 17 अप्रैल, 2010 को माओवादी नेता किशन जी का जो लैपटॉप बरामद

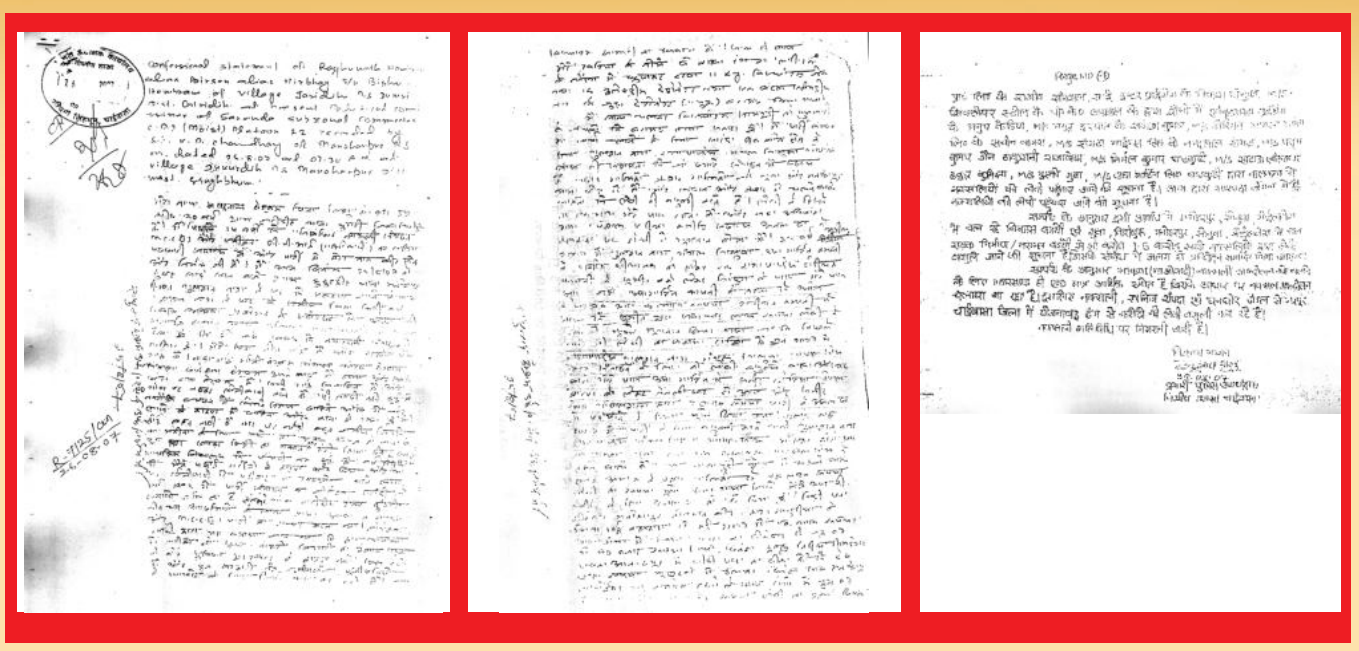

हुआ, उससे मिली सूचनाओं से भी इस बात की पुष्टि हुई कि इस साल झारखंड से माओवादियों को 12 करोड़ 20 लाख रुपये मिले. तीन क्षेत्रों से माओवादी सौ करोड़ रुपये सालाना वसूलते हैं और अपने कैडरों को बाक़ायदा वेतन देते हैं. ख़ुफ़िया अधिकारी नक्सल संगठन को नक्सल कॉरपोरेशन बताते हैं और कहते हैं कि इन्होंने इस साल वसूली का टार्गेट बढ़ाकर डेढ़ सौ करोड़ रुपये कर दिया है. हर साल 15 फ़ीसदी का लक्ष्य बढ़ा दिया जाता है. रंगदारी टैक्स, ड्रग्स, लूट, फिरौती, डकैती के अलावा नक्सली संगठन क़रीब एक करोड़ रुपये अफीम पैदा करने वालों से भी वसूलते हैं. इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास इसका पक्का प्रमाण है कि अफीम पैदा करने वालों से लेवी वसूलने के लिए नक्सली संगठन अफीम की खेती को बढ़ावा भी दे रहे हैं और उन्हें सुरक्षा भी प्रदान कर रहे हैं. आईबी की सूचना का मतलब है कि गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार को इस बारे में पता है, लेकिन कार्रवाई क्या हुई, यह सबके सामने है. बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश से नक्सलियों के कुल राजस्व का 40 फ़ीसदी मिलता है. सबसे अधिक धन खनिज संपन्न झारखंड से मिलता है. बंगाल और उड़ीसा से अपेक्षाकृत कम धन मिलता है, लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों से भी धन आता है. कुछ दिनों पहले रायगढ़ा पुलिस ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टाफ को 13 लाख रुपये ले जाते पकड़ा था, जो नक्सलियों को सुपुर्द करने के लिए ले जाया जा रहा था. उससे ही यह खुलासा हुआ कि जो संस्थान या औद्योगिक प्रतिष्ठान नक्सलियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, उन्हें महज़ 6 फ़ीसदी लेवी देनी पड़ती है. अन्य को 15 फ़ीसदी. यहां तक कि बस और ट्रक यूनियनों को भी टैक्स देना पड़ता है. झारखंड में पांच से 10 प्रतिशत सिविल ठेकेदारों को, 50 रुपये प्रति ट्रक एवं बस और एक हज़ार से पांच हज़ार रुपये तक ट्रक ऑपरेटरों को देना पड़ता है. बंगाल में स्टोन क्रशर, ठेकेदारों, व्यापारियों और यहां तक कि स्कूल टीचरों को भी टैक्स देना पड़ता है.

2007 में नक्सलियों ने हथियारों की ख़रीद के लिए एक ऑस्ट्रियन कंपनी से करार किया था, जो नक्सलियों को मलेशिया, म्यांमार और बंगाल के रास्ते हथियार पहुंचा रही है. आर्थिक स्रोत की बात छोड़िए, केंद्र सरकार इस आर्म्स सप्लाई लाइन को आज तक ध्वस्त नहीं कर पाई. इसके साथ ही नक्सलियों के इस्तेमाल के लिए विशेष टायर और मोटरसाइकिलें ख़रीदी जा रही हैं. यहां तक कि मुंबई की उस टेक्सटाइल कंपनी का भी पता चला, जो नक्सलियों के लिए वर्दी सप्लाई करती है. रायपुर की एक छापेमारी में पांच करोड़ रुपये की वसूली के दस्तावेज और वर्दी का पूरा ब्यौरा मिला था. नक्सलियों की छह कंपनियों के लिए वर्दी की सप्लाई आनी थी. ख़ुफ़िया एजेंसियों ने ये सारी जानकारियां केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मुहैया कराईं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

अब एक और विडंबना देखिए, गृह मंत्रालय के दस्तावेज ही यह बताते हैं कि नक्सलियों की आय मोटे तौर पर 14 सौ करोड़ रुपये से कम नहीं है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कुछ ही दिनों पहले आधिकारिक तौर पर कहा था कि यह राशि हज़ार से 12 सौ करोड़ रुपये है. पुलिस इसे दो हज़ार करोड़ रुपये बताती है. बता सब रहे हैं, पर कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं कर रहे. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सातवीं रिपोर्ट में सभी राज्य सरकारों और राज्य पुलिस से नक्सली संगठनों के इस वसूली और काला धन सफेद करने के धंधे पर कारगर तरीक़े से अंकुश लगाने के लिए अलग से विशेष प्रकोष्ठ बनाने की सिफ़ारिश की गई थी. दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह सिफ़ारिश फरवरी 2008 में ही की, लेकिन राज्य सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और न केंद्र सरकार ने कोई तवज्जो दी. केंद्र ने राज्य सरकारों से नक्सली संगठनों द्वारा अवैध खनन रोकने के कारगर उपाय करने को कहा था, लेकिन ज़मीनी वास्तविकता क्या है, यह केंद्र सरकार भी जानती है.

नक्सली नेताओं की आलीशान ज़िंदगी भी भारी धन की आमद को उजागर करती है. झारखंड के बुंडू इलाक़े में पकड़ा गया एक नक्सली कमांडर रीबॉक के जूते, ब्रांडेड शर्ट और हाई स्टैंडर्ड मोबाइल फोन से लैस था. रीजनल कमांडर कुंदन पठान ने मई 2008 में बैंक से लूटे गए चार लाख रुपये में से केवल एक लाख रुपये सेंट्रल कमेटी को लौटाए थे. बाक़ी धन उसने हथियार एवं मोबाइल ख़रीदने और होटलबाज़ी में उड़ा दिया. हर 30 नक्सलियों पर 20 के क़रीब अच्छी मोटरसाइकिलें होती हैं. ख़ुफ़िया सूत्रों का यह भी कहना है कि नक्सली लीडर कई राज्यों में उद्योग–धंधों में भी पैसा निवेश कर रहे हैं. 2009 में माओवादी पॉलित ब्यूरो के सदस्य अमिताभ बागची की गिरफ़्तारी के बाद इसका खुलासा हुआ था. उसके पास से बंगाल की कुछ औद्योगिक इकाइयों में 20 करोड़ रुपये के निवेश के दस्तावेज भी बरामद हुए थे. बंगाल चैप्टर के सचिव सोमेन ने भी गिरफ़्तारी के बाद यह खुलासा किया था कि बंगाल में निवेश की राशि एक अरब रुपये से कम नहीं है.

prabhatranjandeen@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 2 अंक 20
दिल्ली, 26 जुलाई –1अगस्त 2010

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के –2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–4783999/11–23418962
विज्ञापन + 91 9899815169
प्रसार + 91 9868013165
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16 (+4)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

नक्सल फंडिंग चैनल (झारखंड)

जिलाः रांची

1. अनवर अंसारी- ठेकेदार 30,000/=
2. बिहारी महतो- क्रशर मालिक 60,000/=
3. अशोक कुमार साह- व्यापारी 30,000/=
4. हदीस अंसारी- व्यापारी 30,000/=
5. रामपति करमाली- व्यापारी 25,000/=
6. कालीचरण सिंह- ठेकेदार 25,000/=
7. एकेटी कंपनी-मेसर्स बरियार सिंह ट्रांसपोर्टर
8. टीटीसी कंपनी-मेसर्स लक्ष्मण रिकवारी ट्रांसपोर्टर
9. एसीए कंपनी-मेसर्स आलोक रूंगटा ट्रांसपोर्टर
10. सीटीसी कंपनी ट्रांसपोर्टर
11. मोबेट कंपनी ट्रांसपोर्टर
12. मोदी कंपनी-मेसर्स कमल अग्रवाल ट्रांसपोर्टर
13. अशोक सिंह, बछरा वेयरहाउस (डिपो मालिक)
14. गोपाल सिंह, केडी वेयरहाउस (डिपो मालिक)
15. मुन्ना सिंह, आरा वेयरहाउस (डिपो मालिक)
16. मिथिलेश सिंह, कोरकाटा वेयरहाउस (डिपो मालिक)
17. कामाख्या सिंह, केडी वेयरहाउस (डिपो मालिक)
18. संजय शर्मा, केडी वेयरहाउस (डिपो मालिक)
19. भोला सिंह, केडी वेयरहाउस (डिपो मालिक)
20. राजू शर्मा, बाजार टांड वेयरहाउस (डिपो मालिक)
21. विनोद सिंह, बाजार टांड वेयरहाउस (डिपो मालिक)
22. खान साहेब वेयरहाउस (डिपो मालिक)
23. आनंद अग्रवाल, बाजार टांड वेयरहाउस (डिपो मालिक)
24. संतोष अग्रवाल, बाजार टांड वेयरहाउस (डिपो मालिक)

(7–24) 50,00,000/=

25. वकील सिंह टिंबर मर्चेंट -24,000/=
26. सुभाष साहू गेहूं के थोक व्यापारी -36,000/=
27. अजित साह गेहूं के थोक व्यापारी - 36,000/=
28. अनिल कुमार भगत सिनेमा हॉल मालिक - 12,000/=
29. शेखर साहू (कॉलेज रोड बुंडू) गेहूं के थोक व्यापारी -36,000/=
30. अजय दत्ता (बुंडू) सिनेमा हॉल मालिक -12,000/=
31. शत्रुघ्न महतो होटल मालिक - 12,000/=
32. कैलाश जायसवाल होटल मालिक - 12,000/=
33. भाटा भगत सोनाहातू गेहूं के थोक व्यापारी - 36,000/=
34. बिपिन कुमार जमुदाग खाद व्यापारी - 36,000/=
35. मथुरा साह व्यापारी - 36,000/=
36. कामता सिंह बुंडू लकड़ी व्यापारी - 30,000/=
37. ठेकेदार (बुंडू बाजार) 60,000/=
38. अजय सरावगी (खूंटी) व्यापारी - 36,000/=
39. रोशन लाल शर्मा लाह व्यापारी - 36,000/=
40. सवारा सेठ नील फैक्ट्री चक्रधरपुर - 36,000/=
41. जैबुर रहमान लकड़ी तस्कर - 10, 8000/=
42. छोटू खान लकड़ी तस्कर - 10, 8000/=
43. मनोज चौधरी लकड़ी तस्कर - 10, 8000/=
44. श्याम मुंडा लकड़ी तस्कर (मुरहू) - 10,8000/=
45. आफताब (मुरहू) लकड़ी तस्कर - 10,8000/=
46. बुधिया साहू लकड़ी तस्कर - 10,8000/=
47. अनूप शाह लकड़ी तस्कर - 10, 8000/=
48 राशन डीलर 14,4000/=

जिलाः गुमला

1. प्रभु शाह-बिशुनपुर ठेकेदार - 100,000/=
2. हरदयाल सिंह-बिशुनपुर ठेकेदार - 100,000/=
3. दिनेश्वर साह ठेकेदार - 100,000/=
4. महेश साह ठेकेदार - 100,000/=
5. रवींद्र साह ठेकेदार - 100,000/=
6. आजाद साहू चिमनी भट्ठा - 100,000/=
7. नाथेश्वर साहू चिमनी भट्ठा - 100,000/=
8. महावीर यादव ठेकेदार - 100,000/=
9. शत्रुघ्न नायक ठेकेदार - 100,000/=
10. भारत नायक एजेंट - 100,000/=
11. रतनलाल सिंह ठेकेदार - 100,000/=
12. कृष्णा सिंह ठेकेदार एवं लाइन होटल के मालिक - 50,000/=
13. बबलू सिंह ठेकेदार - 50,000/=
14. कृष्णा साहू कपड़ा व्यापारी - 25,000/=
15. अशोक ओरांव व्यापारी - 1, 00,000/=
16. प्रभु साव डीलर - 25,000/=
17. रवींद्र सिंह ठेकेदार - 50,000/=
18. रामसेवक साहू डीलर - 50,000/=
19. चुन्नू सिंह ठेकेदार - 50,000/=
20. हृदयपाल साहू ठेकेदार - 50,000/=
21. संदीप सिंह व्यापारी - 25,000/=

जिलाः पलामू

1. लवकुश सिंह, हुसैनाबाद 5,000/=
2. सत्येंद्र सिंह, हुसैनाबाद 5,000/=
3. अल्लू मियां, हुसैनाबाद 5,000/=
4. अभिमन्यु अग्रवाल, हुसैनाबाद 5,000/=
5. लक्ष्मण सिंह, हुसैनाबाद 5,000/=
6. पप्पू अग्रवाल, हुसैनाबाद 5,000/=
7. अजय सिंह, हुसैनाबाद 5,000/=
8. अमिय सिंह, हुसैनाबाद 5,000/=
9. मनोज सिंह, हुसैनाबाद 5,000/=
10. भीष्म नारायण सिंह, हुसैनाबाद 5,000/=
11. ज्ञानचंद पांडेय, डाल्टेनगंज 2,00,000/=
12. संजय सहाय, डाल्टेनगंज 1,00,000/=
13. शंभू साह, छतरपुर ठेकेदार - 1,00,000/=
14. भृगु सिंह, गढ़वा 50,000/=
15. जलाल मियां, हरिहरगंज 50,000/=
16. कृष्णा सिंह, डाल्टेनगंज 1, 00,000/=
17. टिंकू सिंह, मोहम्मदगंज 1,00,000/=
18. सुरेश यादव, गढ़वा ठेकेदार -1,00,000/=
19. राजेंद्र ओरांव, पाटन 10,000/=
20. बुद्धदेव प्रजापति, पाटन 15,000/=
21. अर्जुन राम, पाटन 12,000/=
22. राजेश्वर अमीन, पाटन 8,000/=
23. देवकुमार यादव, पंचफेरिया 10,000/=
24. उपेंद्र यादव, पाटन 16,000/=
25. विनोद मांझी, दुआमा 9,000/=
26. गोपाल साव, पाटन 20,000/=
27. सत्यनारायण पांडेय, लेस्लीगंज 1,00,000/=
28. विनोद पांडेय, लेस्लीगंज 10,000/=
29. प्रमोद सिंह, लेस्लीगंज ठेकेदार - 20,00,000/=
30. मणि सिंह, लेस्लीगंज 1, 00,000/=
31. बुधू सिंह, लेस्लीगंज 1, 00,000/=
32. अजय सिंह, लेस्लीगंज 10, 00,000/=
33. संतू सिंह, डाल्टेनगंज 10,000/=
34. शिव सिंह, लेस्लीगंज 10,000/=
35. सुरेंद्र सिंह, लेस्लीगंज 10,000/=
36. शेखर कंस्ट्रक्शन, पनकी (मैनेजर नरेश शर्मा के जरिए) 10,00,000/=
37. कलावती कंस्ट्रक्शन, पनकी (मैनेजर झाजी के जरिए) 1,00,000/=
38. अनूप साव, पनकी 50,000/=
39. अवधेश साव, पनकी 30,000/=
40. राजो सिंह, पनकी 20,000/=
41. कामाख्या सिंह, पनकी 20,000/=
42. लीलावर यादव, केकरगढ़ 20,000/=
43. मुमताज खान, मनातू 20,000/=
44. बिरला बॉक्साइट कंपनी 80, 00,000/=
45. पंचम सिंह ठेकेदार - 5,00,000/=
46. पाटिल कंस्ट्रक्शन, गढ़वा 68,00,000/=
47. टुनटुन साव, लातेहार 2, 00,000/=
48. अली अहमद, लातेहार बीड़ी पत्ता व्यापारी - 5, 00,000/=
49. फिरोज मियां, चंदवा लातेहार 2, 00,000/=
50. महेंद्र साव ठेकेदार - 1, 00,000/=
51. तेतरिया माइन्स, बालूमठ लातेहार (वेइंग ब्रिज मालिक) - 2,00,000/=
52. कृष्णा सिंह, बालूमठ लातेहार 50,000/=
53. अरविंद सिंह, लेस्लीगंज ठेकेदार - 1, 00,000/=

जिलाः लातेहार

1. चरित्तर यादव व्यापारी, लातेहार -20,000/=
2. सुखदेव यादव व्यापारी, बालूमठ-20,000/=
3. राजेश यादव व्यापारी, बालूमठ-25,000/=
4. लालू यादव व्यापारी, बालूमठ-15,000/=
5. टुनटुन साव व्यापारी, गारू 10,000/=
6. शकील अंसारी व्यापारी, मनिका- 20,000/=
7. मनोज जायसवाल व्यापारी, महुआटांड - 10,000/=
8. अरुण जायसवाल व्यापारी, महुआटांड - 5,000/=
9. मुनेश्वर सिंह व्यापारी, महुआटांड - 10,000/=
10. सतीश प्रसाद व्यापारी, महुआटांड - 5,000/=
11. बिहारी जायसवाल व्यापारी, महुआटांड - 5,000/=
12. शिवनारायण सिंह व्यापारी, महुआटांड - 5,000/=
13. छेदी उर्फ अमजद व्यापारी, महुआटांड - 5,000/=
14. धनेश्वर घासी व्यापारी, महुआटांड -5,000/=
15. जाकिर मियां व्यापारी, महुआटांड - 20,000/=
16. यमुना प्रसाद व्यापारी,महुआटांड - 15,000/=
17. नौशाद मियां व्यापारी, सरयू - 20,000/=
18. दिनेश साव व्यापारी, गारू - 15,000/=
19. अजय शर्मा व्यापारी, लातेहार - 10,000/=
20. अनिल सिंह ठेकेदार, बरवाडीह - 1,00,000/=
21. अजय कुमार मल्होत्रा उर्फ बिट्टू सिंह ठेकेदार, बरवाडीह - 1,00,000/=
22. राजू साव व्यापारी, बरवाडीह - 12,000/=
23. उमेश राम व्यापारी, बरवाडीह- 10,000/=
24. विनय साव व्यापारी, गारू - 10,000/=
25. सुनील सिंह व्यापारी, गारू - 10,000/=
26. अली मोहम्मद बीड़ी पत्ता ठेकेदार, लातेहार - 2, 00,000/=
27. फिरोज मियां बीड़ी पत्ता ठेकेदार, चंदवा - 1, 50,000/=
28. सत्यदेव प्रसाद ठेकेदार, चंदवा - 1,00,000/=
29. मंटू साव व्यापारी, चंदवा- 1,00,000/=
30. महेंद्र साव ठेकेदार, सुरीडीह - 1,00,000/=
31. जयराम सिंह व्यापारी, बरवाडीह- 50,000/=
32. मदन साव व्यापारी, मोखाई- 10,000/=
33. निजाम मियां व्यापारी, कुचिला- 10,000/=
34. बदरी साह व्यापारी, लातेहार- 10,000/=
35. प्रदीप जायसवाल व्यापारी, बरवाडीह
36. संजय जायसवाल व्यापारी, लातेहार
37. अमरनाथ व्यापारी, बरवाडीह
38. आनंद सिंह व्यापारी, लातेहार
39. प्रमोद साह व्यापारी, लातेहार
40. संजय साह व्यापारी, बालूमठ
41 जमाल मियां व्यापारी, महुआटांड

(35–41) 1,00,000/=

जिलाः गढ़वा

1. मेसर्स जैन एंड कंपनी, भवनाथपुर (मैनेजर एससी बनर्जी के जरिए) 3,00,000/=
2. मेसर्स आईएसएस कंपनी, भवनाथपुर (मैनेजर रोशनलाल के जरिए) 3,00,000/=
3. मेसर्स आरएसएस कंपनी, भवनाथपुर (मैनेजर सुमन जी के जरिए) 3,00,000/=
4. मेसर्स पीसीसी कंपनी, भवनाथपुर (मैनेजर शिवपूजन यादव के जरिए) 3,00,000/=
5. मेसर्स गुप्ता कंपनी, भवनाथपुर (मैनेजर मुकुल जी के जरिए) 3,00,000/=
6. उदय दुबे, व्यापारी भवनाथपुर 3,00,000/=
7. राजेंद्र प्रताप देव, भवनाथपुर 3,00,000/=
8. उमेश यादव, बूका 3,000/=
9. अरविंद पासवान 30,000/=
10. विजय पांडेय 30,000/=
11. आनंदी सिंह 30,000/=
12. श्यामलाल पासवान 30,000/=
13. डॉ. आले रसूल खान, मझिआंव 30,000/=
14. मो. शकील खान, सोनपुरवा 30,000/=
15. शकील खान, ठेकेदार धुरवा 30,000/=
16. अनिल कमलापुरी, डीलर मझिआंव 40,000/=
17. विजय साह, व्यापारी मझिआंव 25,000/=
18. प्रसाद किराना स्टोर, मझिआंव बाजार 20,000/=
19. संत कुमार सिंह, मझिआंव 30,000/=
20. ददन सिंह, क्रशर मालिक 40,000/=
21. शाही भूषण सोनी, व्यापारी मझिआंव 30,000/=
22. बलराम मेहता, डीलर गहिरी 20,000/=
23. महेंद्र शुक्ला, गढ़वा 25,000/=
24. श्यामचंद्र पांडेय, बीड़ी पत्ता व्यापारी 30,000/=
25. तिवारी, ठेकेदार गिसगी 30,000/=
26. तन्नू उर्फ भोला सिंह, देवदर 25,000/=
27. संजय सिंह, नगरउंतारी 20,000/=
28. महेंद्र साव, भवनाथपुर ठेकेदार -25,000/=
29. भुनेश यादव, जपला ठेकेदार - 40,000/=
30. अमृत शुक्ला ठेकेदार- 45,000/=
31. बुल्लू पांडेय, पिपराडीह ठेकेदार - 40,000/=
32. कृष्णा यादव बीड़ी पत्ता ठेकेदार- 20,000/=
33. राजेंद्र यादव, नगरउंतारी 25,000/=
34. ललन तिवारी, नगरउंतारी 20,000/=
35. रिद्धी सिंह बीड़ी पत्ता ठेकेदार गढ़वा - 1,00,000/=
36. ओमप्रकाश केसरी, भंडरिया 40,000/=
37. विनोद केसरी, भंडरिया 20,000/=
38. मल्लू सिन्हा, भंडरिया 25,000/=
39. मदन केसरी, भंडरिया 20,000/=
40. विनय सिंह, नवका 25,000/=
41. राजेश्वर ठाकुर, जोन्हीखंड 20,000/=
42. सचित साव, बिन्डा 30,000/=
43. विनोद सिंह, नमजाहा 50,000/=
44. संजय सिंह, पर्रो 50,000/=
45. जंगी सिंह, बिजका 20,000/=
46. चंद्रिका सिंह, मंजारी 30,000/=
47. अशोक गुप्ता, गोडरमाना 35,000/=
48. अर्जुन ठाकुर, रामानुज 40,000/=
49. गोमल चौरसिया, रामानुज 35,000/=
50. देवेंद्र साव, रामकंडा 55,000/=
51. जोखन सिंह, कसमर 30,000/=
52. राजकिशोर यादव, ललहैया 35,000/=
53. विजय साव, उदयपुर 30,000/=
54. कल्लू पांडेय, परसर 20,000/=
55. समित अंसारी, परसर 25,000/=
56. विनोद साव, तेतरियाडीह 35,000/=
57. भिखारी पांडेय, उदयपुर 30,000/=
58. रंजन चौबे, गढ़वा 35,000/=
59. अनूप तुलस्यान, डाल्टेनगंज 25,000/=
60. विजय पांडेय, डाल्टेनगंज 30,000/=
61. रंजीत, चैनपुर, डाल्टेनगंज 35,000/=
62. दिलीप चंद्रवंशी, चैनपुर, डाल्टेनगंज 30,000/=
63. मनोज साव, चैनपुर, डाल्टेनगंज 35,000/=
64. नरेश चंद्रवंशी, बीड़ी पत्ता ठेकेदार, डाल्टेनगंज 40,000/=
65. मणि प्रसाद, बीड़ी पत्ता ठेकेदार, डाल्टेनगंज 45,000/=
66. देवेंद्र प्रसाद, बीड़ी पत्ता ठेकेदार, डाल्टेनगंज 40,000/=
67. जेबी कंपनी, बीड़ी पत्ता ठेकेदार, डाल्टेनगंज 20,000/=
68. सुबोध प्रसाद, बीड़ी पत्ता ठेकेदार, डाल्टेनगंज 25,000/=
69. गोपाल चौरसिया, बीड़ी पत्ता ठेकेदार, डाल्टेनगंज 30,000/=
70. महेंद्र शुक्ला, रेहला 35,000/=
71. हीरा यादव, रणपुरा 40,000/=

जिलाः हजारीबाग

1. शेरे मोहम्मद बीड़ी पत्ता ठेकेदार - 50,000/=
2. यदुनंदन साह ठेकेदार - 10,00,000/=
3. कृष्णा प्रसाद सिंह ठेकेदार- 8,00,000/=
4. मुकेश पांडेय ठेकेदार- 7,00,000/=
5. गोविंद राणा ठेकेदार- 6,00,000/=
6. कारू साव ठेकेदार- 12,00,000/=
7. शंकर पांडेय 6,00,000/=
8. मूलचंद्र साव ठेकेदार- 9,00,000/=
9. अमित वर्मा ठेकेदार- 7,00,000/=
10. शंभु सिंह ठेकेदार- 60,00,000/=
11. संतोष पांडेय 60,00,000/=
12. अशोक सिंह 50,000/=
13. राजकुमार सिंह 55,000/=
14. अभय सिंह 60,000/=
15. रुस्तम खान 10,000/=
16. त्रिलोकी साह ईंट भट्ठा मालिक- 10,000/=
17. सुधीर कुमार सिंह 10,000/=
18. देवराज सिंह ट्रांसपोर्ट एजेंसी के मालिक- 50,000/=
19. एचसीएल कंपनी बरकटा, हजारीबाग- 20,00,000/=
20. लार्सन एंड टूब्रो चौपारन, हजारीबाग- 1,50,000/=
21. अरुण लाल क्रशर मालिक- 25,000/=
22. सतुन केसरी क्रशर मालिक- 25,000/=
23. जय मां दुर्गा स्टोन वर्क्स चिप्स, धनंजय कुमार सिंह क्रशर मालिक- 10,000/=
24. मेसर्स ज्योति स्टोन वर्क्स, विनोद कुमार मेहता क्रशर मालिक- 10,000/=
25. हजारीबाग स्टोन चिप्स 10,000/=
26. बहाब मियां, चौपारन, हजारीबाग 2, 00,000/=
27. अख्तर मियां, बीड़ी पत्ता ठेकेदार, चौपारन 2, 00,000/=
28. विनोद सिंह, बीड़ी पत्ता ठेकेदार, चौपारन 10,000/=
29. कार्तिक सिंह, बीड़ी पत्ता ठेकेदार, चौपारन 10,000/=
30. अनवारुल हक, बीड़ी पत्ता ठेकेदार, चौपारन 10,000/=
31. मुमताज खान, सदर बीड़ी पत्ता ठेकेदार- 12,000/=
32. न्यू गवर्नमेंट बीड़ी पत्ता कंपनी, बाबूजी कमाल खान 4, 00,000/=
33. दिलीप कुमार जैन, सदर 30,000/=
34. वंशी सिंह, हजारीबाग 10,000/=
35. रतिनंदन सिंह, हजारीबाग 7,000/=
36. रामनंदन सिंह, हजारीबाग 5,000/=
37. अनिल कुमार जैन, सदर 30,000/=
38. नागो यादव, चौपारन 5,000/=
39. श्रीराम यादव, चौपारन 5,000/=

जिलाः रामगढ़

1. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, (कुमार महेश सिंह के जरिए) 1,00,000/=
2. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, (रमेश जैन के जरिए) 2,00,000/=
3. डीके स्टोन, बीएन सिंह 10,000/=
4. संत कुमार वसल, स्टोन व्यापारी 10,000/=
5. आरपीएल रूंगटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, रामगढ़ 50,000/=
6. बाबू लाल गुप्ता 50,000/=
7. शंकर ट्रांसपोर्ट कंपनी 50,000/=
8. सीटी चनाली ट्रांसपोर्ट के मालिक, उमेश मोदी 30,000/=
9. सेंट्रल कोल फील्ड्स, वसंत वाशरी, वेस्ट बोकारो, रामगढ़ 50,000/=
10. मैनेजर, सेंट्रल कोल फील्ड्स, रामगढ़ 50,000/=

जिलाः चतरा

1. बौबी राम ठेकेदार - 50,000/=
2. उदय गुप्ता ठेकेदार - 50,000/=
3. मुन्ना भारद्वाज ठेकेदार - 1, 00,000/=
4. सलीम गोल्डन ठेकेदार - 50,000/=
5. विमल गोप ठेकेदार - 20,000/=
6. बादो यादव ठेकेदार - 20,000/=
7. प्रमोद जायसवाल ठेकेदार - 20,000/=
8. आशीष जायसवाल ठेकेदार - 20,000/=
9. मुन्ना मियां ठेकेदार - 20,000/=
10. मोनू जैन बीड़ी पत्ता ठेकेदार - 50,000/=
11. सुल्तान मियां बीड़ी पत्ता ठेकेदार - 50,000/=
12. चक्रहेश सिंह कोयला व्यापारी- 30,000/=
13. राम नारायण सिंह कोयला व्यापारी- 20,000/=
14. सलीम मल्लिक कोयला व्यापारी - 10,000/=
15. रऊफ मियां कोयला व्यापारी - 10,000/=
16. विजय निषाद कोयला व्यापारी - 10,000/=
17. जगदीश साव कोयला व्यापारी - 5,000/=
18. संजय साव कोयला व्यापारी - 5,000/=
19. विवेक सिंह क्रशर मालिक - 20,000/=
20. बच्चू सिंह क्रशर मालिक - 20,000/=
21. यमुना बस मालिक - 25,000/=
22. लार्सन एंड टूब्रो पिपरवार चतरा- 5,00,000/=

जिलाः गिरीडीह

1. शिवम रोलिंग मिल 5,00,000/=
2. बाल मुकुंद रोलिंग मिल 5,00,000/=
3. अतिवीर रोलिंग मिल 5,00,000/=
4. मोंगिया रोलिंग मिल 5,00,000/=
5. लाल स्टील रोलिंग मिल 5,00,000/=
6. श्रीराम रोलिंग मिल 5,00,000/=
7. विश्वनाथ फेरो 1,00,000/=
8. संत कुरिया आयरन स्पंज 10,00,000/=
9. लालसर आयरन स्टील 10,00,000/=
10. गौरीशंकर रोलिंग मिल 1,00,000/=
11. सतनाम रोलिंग मिल 1,00,000/=
12. भारद्वाज रोलिंग मिल 1,00,000/=
13. भोला मोदी, तिसारी 50,000/=
14. राजन अग्रवाल, भूमाफिया, तिसारी 50,000/=
15. बबलू गोयल, क्रशर मालिक, तिसारी 1,00,000/=
16. इब्राहीम अंसारी- डीलर- तिसारी 50,000/=
17. रतनलाल अग्रवाल, सरिया बाजार व्यापारी - 1,00,000/=
18. महेंद्र अग्रवाल, सरिया बाजार व्यापारी - 50,000/=
19. भोला जैन, सरिया बाजार क्रशर मालिक- 40,000/=
20. गोपी मोदी, सरिया बाजार व्यापारी - 3,50,000/=
21. चंद्रशेखर, जयनगर क्रशर मालिक- 5,00,000/=
22. छोटेलाल बिहारीलाल, बगोदर कंस्ट्रक्शन कंपनी- 5,00,000/=
23. श्याम किशोर सिंह, ब्लॉक सर्किल अफसर, पीरटांड प्रखंड 2,00,000/=
24. मनोज चौधरी ठेकेदार- 1,00,000/=
25. धार्मिक ट्रांसपोर्ट, मधुबन 20,000/=
26. जैन धार्मिक ट्रस्ट, राजेंद्र जैन, मधुबन 5,00,000/=
27. एनआर कंसट्रक्शन 9,00,000/=
28. महेश जैन 2,00,000/=
29. श्वेतांबर (छकनलाल मैनेजर के जरिए) 50,000/=
30. श्वेतांबर (अनिल दूगड़ मैनेजर के जरिए) 50,000/=
31. विषपंथी दिगंबर, मधुबन (मनोहर जैन मैनेजर के जरिए) 1,00,000/=
32. ध्रुव कुमार बस मालिक- 30,000/=
33. रंजीत कुमार
34. मनोज कुमार
35. विक्रम मांझी
36. गोकुल साव
37. मनोज साव

(33–37) 5,00,000/=

38. छोटन यादव, बगोदर ठेकेदार- 80,000/=
39. प्रदीप सिंह 55,000/=
40. बिहारीलाल मंडल 50,000/=
41. छोटेलाल चौधरी ठेकेदार - 40,000/=
42. शत्रुघ्न मंडल ठेकेदार - 36,000/=
43. पीसीएल कंपनी बगोदर- 50,000/=
44. अटका बाजार और मुंडारो की जनता 25,000/=
45. अवैध कोयला डीलर कमीशन
46. ब्रिज कलवर्ट के टेंडर में 5 प्रतिशत कमीशन
47. रोड कंसट्रक्शन में 10 प्रतिशत कमीशन
48. पिच रोड कंसट्रक्शन में 30 प्रतिशत कमीशन
49. फिशरीज़ में 25 प्रतिशत कमीशन
50. कोऑपरेटिव बिल्डिंग कंसट्रक्शन में 12 प्रतिशत कमीशन
51. पीसीएल कंपनी (प्रति माह 15,000/=)
52. अनूप सिंह
53. विजय चौधरी
54. कामेश्वर मंडल
55. मनोज सिंह
56. रामेश्वर यादव

(45–56) 13,00,000/=

जिलाः कोडरमा

1. शंकर गोपाली बीड़ी पत्ता ठेकेदार- 30,000/=
2. जलील मियां बीड़ी पत्ता ठेकेदार- 20,000/=
3. सुबई सिंह ईंट भट्ठा मालिक- 20,000/=
4. अर्जुन प्रसाद ईंट भट्ठा मालिक - 20,000/=
5. सुरेश झौजगेरी खदान मालिक - 30,000/=

जिलाः चाईबासा

1. उषा मार्टिन, (मैनेजर समीर दहिया के जरिए) 7,00,000/=
2. क्रशर मालिक समूह, नोआमुंडी 48,00,000/=
3. ओआरएस इंडिया 12,00,000/=
4. रूंगटा माइंस 25,00,000/=
5. उषा मार्टिन, घाटकुरी 25,00,000/=
6. विनय पंसारी 35,00,000/=
7. रूंगटा माइंस, घाटकुरी 25,00,000/=
8. शाह ब्रदर्स, कर्मपद 25,00,000/=
9. बालजोरी कंपनी चंद्रप्रकाश 5,00,000/=
10. डंपर मालिकों का समूह 40,00,000/=
11. कोलकाता के बीड़ी पत्ता ठेकेदार 1,00,000/=
12. चतरा के ठेकेदार 90,000/=
13. दिनेश कुल्लू तिरिया, सिमडेगा 1,50,000/=
14. दिनेश साव 90,000/=
15. ठकुरानी ओर माइंस 15,00,000/=
16. शिवानी स्टील 8,00,000/=
17. श्याम मिनरल्स 3,00,000/=
18. स्वाती इंटरनेशनल 6,00,000/=
19. टोरियन आयरन स्टील 25,00,000/=
20. जय दुर्गा मिनरल्स 6,00,000/=
21. साई इंटरप्राइजेज 5,00,000/=
22. त्रिवेणी मिनरल्स 4,00,000/=
23. शिवशक्ति मिनरल्स 3,00,000/=
24. दुर्गा मिनरल्स 10,00,000/=
25. बालाजी मिनरल्स 5,00,000/=
26. शारदा क्रशिंग 20,00,000/=
27. लेहर्स एक्सपोर्ट्स एंड सर्विस 15,00,000/=
28. पद्म कुमार जैन माइन्स 30,00,000/=
29. अनिल कुमार निर्मल कुमार, घाटकुरी 25,00,000/=
30. शारदा पेटी वर्क्स 15,00,000/=

जिलाः जमशेदपुर

1. एचपी विश्वास एंड कंपनी 2,00,000/=
2. मेसर्स शहजादी प्राइवेट लिमिटेड 5,00,000/=
3. अरुण सिंह ठेकेदार- 5,00,000/=
4. कृष्णा साव, गुरबंदा 1,00,000/=
5. अंकित कंसट्रक्शन 5,00,000/=
6. हिमाचल कंसट्रक्शन 2,00,000/=
7. वैष्णवी कंसट्रक्शन 7,00,000/=
8. आरके बिल्डर्स रांची 5,00,000/=
9. अवधेश कंसट्रक्शन 3,00,000/=
10. हिमाचल कंसट्रक्शन रांची 3,00,000/=
11. अजय इंजीकॉम बिहार 4,00,000/=
12. विश्वास एंड कंपनी रांची 5,00,000/=
13. प्रधान कंसट्रक्शन रांची 3,00,000/=
14. कमला कंसट्रक्शन बोकारो 3,00,000/=
15. झारखंड लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन 3,00,000/=

जिलाः सरायकेला

1. मंटू सिंह, चाकोलिया क्रशर मालिक- 5,000/=
2. मुन्ना, चाकोलिया क्रशर मालिक- 5,000/=
3. पोतल महतो 5,000/=
4. कुणाल सिंह 5,000/=
5. दयाल महतो 5,000/=
6. गणेश गोरिया 5,000/=
7. अजीज हसनैन 25,000/=
8. दीपक गोप 5,000/=
9. रोहणी महतो 5,000/=
10. विजय पांडेय 5,000/=
11. अफरीद खान 5,000/=
12. सुधीर गोरई 10,000/=
13. भादोडीह पेट्रोल पंप 5,000/=
14. पाता पेट्रोल पंप 5,000/=
15. भुइयांडीह पेट्रोल पंप 5,000/=
16. कंदर बेरा-02 पेट्रोल पंप 10,000/=
17. आसनबनी-04 पेट्रोल पंप 20,000/=
18. हिल व्यू पेट्रोल पंप 5,000/=
19. टेंथ माइल स्टोन होटल 30,000/=
20. सिल्वर क्रेस्ट होटल 25,000/=
21. हिल व्यू होटल 25,000/=
22. कार्तिक महतो व्यापारी - 3,00,000/=
23. प्रवीण सिंह, एनएच-32 ठेकेदार- 7,00,000/=
24. ठेकेदार एनएच-33 7,00,000/=
25. चांडिल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड 30,000/=
26. जय मंगला स्पंज आयरन 30,000/=
27. सिद्धि विनायक लिमिटेड 30,000/=
28. केवल मेटालिक लिमिटेड 30,000/=
29. कोहीनूर स्टील 30,000/=
30. जेएमटी ऑटो लिमिटेड 30,000/=
31. साइज़र मेटैलिक लिमिटेड 30,000/=
32. एसएसआर आयरन स्टील लिमिटेड 30,000/=
33. शिवराम स्पंज आयरन लिमिटेड 30,000/=
34. ओम दयाल आयरन स्टील कंपनी 30,000/=
35. झारखंड स्पंज आयरन लिमिटेड 30,000/=
36. श्रीओम मेटल लिमिटेड 30,000/=
37. जेएसएस एशिया कंपनी लिमिटेड 30,000/=
38. डिवाइन एलाएंस पावर कंपनी लिमिटेड 30,000/=
39. मेसर्स जूही लिमिटेड 30,000/=
40 मेसर्स नरसिंह इस्पात लिमिटेड 30,000/=
41. पसारी स्टील प्राइवेट लिमिटेड 30,000/=
42. इग्नाइट स्टील लिमिटेड 30,000/=
43. शुभ स्टील लिमिटेड 30,000/=

जिलाः बोकारो

1. बोकारो ब्लॉक ऑफिस के विकास कार्यों में 5 प्रतिशत कमीशन 5,00,000/=
2. आरके पांडेय एंड कंपनी 50,000/=
3. अजय सिंह एंड कंपनी 25,000/=
4. जुगनू एंड कंपनी 20,000/=
5. बीकेबी एंड कंपनी 50,000/=
6. सर्वेश्वरी कंपनी, विनोद सिंह एंड प्यारी सिंह 20,000/=
7. एबी सिंह एंड कंपनी, बृजनंदन सिंह एंड बीजन सिंह 20,000/=
8. नवीन ट्रांसपोर्ट कंपनी, गोपालजी सिंह 20,000/=
9. जेपीसी कंपनी, जगदीश बर्नवाल 20,000/=
10. ललन प्रसाद सिंह एंड कंपनी 20,000/=
11. बोकारो एवं करगलि क्षेत्र की सभी वेइंग ब्रिज 5,00,000/=
12. धोरी क्षेत्र की सभी वेइंग ब्रिज 5,00,000/=
13. दामोदर वैली कॉरपोरेशन, कोल एरिया 5,00,000/=
14. तारकेश्वर महतो, बोकारो थर्मल के ठेकेदार 4,00,000/=
15. तारकेश्वर महतो ठेकेदार- 50,000/=
16. हेमलाल महतो कोयला डीलर - 50,000/=
17. हुलास महतो कोयला माफिया- 25,000/=
18. प्रकाश महतो 50,000/=
19. दुलारचंद महतो 50,000/=
20. आरपीएल ट्रांसपोर्ट बोकारो 50,000/=
21. जीआरपीएल, तिलकराम मेवर 30,000/=
22. वीरा कोठरिया 20,000/=
23. विनोद कुमार अग्रवाल 30,000/=
24. सिटी ट्रांसपोर्ट, दयानंद मोदी 20,000/=
25. बीके जैन ठेकेदार टीटीपीएस- 25,000/=
26. इखलाक अहमद ठेकेदार टीटीपीएस- 25,000/=
27. जावेद इकराम ठेकेदार टीटीपीएस- 15,000/=
28. एबीवी, रिजवानुल्लाह ठेकेदार बोकारो- 10,000/=
29. केके जैन ठेकेदार टीटीपीएस- 10,000/=
30. पीके जैन ठेकेदार टीटीपीएस- 10,000/=
31. दिलीप कुमार जैन 10,000/=
32. शमशुल हक टीटीपीएस ठेकेदार-10,000/=
33. केजे खान ठेकेदार- 15,000/=
34. सीताराम राम एलकेके ट्रक्स- 15,000/=
35. देवनारायण प्रजापति ठेकेदार टीटीपीएस- 10,000/=
36. जीआरपीएल तिलकराम मेवर- 30,000/=
37. पप्पू जैन ठेकेदार टीटीपीएस- 10,000/=
38. एसके सिंह ठेकेदार टीटीपीएस- 10,000/=
39. सूर्या उद्योग धनबाद 10,000/=
40. अजय जैन ठेकेदार- 10,000/=
41. महावीर जैन ठेकेदार- 10,000/=
42. रामजीत साह ठेकेदार- 10,000/=
43. मेसर्स एसएम सिंह पतरातू थर्मल- 10,000/=
44. केके कंसट्रक्शन, लालचंद महतो ठेकेदार- 15,000/=
45. आरडी साहू ठेकेदार- 10,000/=
46. विनोद कुमार गगमेत 10,000/=
47. आलम खान ठेकेदार- 5,000/=
48. सूरजमल सिंह 5,000/=
49. प्रेमचंद साहू ठेकेदार टीटीपीएस- 5,000/=
50. सुनील सिंह कोयला तस्कर एवं क्रशर मालिक- 25,000/=
51. कादिर भाटिया इस्पात तस्कर- 20,000/=
52. भगवती प्रसाद वर्मा 10,000/=
53. महावीर जैन एंड वृद्धिचंद जैन 10,000/=
54. कमल जैन 50,000/=
55. रणविजय सिंह क्रशर मालिक- 10,000/=
56. प्रह्लाद शर्मा क्रशर मालिक- 10,000/=
57. आईईएल के कार्मिक प्रबंधक अशोक कुमार सिंह 50,000/=
58. दिल मोहम्मद मियां 10,000/=
59. इमाल मियां 10,000/=
60. अकबर मियां 10,000/=
61. सदाकत मियां 10,000/=
62. शैलेंद्र सिंह 51,000/=
63. हेमजी रामजी माणिक आईईएल पेट्रोल पंप मालिक- 10,000/=
64. रणजीत सिंह 25,000/=
65. नवल सिंह 25,000/=
66. धीरेंद्र सिंह 25,000/=
67. प्रमोद केसरी 25,000/=
68. जयमंडल सुंडी 25,000/=
69. जगन्नाथ महतो 5,000/=
70. मोहन गंझू 5,000/=
71. कमल भगत
72. बीगन प्रसाद भगत
73. दीनदयाल जायसवाल
74. राम नारायण जायसवाल
75. हरेंद्र प्रसाद जायसवाल
76. सुरेंद्र मुंडा (खाद्यान्न डीलर)

(71–76) 4,00,000/=

77. सोना बस के मालिक 72,000/=
78. प्रसाद बस के मालिक 24,000/=
79. मुक्तेश्वरी बस के मालिक 24,000/=
80. श्रीराम बस के मालिक 12,000/=
81. सुरेश बस 12,000/=
82. प्रदीप जैन 75,000/=
83. इशाक खान ठेकेदार- 75,000/=
84. रंजीत साव ठेकेदार- 75,000/=

जिलाः धनबाद

1. ब्लॉक (प्रखंड) टूंडी 5,00,000/=
2. ब्लॉक (प्रखंड) तोपचांची 5,00,000/=
3. ब्लॉक (प्रखंड) गोविंदपुर 6,00,000/=
4. धनबाद शहर के व्यापारी एवं ठेकेदार 3,00,000/=
5. कोयला, इस्पात एवं स्क्रैप के तस्कर 20,00,000/=
6. एचसीएल रोड कंसट्रक्शन 15,00,000/=
7. मैनेजर राय- निरसा 10,00,000/=

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

आज़ाद के साथ हेमचंद्र की भी हत्या की गई. पहले उन्हें जोनल कमांडर बताया गया, बाद में पता चला कि वह तो पत्रकार थे. इस हत्याकांड की साज़िश किस स्तर पर रची गई.

नक्सलवाद, मीडिया और पुलिस

मीडिया को धमकी

हद में रहो

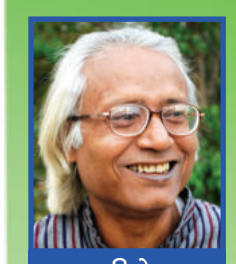

आदियोग

सीपीआई (माओवादी) के प्रवक्ता आज़ाद की मुठभेड़ के नाम पर आंध्र प्रदेश पुलिस द्वारा की गई हत्या के बाद अमन एवं इंसाफ़ के पैरोकार सदमे और गुस्से में हैं. इनमें बहुतेरे माओवादियों के हिंसा के रास्ते पर उंगली भी उठाते रहे हैं, लेकिन उससे पहले सरकारों की जनविरोधी नीतियों और उसके प्रतिरोध के बर्बर दमन को ज़रूर कठघरे में भी खड़ा करते रहे हैं. पुलिस-सुरक्षाबल और माओवादियों के बीच जारी हिंसक भिड़ंत में छत्तीसगढ़ का बस्तर और उसमें भी दंतेवाड़ा ज़िला सबसे नाज़ुक इलाक़ा है. स्वामी अग्निवेश एवं दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं की दंतेवाड़ा यात्रा की ख़बर उन इलाक़ों तक भी पहुंची, जहां मुख्यधारा के तथाकथित मीडिया की पहुंच नहीं है या कहें कि ये इलाक़े उनके हाशिए से बाहर हैं. इस यात्रा ने सबसे ज़्यादा और सबसे पहले प्रभावित आबादी और ख़ासकर बस्तर के आदिवासियों के बीच अमन की आस जगाने का काम किया. हालांकि उन्हें स्वामी अग्निवेश के क़द या उनके काम का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन इतनी जानकारी ज़रूर हो गई कि गेरुआ रंग के लिबास में कोई महान संत इसलिए निकला है कि सरकार और माओवादियों के बीच बातचीत का माहौल बने. सुलह का कोई रास्ता निकले, अमन की बहाली हो और आदिवासियों का चैन लौटे. स्वामी अग्निवेश की कोशिशों में माओवादियों की नुमाइंदगी आज़ाद कर रहे थे और उन्हीं की हत्या ने इस दीये को बुझा देने का काम किया. यह सीधा संदेश दिया कि केंद्र सरकार माओवादियों का सफ़ाया चाहती है, उनके साथ बातचीत नहीं.

आज़ाद के साथ हेमचंद्र की भी हत्या की गई. पहले उन्हें जोनल कमांडर बताया गया, बाद में पता चला कि वह तो पत्रकार थे. इस हत्याकांड की साज़िश किस स्तर पर रची गई. आज़ाद और हेमचंद्र को एक जुलाई की सुबह ग्यारह बजे के आसपास नागपुर में पकड़ा गया और उस रात दस बजे से अगले लगभग चार घंटे के बीच किसी समय मार दिया गया. इस बीच क्या-क्या हुआ, किस तरह हुआ, किसके इशारे पर हुआ? क्या फ़र्ज़ी मुठभेड़ के नाटक का मंचन आंध्र प्रदेश के स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो (एसआईबी) ने अपनी मर्ज़ी से किया? अगर हां, तो इसका मतलब यह निकला कि पुलिस, सुरक्षाबलों या एसआईबी जैसी एजेंसियां बेलगाम हैं और अमन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हैं. अगर नहीं, तो क्या इसकी पटकथा आंध्र प्रदेश सरकार ने तैयार की, जहां सुलह के लिए चल रही बातचीत के बीच माओवादियों का सफ़ाया कर देने का पुराना इतिहास रहा है. या कि इसके लिए केंद्र सरकार की मंज़ूरी या उसका फ़रमान था? इसमें माओवादियों का सफ़ाया करने की सरकारी जंग के सर्वोच्च कमांडर केंद्रीय गृहमंत्री पी चिदंबरम किस भूमिका में थे? आख़िरकार स्वामी अग्निवेश बातचीत का जो पुल बनाने की तैयारी में थे, उसके एक छोर पर अगर आज़ाद थे तो दूसरे छोर पर चिदंबरम.

पत्रकार की ज़िम्मेदारी है कि वह लोगों तक सच को पहुंचाए. सच की तह तक जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ख़बर अगर माल भर है तो उसकी डिलीवरी में देरी नहीं की जा सकती. तब उसका सोच-विचार से क्या लेना-देना? तो किस बात की ईमानदारी, कौन सी प्रतिबद्धता, कहां की संवेदनशीलता और कैसे मूल्य, अगर किसी मीडिया समूह का उत्पाद केवल और केवल लाभ कमाने के लिए है, उपभोक्ताओं को सही सूचना देने के लिए नहीं? जनता को सजग करने का दायित्व निभाना तो बहुत दूर की कौड़ी है. इसीलिए अब पत्रकारिता की दुनिया में ऐसे लोगों की फ़ौज़ और उनकी पूछ बढ़ती जा रही है, जो भले ही पत्रकारिता संस्थानों से निकले हों, लेकिन दिल-दिमाग़ से अंगूठा टेक हैं. लेकिन यह पूरा सच नहीं है. असली सच तो यह है कि मीडिया समूहों में जानने और समझने की आज़ादी की लक्ष्मण रेखाएं पहले से खिंची होती हैं और जिसे लांघना नौकरी से हाथ धो बैठने के हालात पैदा करना होता है. इसकी परिधि मीडिया को संचालित कर रहे कॉरपोरेट समूह के व्यापारिक हितों से तय होती है, सामाजिक हितों से नहीं. पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों उर्फ़ मीडिया के उपभोक्ताओं का अधिकार है कि उन्हें किसी घटना, सवाल या मुद्दे को हर कोण से जांचने-परखने और उसके मुताबिक़ अपनी राय बनाने की सहूलियत मिले. यह तभी मुमकिन है, जब उन्हें सही और पूरी जानकारी मिले. किसी पक्ष या कोण को दबाने या ग़लत तरीक़े या अधूरा रखने से यह मुमकिन नहीं.

फ़िलहाल, लगता यही है कि ज़्यादातर बड़े मीडिया समूह इस सरकारी इशारे को समझ गए हैं कि विकास या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में विस्थापन, जबरिया भूमि अधिग्रहण, उसके प्रतिरोध और उस पर राज्य दमन जैसे सुलगते मामलों में उपभोक्ताओं के अधिकार को सीमित कर दिया जाए और उससे अप्रभावित समुदायों की राय को एकतरफ़ा बना दिया जाए. सरकारों के लिए अपनी कंपनीपरस्ती के नमक का हक़ अदा करने का रास्ता खुले और जन विरोधी विकास का झंडा लहराए. यह तभी मुमकिन है, जब ऑपरेशन ग्रीन हंट को तेज़ किया जाए और उसे आख़िरी मंज़िल तक पहुंचाया जाए यानी आंध्र प्रदेश के मॉडल को दोहराया जाए कि बातचीत का नाटक करो और उसके पीछे माओवादियों का संहार भी जारी रखो. भले ही प्रभावित आबादी का कचूमर निकले और देश की संप्रभुता जाए भाड़ में. जहां अपने नफे-नुक़सान के मुताबिक़ उड़ान भरने वाले मीडिया समूह और मीडियाकर्मी बिकने के लिए क़तार में हों, वहां सेंसरशिप की भला क्या ज़रूरत?

तो भी तमाम सिरफ़िरे मीडियाकर्मी हैं जो मानते ही नहीं. उन्हें हवालात में या जेल भिजवा कर समझाया जाता रहा है और इस मामले में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा है. अब उन्हें समझा दिए जाने की सीधी और खुली धमकी दे दी गई है. इस मामले में भी छत्तीसगढ़ ने पहल की. आज़ाद के साथ हेमचंद्र के मारे जाने के बाद राज्य के पुलिस प्रमुख विश्वरंजन ने रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि हमारे पास माओवादी समर्थक पत्रकारों की सूची है. उन पर ख़ुफ़िया एजेंसियों की नज़र है, पुख्ता सबूत मिलते ही उन पर कार्रवाई की जाएगी. किसी मीडियाकर्मी को जंगल में जाने और माओवादी नेताओं का साक्षात्कार लेने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन माओवादियों के ख़िलाफ़ सुरक्षाबलों द्वारा जारी कार्रवाइयों के दौरान उनका जंगल में जाना निश्चित रूप से ख़तरनाक हो सकता है. तो भी जो इस दौरान जंगल में घुसने का जोखिम उठाते हैं और मारे जाते हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता. मतलब कि हेमचंद्र ने जंगल जाने और माओवादियों से मिलने का जोखिम उठाया और इसका ख़ामियाजा भुगता. जो भी यह हिमाकत करेगा, मारा जाएगा.

विश्वरंजन की धमकी पुलिस को बेझिझक आगे बढ़ो का फ़रमान थी. इसके एक सप्ताह के भीतर ही दंतेवाड़ा ज़िले के एसएसपी एसआरपी कुलकर्णी ने यह सनसनीखेज़ ख़ुलासा कर दिया कि छह जुलाई को कांग्रेसी कार्यकर्ता कम ठेकेदार के मकान पर हुए हमले की साज़िश रचने वाले की शिनाख्त कर ली गई है और वह समेली गांव का वाशिंदा लिंगाराम कोडापी है. उसने बाक़ायदा आतंकवादी कार्रवाइयों का प्रशिक्षण लिया है. लिंगाराम अरुंधति राय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर नंदिनी सुंदर के संपर्क में था. आज़ाद को ढेर किए जाने से पहले उसमें जोश भरा गया था कि वह आज़ाद की जगह लेने की क्षमता रखता है. हैरानी की बात यह कि अपना नाम लिए जाने के बावजूद लिंगाराम भूमिगत नहीं हुए. वह मीडिया के सामने पहुंचे और आंसू भरी आंखों से इस इल्ज़ाम को झूठा और ख़ुद को बेगुनाह बताया. उन अनुभवों को सामने रखा जब पिछले सितंबर में अपने गांव से पुलिस ने उन्हें उठाया था और 40 दिनों तक हिरासत में रखा था. बाद में लोगों की पहल पर बिलासपुर उच्च न्यायालय से ही उन्हें रिहाई मिली. ख़ौफ़ इस क़दर था कि अदालत के सामने अपनी ग़ैर क़ानूनी हिरासत पर उन्होंने ज़ुबान बंद रखने में ही भलाई समझी और रिहा होते ही उन्होंने छत्तीसगढ़ भी छोड़ दिया. कुल मामला यह कि पुलिस उन्हें एसपीओ बनाने पर आमादा थी और वह इसके लिए तैयार नहीं थे.

कौन है लिंगाराम

वह नोएडा स्थित एक मीडिया संस्थान के इंस्टीट्यूट के किसी कार्यक्रम से जुड़े हैं. उन्होंने दंतेवाड़ा में पुलिसिया जुल्म के शिकार लोगों को दिल्ली लाने और उनकी दु:खभरी दास्तान को कई मंचों से जगज़ाहिर करने की हिम्मत की थी. वनवासी चेतना आश्रम का उदाहरण काफ़ी है, जिसे सरकारी ज़्यादतियों को सतह पर लाने की हिमाकत करने की तगड़ी सज़ा मिली. हालात इतने बिगड़े कि उसके सचिव हिमांशु कुमार को भेष बदल कर दंतेवाड़ा से भागना पड़ा. इन दिनों वह छत्तीसगढ़ के हालात को बताने के लिए साइकिल यात्रा पर हैं और फ़िलहाल पंजाब में हैं. नंदिनी सुंदर इसलिए आंख की किरकिरी हैं, क्योंकि उन्होंने सलवाजुडूम के ख़िलाफ़ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया. जबकि विश्वरंजन उसे आदिवासियों का स्वत: स्फूर्त आंदोलन और गांधीवाद का नया प्रयोग करार देते रहे हैं.

विश्वरंजन ज़रा हट के हैं. पुलिस के आला अधिकारी के साथ-साथ वह कवि एवं लेखक भी हैं. साहित्य उनके ख़ून में रहा है. वह उर्दू के जाने-माने शायर फ़िराक़ गोरखपुरी के पौत्र हैं, जिन्हें नेहरू बहुत मानते थे और फ़िराक़ साहब उनसे भी चुटकी लेने में नहीं हिचकिचाते थे. जो फ़िराक़ साहब को महज़ हुस्नो-इश्क़ और वासना के शायर के बतौर जानते हैं, उन्होंने शायद उनके काव्य संग्रह धरती की करवट को नहीं पढ़ा, जिसमें रोटियां, क़ैदी, जागते रहो, माज़ीपरस्त, नई चेतना जैसी नज़्में शामिल हैं और जो लय-ताल की ख़ूबसूरती के साथ ज़ालिम निजाम से बग़ावत करने का पैग़ाम देती हैं. फ़िराक़ साहब को अपनी धारदार नज़्मों के कारण आज़ादी से पहले जेल की हवा खानी पड़ी थी. आज ज़िंदा होते और लिख रहे होते तो जेल में ही होते. विश्वरंजन अपने पितामह से भी बहुत हट के हैं.

यहां दास्ताने आदम नामक उनकी मशहूर लंबी नज़्म के इस पहले बंद को पेश करना मुनासिब होगा. मुनासिब यह भी होगा कि विश्वरंजन इसे दोबारा पढ़ें, उसका अंग्रेजी या तमिल अनुवाद महाबली चिदंबरम को भी भेंट करें, उसे प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को भी पढ़ाएं, जो कई बार माओवादियों को देश के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बता चुके हैं और जिनकी अध्यक्षता में 14 जुलाई को हुई बैठक में यह तय किया गया कि चार बुरी तरह अशांत राज्यों में माओवाद विरोधी कार्रवाई की एकीकृत कमान बनाई जाए.

कुर्नों के मिटाने से मिटे हैं न मिटेंगे,
आफ़ाते-ज़माना से झुके हैं न झुकेंगे,
उभरे तो दबाने से दबे हैं न दबेंगे,
हम मौत के भी मारे मरे हैं न मरेंगे,
हम ज़िंदा थे, हम ज़िंदा हैं, ज़िंदा रहेंगे.

feedback@chauthiduniya.com

बदलाव जनतांत्रिक तरीक़े से होगा, बंदूक के बल पर नहीं

छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक *विश्वरंजन* का मानना है कि नक्सली बंदूक़ के बल पर बदलाव चाहते हैं, जो संभव नहीं है. परिवर्तन के लिए उन्हें जनतांत्रिक रास्ता अपनाना होगा. पेश हैं उनसे हमारे *समन्वय संपादक मनीष कुमार* की एक लंबी बातचीत के प्रमुख अंश:

आप पर आरोप है कि आपने छत्तीसगढ़ में यह फरमान जारी किया है कि कोई मीडियाकर्मी, कोई अख़बार या टीवी का रिपोर्टर नक्सलियों के साथ खड़ा नज़र आएगा या फिर उनके साथ सहानुभूति रखेगा तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी...

यह तो कहा ही नहीं गया है. मैंने टीवी और कई जगहों पर कहा है कि सिर्फ़ किसी से बात करने पर कोई कार्रवाई नहीं होगी. कार्रवाई तभी हो सकती है, जबकि हमें कोई पॉजिटिव सबूत मिले कि अमुक शख्स नक्सलियों की मदद कर रहा है.

यह कैसे तय होगा कि फलां मीडियाकर्मी नक्सलियों की मदद कर रहा है? अख़बार में रिपोर्ट लिखने के जुर्म में आप किसी पर कैसे कार्रवाई कर सकते हैं?

सिर्फ़ अख़बार में लिखने से यह तय नहीं होगा. वह शख्स तब जर्नलिस्ट नहीं रहेगा, अगर वह नक्सलियों को बंदूक़ पहुंचा रहा है या कुछ और चीज पहुंचा रहा है. फिर वह जर्नलिस्ट का काम नहीं कर रहा होगा न!

दूसरे पुलिस अधिकारियों की तुलना में लोग आपसे कुछ और अपेक्षाएं रखते हैं. आप लेखक हैं, कवि भी हैं. आप अख़बारों में वैचारिक लेख लिखते हैं. क्या आपको नहीं लगता कि आपकी ड्यूटी और आपके विचारों में विरोधाभास है?

मैं एक कवि हूं, संवेदनशील हूं, मैं हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकता. और वैचारिक स्तर पर मैं यह मानता हूं कि नक्सलवाद की जो पूरी विचारधारा है, वह जनतांत्रिक सोच और जनतांत्रिक विचारधारा के ख़िलाफ़ जा रही है. वह एक माओवादी तानाशाही बनाना चाहता है. यह मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वे ख़ुद बोलते हैं. उनका जितना भी साहित्य है, किताबें हैं, उनमें यह बात साफ-साफ लिखी है कि वे हिंसक संघर्ष और हथियारों के जरिए सत्ता पर क़ब्ज़ा करना चाहते हैं. जो जनतांत्रिक सोच है और जिस विचारधारा को लेकर भारत ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, यह सब कुछ उसके बिल्कुल विपरीत जाता है. इसलिए मैं वैचारिक तौर पर उनसे सहमत नहीं हूं.

वैचारिक बहस से दूर ज़मीनी हक़ीक़त तो यह है कि देश के ग्रामीण इलाक़ों में हमारा सरकारी तंत्र विफल हो चुका है. क्या आपको नहीं लगता है कि नक्सलवाद सरकार की गड़बड़ियों का ही नतीजा है?

इसका भी जनतांत्रिक हल ही निकालना पड़ेगा. देखिए, जनतंत्र का भी विकास होना ज़रूरी है. प्रजातंत्र में बदलाव भी जनतांत्रिक तरीक़े से होता है, बंदूक़ के बल पर नहीं होता.

यह बात भी तो सच है कि आज़ादी मिले हुए साठ साल हो गए और अभी भी हमारे गांवों की हालत ख़राब है. वहां ग़रीबी है, बिजली नहीं, पानी नहीं, स्कूल नहीं, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं. ऐसे में ग्रामीणों और वनवासियों के पास दूसरा रास्ता क्या है?

दूसरे देशों में गणतंत्र सौ साल और दो सौ साल में विकसित हुआ है. साठ साल में बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ नहीं हुआ. जो कुछ नहीं हुआ है, उसके लिए हम तानाशाही को तो नहीं ला सकते. यह भी सोचने की बात है कि जहां तानाशाही आई है, वहां क्या हश्र हुआ है.

क्या आपके अंदर का कवि यह मानता है कि सेना से, पुलिस से या सीआरपीएफ से इस आंदोलन को ख़त्म किया जा सकता है?

हम आंदोलन को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, हम हिंसा को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं. आंदोलन को बिना हिंसा के भी चलाया जा सकता है. आख़िरकार माओवादियों के बहुत से ऐसे संगठन हैं, जो हिंसा का रास्ता छोड़कर प्रजातांत्रिक रास्ते पर उतरे हैं. ऐसा नहीं है कि सारे माओवादी हथियार उठाकर ही काम कर रहे हैं. अगर आप पूरे विश्व में वामपंथी आंदोलनों को देखिए तो ऐसा कई जगह हुआ है कि वामपंथ को जनतांत्रिक तरीक़े से लाने की कोशिश की गई, क्योंकि उन्हें लगा कि आज के युग में हिंसा का रास्ता कारगर साबित नहीं होता.

लेकिन हमारे देश में हिंसक आंदोलन का विस्तार हो रहा है. कुछ साल पहले तक पचास ज़िले थे और अब दो सौ साठ ज़िले ऐसे हैं, जहां नक्सलियों का प्रभाव है. क्या वजह है कि देश में हिंसक आंदोलन का वर्चस्व बढ़ता ही चला जा रहा है?

देखिए, बंदूक़ के बल पर वर्चस्व बढ़ाया जा सकता है. मेरा यह मानना है और जिन लोगों ने बस्तर के उन क्षेत्रों में काम किया है, जहां पर इस तरह की हिंसा हो रही है, वे भी जानते हैं और बहुत सारे रिसर्च करने वालों का भी यही मत है कि नक्सलियों का बहुत बड़ा तबका इस डर से उनके साथ है कि अगर वह थोड़ा भी विरोध करेगा तो उसे मार दिया जाएगा. इसलिए हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि वे सही हैं.

चाहे छत्तीसगढ़ हो या उड़ीसा, ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ स्वयंसेवी संगठनों, जो जनजागरण का काम कर रहे हैं, के कार्यकर्ताओं को नक्सली बताकर परेशान किया जाता है. पुलिस उन्हें गिरफ़्तार कर लेती है?

ऐसा सबके साथ नहीं होता है. आज भी बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं. कुछ राज्यों में एक-दो या चार या पांच संस्थाओं को बैन किया गया है, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ पॉजिटिव सबूत मिले हैं कि वे नक्सलियों की मदद कर रहे हैं. यह कहना ग़लत इसलिए भी है, क्योंकि बहुत सारी वामपंथी स्वयंसेवी संस्थाएं भी काम कर रही हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है.

एक अजीबोग़रीब इत्तेफ़ाक़ है कि जहां नक्सलियों का प्रभाव है, वे इलाक़े खनिज पदार्थों के भंडार हैं. सरकार के साथ-साथ विदेशी कंपनियां वहां दोनों हाथों से धन बटोर रही हैं, लेकिन वहां रहने वालों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है...

आप जो कह रहे हैं, उस पर कोई विस्तृत रिसर्च किसी ने नहीं किया है. बस्तर में आज की तारीख़ में एनएमडीसी और बस्तर मिनरल कॉरपोरेशन के अलावा किसी भी मल्टी नेशनल या विदेशी कंपनी को काम नहीं दिया गया है. जहां पर एस्सार की पाइप लाइन जा रही है, वह एनएमडीसी से ख़रीद कर उसके ट्रस्ट को भेजी जा रही है. टाटा को जो स्टील प्लांट बनाने को दिया गया है, आज तक उसके लिए ज़मीन नहीं दी गई है. प्रॉस्पेक्टिंग के लिए भी जो दिया गया, उसमें बस्तर का प्वाइंट वन इलाका शामिल नहीं है. हम तो पुलिस वाले हैं, लेकिन इन बातों की पुष्टि केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर भी की जा सकती है. आपको यह पता होगा कि बस्तर देश का सबसे बेहतरीन जंगली इलाक़ा है और फॉरेस्ट अधिनियम के तहत ज़्यादातर मिनरल उसके अंदर हैं. जंगलों को आप काट नहीं सकते हैं और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमिटी है, जो इसकी अनुमति देती है तो कैसे किसी कंपनी को दिया जा सकता है.

नक्सली इतने ज़िलों में फैले हैं, इतना बड़ा संगठन चला रहे हैं. इसे चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है. नक्सलियों के पास इतना पैसा कहां से आता है?

हक़ीक़त यह है कि इनका बहुत बड़ा पैसा अवैध वसूली से आ रहा है. यह उन लोगों को आतंकित करके लिया जा रहा है, जो बेचारे इन इलाकों में काम करते हैं. अगर आप इन गांवों में जाएं तो देखेंगे कि गांववालों का आधा खाना वे ले जाते हैं. पीडीएस से जो मिलता है, उसका आधा ले जाते हैं. उनको देना पड़ता है. उनकी मिलिट्री प्लाटून के लिए देते हैं, उनके मिलिशिया के लिए देते हैं. जहां भी नक्सली हैं, वहां के आदिवासी दे रहे हैं. इसके अलावा जो छिटपुट काम होते हैं, छोटे-मोटे ठेकेदार होते हैं, जो वहीं रहते हैं, उन्हें डराकर पैसा लिया जाता है. यह पूरा आंदोलन वसूली पर आधारित है और ज़्यादातर भूमिगत आंदोलनों में ऐसा ही होता है. इसमें कुछ भी नया नहीं है. विश्व भर में जहां भी इस तरह के आंदोलन हुए हैं, वहां अवैध वसूली होती ही है.

ख़बरें तो यह भी आ रही हैं कि सरकारी अधिकारी भी नक्सलियों को पैसे दे रहे हैं...

बस्तर में यह नहीं होता है, यह किसी दूसरी जगह की बात हो सकती है. नार्थ ईस्ट के इलाक़ों में उल्फा को लेकर इस तरह की चीजें सामने आई हैं, लेकिन बस्तर में नक्सलियों ने किसी अधिकारी से पैसा लिया हो, यह नहीं हुआ. बस्तर से तो उन्होंने अधिकारियों को ही निकाल दिया तो पैसा किससे लेंगे.

अगर आपको ये सारी बातें मालूम हैं तो इस अवैध वसूली रैकेट को तोड़ने के लिए कोई रणनीति क्यों नहीं बनाई गई?

ऐसा नहीं है. जहां भी पता लगता है, लोग पकड़े भी जा रहे हैं. हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है. जब हमें लगता है कि हम इसे अदालत में सिद्ध करने में सक्षम हैं तो कार्रवाई करते हैं. ज़ाहिर है कि अंतिम निर्णय तो हम नहीं लेंगे, अदालत ही लेगी.

तो इसका मतलब यह हुआ कि बहुत सारी जानकारियां होने के बावजूद पुलिस कुछ नहीं करती है...

नहीं, हमारा कहना यह नहीं है. हालांकि अपराधी पकड़ा ही जाता है, लेकिन उसे सिद्ध करना पड़ता है. कानूनी प्रक्रिया में जिस न्यायिक व्यवस्था को हम मानते हैं और जितना भी सभ्य समाज है, उसका आधार ही इस बात पर है कि 99 दोषी भले ही छूट जाएं पर किसी एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए. इसलिए पूरी प्रक्रिया धीमी होती है, बहुत ही फूंक-फूंक कर कदम उठाना पड़ता है.

नक्सली जिस तरह कभी ट्रेन की लाइनों को उड़ा देते हैं, थानों पर हमले और पुलिसवालों की हत्याएं हो रही हैं, उससे पूरे देश में भय और ख़ौफ़ का माहौल बन गया है. ऐसा लगने लगा है कि हमारा पूरा तंत्र विफल हो रहा है. क्या आप इस ख़तरे को महसूस नहीं करते, क्या आपको इस बात से डर नहीं लगता है?

इतिहास की जो अवधि होती है, वह किसी आदमी के जीवनकाल की नहीं होती है. इसलिए मेरा मानना है कि जैसे-जैसे प्रजातांत्रिक ताक़तें मज़बूत हुई हैं, वैसे-वैसे हिंसक एवं आतंकवादी शक्तियां ख़त्म हुई हैं. यह हमारे देश में भी होगा, क्योंकि हमारे यहां आजादी की लड़ाई भी जनतांत्रिक सोच को आगे रखकर लड़ी गई. ऐसा संभव ही नहीं है कि इस तरह की ताकतें कुछेक हरकतें करके और थोड़ा-बहुत ख़ौफ़ का माहौल बनाकर अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगी.

अंत में मैं आपसे फिर एक बार पूछना चाहता हूं कि मीडिया पर प्रतिबंध वाली बात में कितनी सच्चाई है...

यह तो आप यहां के मीडियावालों से ही पूछिए. अगर मीडिया को वहां जाने से रोका जाता है तो ख़बरें कहां से आती हैं? वहां की तस्वीरें कहां से आती हैं? यह तो सिर्फ प्रशासन पर दबाव डालने के लिए एक खास तरह के लोग इस तरह की ख़बरों को प्रचारित कर रहे हैं.

manish@chauthiduniya.com

उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हरक सिंह रावत का कहना है कि यहां की जनता ने भाजपा की संस्कारविहीनता के कारण ही संसदीय चुनाव में उसे पूरी तरह नकार दिया.

गडकरी का हेडमास्टर कौन?

राजकुमार शर्मा

नितिन गडकरी, तुम्हारे स्कूल का हेडमास्टर कौन है? जैसा सवाल दागकर देवभूमि उत्तराखंड की शिक्षित जनता ने भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी खड़ी कर दी है. देहरादून के परेड मैदान में अपेक्षा के अनुरूप जनता की मौजूदगी न देखकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर बहक गए और उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस से सवाल कर डाला कि अफ़जल गुरु उसका जमाई लगता है क्या? कांग्रेस ने उसे अपनी बेटी दे रखी है क्या, जिससे वह उसकी हिफ़ाज़त करती फिर रही है? नितिन गडकरी का यह बयान भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना आत्मघाती सिद्ध हो सकता है, इसकी कल्पना भी अगर गडकरी को होती तो वह निश्चित रूप से जनता के बीच ऐसे सवाल न करते. वैसे इस तरह की बचकानी बयानबाज़ी उनकी पहचान बनती जा रही है.

देहरादून एवं यहां की जनता पूरे देश में प्रबुद्धता के लिए जानी जाती है. किसी भी राजनीतिक दल का नेता यहां आता है और भाषण करता है तो उसे सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं. यह पहला अवसर था कि सूबे के नेताओं के तमाम प्रयासों के बावजूद गडकरी की सभा में लोगों की मौजूदगी कम रही. निशंक सरकार एवं भाजपा के दिग्गजों को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी. इसके लिए ख़राब मौसम भी एक कारण रहा. फिर भी राज्य भर से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता आए थे. अपेक्षित भीड़ न पाकर नितिन गडकरी अपने भाषण को चर्चित बनाने के लिए कुछ इस कदर बहके कि उन्होंने आतंकी अफ़जल गुरु को कांग्रेस का दामाद बता डाला. इसके पहले भी नितिन ने एक कहावत के ज़रिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद पर सोनिया गांधी के तलवे चाटने का आरोप लगाकर बचकानी बयानबाज़ी का नमूना पेश किया था. इससे उत्तर प्रदेश के समाजवादियों में खासा उबाल आ गया था. सपा कार्यकर्ताओं ने नितिन गडकरी का पुतला तक फूंक डाला था. गडकरी द्वारा मुलायम सिंह यादव एवं लालू प्रसाद से माफ़ी मांगने के बाद ही मामला शांत हो सका था.

अब एक बार फिर उन्होंने बचकाना बयान देकर ख़ुद को विवादों के घेरे में खड़ा कर दिया है. उनके बयान पर जितना उबाल कांग्रेसजनों में है, उससे कहीं ज़्यादा सूबे की शिक्षित जनता में है. देवभूमि, जिसे कभी भाजपा मॉडल प्रदेश बनाने का सपना देखती थी, अब वहीं की जनता ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी की शिक्षा एवं संस्कारों को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है. वह यह जानने पर तुली है कि गडकरी ने जिस स्कूल में शिक्षा ग्रहण की, उसका हेडमास्टर कौन है? जिसके चलते उन्हें इतने घटिया संस्कार मिले हैं. नितिन ने मंच से जब यह सवाल कांग्रेस एवं उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष से किया तो उन्होंने सोचा कि आतंकवाद के मुद्दे पर वह कांग्रेस को घेर लेंगे और जनता वाह–वाह कर उठेगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ. गडकरी यह भी भूल गए कि वह उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिसके नेतृत्व वाली एनडीए सरकार कांधार कांड को लेकर अपनी ज़बरदस्त किरकिरी करा चुकी है और भाजपा के असली चेहरे से जनता पहले ही वाकिफ़ हो चुकी है. ऐसे में वह किसी राजनीतिक मंच से इस तरह के सवाल करके क्या संदेश देना चाहते हैं? उनका सवाल भले ही कांग्रेस के लिए था, किंतु अब वह उनके और उनकी पार्टी के लिए भारी पड़ रहा है.

उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हरक सिंह रावत का कहना है कि यहां की जनता ने भाजपा की संस्कारविहीनता के कारण ही संसदीय चुनाव में उसे पूरी तरह नकार दिया. इतनी घटिया बयानबाज़ी तो कोई गांव स्तर का कार्यकर्ता भी नहीं करता, जैसी गडकरी ने सार्वजनिक मंच से कर दी. यह सिर्फ़ उनकी बचकानी हरक़त नहीं है, बल्कि भाजपा का संस्कारहीन चरित्र है, जो देश एवं लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है. हरक सिंह ने कांधार कांड का हवाला देते हुए सवाल किया कि वाजपेयी सरकार ने भी आतंकियों की सेवा में विमान भेजे थे. अब नितिन गडकरी को बताना चाहिए कि क्या वे आतंकवादी भाजपा के जमाई लगते थे? उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति एवं जैराम संस्थाओं के अध्यक्ष पीठाधीश्वर ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने गडकरी के बयान की निंदा करते हुए कहा कि इससे पूरी भारतीय जनता पार्टी में संस्कार लोप हो जाने का संकेत मिलता है. उन्होंने भाजपा को सुझाव के साथ आमंत्रण भी दिया कि वह अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को संस्कारों एवं सद्विचारों की शिक्षा हेतु दो माह के लिए उनके आश्रम को सौंप दे. उन्हें ईश्वर से प्रार्थना करके संस्कारवान बना दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी का सवाल उनके मानसिक दिवालियापन का परिचायक है. इसे ईश्वरीय कृपा द्वारा ही ठीक किया जा सकता है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष यशपाल आर्या कहते हैं कि इस बयान की वजह भाजपा के जनाधार का खिसकना है. इसके लिए गडकरी को कांग्रेस के साथ–साथ देहरादून की जनता से भी माफ़ी मांगनी चाहिए. कांग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद्र शर्मा ने कहा कि यह भाजपा के पतन का संकेत है. उसका बड़बोलापन अब जनता को भी नागवार लगने लगा है. गडकरी ने ऐसा बयान देकर निशंक सरकार के घोटालों की चर्चा को ढंकने की कोशिश की है.

देहरादून एवं यहां की जनता पूरे देश में प्रबुद्धता के लिए जानी जाती है. किसी भी राजनीतिक दल का नेता यहां आता है और भाषण करता है तो उसे सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं. यह पहला अवसर था कि सूबे के नेताओं के तमाम प्रयासों के बावजूद गडकरी की सभा में लोगों की मौजूदगी कम रही.

उत्तराखंड में अपने तीन कार्यक्रमों में भाग लेने पहुंचे गडकरी अलग–अलग तरह की पोशाकों में दिखे. जनाक्रोश रैली में वह सफेद–कुर्ता पायजामा पहन कर आए, लेकिन उनके बयान ने उन्हें बदरंग करके रख दिया. इस अवसर पर अपेक्षित भीड़ न जुटने से निशंक सरकार की लोकप्रियता पर सवाल खड़े हो गए हैं. कुछ लोग इस रैली को निशंक सरकार की चला–चली की बेला वाली रैली की संज्ञा दे रहे हैं. जनाक्रोश रैली में जनता में कहीं वह आक्रोश नहीं दिखा, जिसका भाजपा ने प्रचार किया था. पार्टी से जुड़ी कई महिला नेताओं ने आपस में ही कानाफूसी करते हुए कहा, अरे, अध्यक्ष जी को यह क्या हो गया? टिहरी से आईं महिला नेताओं के एक दल ने कहा, इससे अच्छे तो राजनाथ सिंह थे. दून की एक महिला पत्रकार ने सूचना अधिकार क़ानून का सहारा लेकर महाराष्ट्र सरकार से गडकरी की शैक्षिक योग्यता की जानकारी मांगी है.

feedback@chauthiduniya.com

सिल्क नगरी का सच

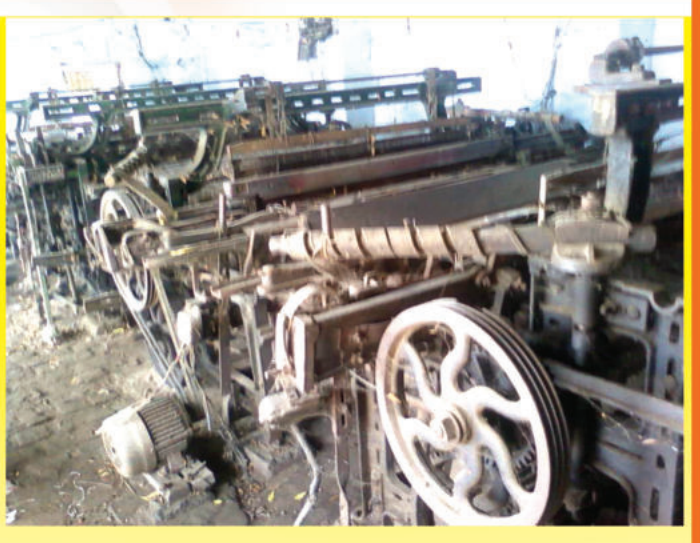

भागलपुर को दुनिया सिल्क नगरी के नाम से जानती है, लेकिन यहां के बुनकरों का हाल बदहाल है. नीतीश कुमार के कार्यकाल में भी बुनकरों की समस्याएं बरक़रार हैं. तो क्या हालात बेहतर बनाने के लिए नीतीश कुमार को भी लालू यादव के शासनकाल की तरह 15 वर्षों का समय चाहिए? यह सवाल उन हज़ारों बुनकरों का है, जो भुखमरी की कगार पर हैं. ज़ाहिर है, सरकार को इन सवालों का जवाब तो देना ही होगा.

कुमार सुशांत

चंपानगर (भागलपुर) निवासी मोहम्मद जावेद अंसारी एक बुनकर है. उसके पास ख़ुद का पावरलूम तो है, लेकिन इतना पैसा नहीं कि वह उसे चला सके. इसके अलावा बिजली की समस्या अलग से. नतीजतन, उसके घर की स्थिति दिनोंदिन दयनीय होती जा रही है. अंसारी ने परिवार की दो वक़्त की रोटी जुटाने के लिए बाहर जाने का फ़ैसला किया है, लेकिन वह असमंजस में है कि बाहर जाकर करेगा तो क्या? क्या इतना कमा पाएगा कि वहां से अपने घर–परिवार के लिए पैसा भेज सके? उसे सरकार की विभिन्न योजनाओं की भी जानकारी है, लेकिन वह कहता है कि उन योजनाओं का लाभ सिर्फ़ पहुंच वाले लोगों को ही मिल पाता है, उस जैसे ग़रीब को नहीं. इसीलिए सरकारी योजनाओं और घोषणाओं से उसका भरोसा उठ चुका है. बुनकर मोहम्मद इसराफ़िल अंसारी बताते हैं कि बुनकरों को कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है, इसीलिए स्थिति भुखमरी तक आ पहुंची है. परिणामस्वरूप वे धीरे–धीरे दूसरे शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं. पिछले चार–पांच सालों के अंदर क़रीब 8 से 10 हज़ार बुनकर मुंबई, मेरठ, मद्रास एवं दिल्ली आदि शहरों में चले गए. अंसारी बताते हैं कि इनमें से कुछ तो दूसरे शहरों में पावरलूम कंपनियों में ही काम रहे हैं, जबकि काम न मिल पाने की वजह से कुछ लोग ऑटो–रिक्शा चलाने और सब्ज़ी बेचने के लिए मजबूर हैं.

आंकड़ों के मुताबिक़, पूरे बिहार में बुनकरों की संख्या क़रीब 4 लाख है. केवल भागलपुर में ही 50 हज़ार से अधिक बुनकर हैं. भागलपुर के नाथनगर, चंपानगर, हसनाबाद एवं नरगाह आदि इलाक़ों में सबसे ज़्यादा बुनकर हैं, जिनकी आय का ज़रिया केवल सिल्क उद्योग ही रहा है. वर्ष 1989 तक भागलपुर के बुनकर अकेले पूरे देश का 48 फ़ीसदी सिल्क तैयार करते थे. उस समय जनसंघ के विजय मित्रा भागलपुर के विधायक थे. राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे भागवत झा आज़ाद. उस ज़माने में देश के अलावा विदेशों में भी भागलपुरी सिल्क की बेहद मांग थी. भागलपुर में सरकारी रेशम कॉलेज भी हुआ करता था, जिसमें रेशम बनाने के गुर सीखने के लिए दूर–दूर से छात्र आते थे. उन्हें कॉलेज की तरफ़ से डिप्लोमा दिया जाता था. समय बदला. 1989 में दंगे हुए. सब कुछ ख़त्म हो गया. सच कहा जाए तो उस दंगे की आग में अगर सबसे ज़्यादा किसी को नुक़सान हुआ तो वे थे भागलपुर ज़िले के बुनकर, जिनकी रोजी–रोटी सिल्क तैयार करने से ही चलती थी. दंगे के बाद इस उद्योग में लगातार गिरावट आती गई. विदेशों से ऑर्डर आने बंद हो गए. 1990 में लालू यादव की सरकार आई. बुनकरों को लालू से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन अफ़सोस कि उम्मीदें सिर्फ़ उम्मीदें बनकर रह गईं. बुनकरों की स्थिति दिनोंदिन बिगड़ती चली गई. रेशम कॉलेज को भी बदहाली का शिकार होना पड़ा और आख़िरकार वह बंद हो गया. उसका मामला आज भी अदालत में विचाराधीन है.

बिहार बुनकर कल्याण समिति के सदस्य हाजी अलीम अंसारी कहते हैं कि 1990 तक भागलपुर में सिल्क बाज़ार की स्थिति अच्छी थी. पहले सिल्क का धागा सस्ता था, अब इसकी क़ीमत में ज़बरदस्त उछाल आ गया है. केंद्र और राज्य सरकार की ओर से बुनकरों के हित में कई योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन उनका लाभ बुनकरों तक नहीं पहुंच पाता. योजनाओं का अधिकतर पैसा बिचौलिए और सरकारी कर्मचारी ही हजम कर जाते हैं. इलाक़े में पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है. गलियों और चौराहों पर गंदगी का अंबार लगा पड़ा है. शहर के एक चिकित्सक डॉ. एस पी सिंह का कहना है कि बुनकरों में टीबी, निमोकोनिएसिस और दमा की बीमारी लगातार बढ़ रही है. वह बताते हैं कि उक्त बीमारियां काम के दौरान काटन का बुरादा उड़ने और सांस द्वारा फेफड़े में जाने से होती हैं. चिकित्सकों का मानना है कि चूंकि बुनकर गंदगी में जीवन बसर कर रहे हैं, इसीलिए इनके स्वास्थ्य को ज़्यादा ख़तरा है. गौरतलब है कि जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, यह सोचकर कि इलाक़े का विकास होगा और उनका दु:ख–दर्द दूर होगा.

भागलपुर संसदीय क्षेत्र में बुनकर मतदाताओं की संख्या क़रीब डेढ़ लाख है, वहीं भागलपुर विधानसभा के अंतर्गत क़रीब 45 हज़ार बुनकर मतदाता हैं. इन आंकड़ों से पता चलता है कि यहां कौन सांसद या विधायक बनेगा, यह फ़ैसला बुनकरों के वोट करते हैं. वर्ष 1995 में बुनकरों ने स्थानीय भाजपा नेता अश्विनी चौबे को अपना विधायक चुना, यह सोचकर कि वह उनकी समस्याओं को दूसरों के मक़ाबले कहीं बेहतर ढंग से समझेंगे, लेकिन परिणाम जस का तस रहा. कहीं कोई बदलाव नहीं आया. 2004 के लोकसभा चुनाव में लोगों ने एक बार फिर भाजपा को मौक़ा दिया और पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी यहां से सांसद बने. भागलपुर में मोदी को लाने के पीछे एक उद्देश्य यह भी था कि विधायक और सांसद दोनों अगर एक ही पार्टी के हों तो शायद कुछ विकास हो जाए, फरियाद सुन ली जाए, लेकिन ढाक के तीन पात वाली कहावत चरितार्थ हुई. वर्ष 2005 में जदयू–भाजपा गठबंधन वाली नीतीश सरकार बनी. अश्विनी चौबे लगातार तीसरी बार विधायक बने. वह राज्य सरकार में मंत्री और सांसद सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बन गए. मोदी के उप मुख्यमंत्री बनने से भागलपुर संसदीय सीट खाली हो गई. इस बार भाजपा की ओर से कद्दावर नेता सैयद शाहनवाज़ हुसैन को मैदान में उतारा गया. किशनगंज से हार चुके शाहनवाज़ ने भागलपुर के बुनकरों से ढेर सारे वादे किए. बुनकरों एवं भागलपुर की जनता को लगा कि शाहनवाज़ बड़े नेता हैं, सुधार ज़रूर होगा और फिर शाहनवाज़ भी जीत गए, लेकिन हालात नहीं बदले. भागलपुर का रेशम कॉलेज आज भी बंद है और बुनकरों की बदहाली का रंग दिनोंदिन गहराता जा रहा है. इलाक़े में विधायक, सांसद एवं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम तो होते हैं, घोषणाएं भी होती हैं, लेकिन कुछ दिनों के शोर के बाद सब कुछ ठंडा पड़ जाता है. हर बार मामला बिजली आपूर्ति और बैंक ऋण में उलझ कर ठंडे बस्ते में चला जाता है.

ज़िले के एक वार्ड पार्षद ख़ुर्शीद आलम उर्फ़ बबलू बताते हैं कि बैंकों ने अब बुनकरों को कर्ज़ देना भी बंद कर दिया है. सरकारी घोषणाओं के बावजूद नाथनगर, चंपानगर एवं हसनानगर में शायद ही ऐसा कोई बुनकर हो, जिसे बैंक ने कर्ज़ दिया हो. नतीज़तन, बुनकर साहूकारों से 5 रुपये प्रति सैकड़ा प्रति माह की ब्याज दर से कर्ज़ लेते हैं, जिसे चुकाने के लिए घर–ज़मीन तक बेचना पड़ जाता है. नाथनगर के बुनकर मोहम्मद नूर आलम का कहना है कि सबसे बड़ी समस्या बिजली की है. वह बताते हैं कि भागलपुर में बिजली बस नाममात्र के लिए है, इसलिए हम ख़ुद का पावरलूम नहीं बना पाते. स्थिति यहां तक ख़राब है कि 24 घंटे में केवल 3–4 घंटे ही बिजली देखने को मिलती है. आलम बताते हैं कि पूरे इलाक़े में केवल 10–12 बड़े व्यवसायी हैं, जिनके पास पूंजी है. वही जनरेटर और पैसे की बदौलत अपने कारखानों को जिंदा रखने में सफल रहे हैं. उनके यहां बुनकर काफी कम मज़दूरी पर काम करते हैं, क्योंकि काम कम है और बुनकरों की संख्या अधिक. एक समाज सेवी एवं बुनकर मोहम्मद आलमगीर बताते हैं कि सत्ता पर बैठे बड़े–बड़े नेता चुनाव के समय ढेरों वादे करते हैं, लेकिन बुनकरों के हित में कभी कुछ करते नहीं.

नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने से यहां के बुनकरों में उम्मीद जगी थी कि अब कुछ अच्छा होगा. लेकिन दुख की बात है कि ऐसा नहीं हो सका. नीतीश सरकार का भी कार्यकाल पूरा होने वाला है, लेकिन बुनकरों की समस्याएं आज भी जस की तस हैं. अब बुनकरों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि हमारी हालत सुधारने के लिए नीतीश कुमार को भी लालू यादव के शासनकाल की तरह 15 वर्षों का समय चाहिए? यह सवाल उन हज़ारों बुनकरों के हैं, जो आज भुखमरी की कगार पर हैं. और, वे इन सवालों का जवाब अपने राज्य के मुखिया से चाहते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

नीतीश सरकार का दावा है कि मुसलमानों को स्वरोज़गार देने और शिक्षित करने के लिए बहुत सारे काम किए गए.

वायदों के भ्रमजाल में मुसलमान

सरोज सिंह

बरसात के इस मौसम में बिहार के मुसलमानों के लिए नीतीश सरकार ने घोषणाओं की बारिश शुरू कर दी है. वक़्त चुनाव का है और मसला धर्मनिरपेक्ष छवि का. इस वजह से दिल और खजाना दोनों खोलने का ऐलान हो रहा है. यह सिलसिला पिछले साढ़े चार सालों से जारी है. मुसलमानों के कल्याण के लिए राज्य में चलाई जा रही कितनी योजनाएं ज़मीन पर उतरीं, इसे लेकर सरकार और विपक्ष के अपने-अपने दावे हैं, लेकिन तल्ख हक़ीक़त यह है कि सूबे का आम मुसलमान आज भी अपनी बेहतरी का इंतज़ार कर रहा है. इतना ज़रूर है कि इस दौरान राज्य में अमन-चैन क़ायम रहा और अल्पसंख्यकों ने भय के माहौल में अपनी रात नहीं गुजारी. पर सुबह से रात होने तक मुसलमानों ने नीतीश राज में भी ख़ुद को वायदों के भ्रमजाल में फंसा पाया और मुसीबतों से लड़ते-लड़ते उनका पूरा दिन बीतता रहा.

नीतीश सरकार का दावा है कि मुसलमानों को स्वरोज़गार देने और शिक्षित करने के लिए बहुत सारे काम किए गए. प्राथमिक स्कूलों में बड़ी संख्या में उर्दू शिक्षकों का नियोजन किया गया. स्कूल से बाहर के मुस्लिम बच्चों के लिए तालीमी मरकज, बालिकाओं के व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए हुनर और औजार, अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना एवं अल्पसंख्यक विद्यार्थी कोचिंग योजना शुरू की गई. सरकार कहती है कि अब तक 2.21 करोड़ रुपये अल्पसंख्यक छात्रों के बीच प्रोत्साहन राशि के तौर पर वितरित किए जा चुके हैं. इसके अलावा अल्पसंख्यक छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण के लिए 16.77 करोड़ और छात्रों के छात्रावास के लिए 35.57 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इसके साथ ही 1994 से बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा मदरसों को मान्यता देने पर लगाई गई रोक को हटाने का फ़ैसला लिया गया, ताकि राज्य के अच्छे मदरसे बोर्ड से मान्यता पा सकें. पर्याप्त संख्या में आधारभूत संरचना वाले मदरसों को उत्क्रमित करने का निर्णय भी नीतीश सरकार ने लिया है. अभी नौ जुलाई को रिपोर्ट कार्ड जारी करने के मौक़े पर मुख्यमंत्री ने 27 हज़ार उर्दू शिक्षकों की भर्ती करने की घोषणा की. घोषणाओं के आसमान से उतरें तो बस एक उदाहरण से बहुत कुछ समझने में सहूलियत होगी. दरभंगा में मुस्लिम छात्राओं का एक स्कूल है, सोहरा हाईस्कूल. इसमें ग़रीब परिवारों की 1500 लड़कियां तालीम हासिल करती हैं. स्कूल में जाने पर पता चला कि पर्याप्त सरकारी मदद के अभाव में इसे चलाने और बच्चों को बेहतर शिक्षा देने में संचालकों को कितनी परेशानी हो रही है. यह तो सोहरा हाईस्कूल चलाने वालों का जुनून है कि यहां इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम छात्राओं को समाज में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया जा रहा है. दरभंगा में ही ऐतिहासिक मिल्लत कॉलेज भी है. इसे शुरू करने वाले तो अब नहीं रहे, पर उनके वंशजों की ख्वाहिश है कि इस कॉलेज के पुराने गौरव को स्थापित करने के लिए इसके अल्पसंख्यक दर्जे को फिर से बहाल कर दिया जाए. ढेर सारे तर्कों के साथ ज़रूरी काग़ज़ातों की मोटी फाइल सचिवालय में घूम रही है, पर कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा है.

अब जरा राजद के आरोपों पर ग़ौर करें. उर्दू शिक्षकों की बहाली पर राजद का आरोप है कि इसके लिए निकाले गए विज्ञापन में सरकार ने ऐसे पेंच लगा दिए हैं कि किसी भी सूरत में एक हज़ार से ज़्यादा लोगों की बहाली नहीं हो सकती. ग़ौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बिहार में 12,862 उर्दू शिक्षकों की बहाली होनी है. इसी तरह 27 हज़ार नए उर्दू शिक्षकों की भर्ती की सरकारी घोषणा को राजद ने चुनावी घोषणा करार दिया है. उसका मानना है कि यह घोषणा चुनावी आचार संहिता में फंस जाएगी. राजद का आरोप है कि सर्वशिक्षा अभियान के तहत वर्ग तीन से आठ तक उर्दू किताबों का वितरण नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते ग़रीब अल्पसंख्यक छात्रों की पढ़ाई लगभग ठप है. पुस्तकालयाध्यक्षों की बहाली में भी नीतीश सरकार ने भेदभाव किया. 1400 पुस्तकालयाध्यक्षों की बहाली होनी थी, पर सरकार ने आलिम की मान्यता ही ख़त्म कर दी. इसके पूर्व वैसे आलिम, जिनके पास पुस्तकालय विज्ञान की डिग्री होती थी, बतौर पुस्तकालयाध्यक्ष बहाल हो जाते थे. लेकिन जब सरकार को पता चला कि 545 पुस्तकालयाध्यक्ष मुस्लिम ही बन गए तो उसने आलिम की मान्यता ही समाप्त कर दी और जब पुस्तकालयाध्यक्षों की बहाली प्रकिया पूरी हो गई तो आलिम की मान्यता फिर बहाल कर दी गई. इसी तरह किशनगंज में एएमयू की शाखा के लिए जो ज़मीन दी गई है, वह तीन टुकड़ों में है, जो कि सरकार की नीयत पर शक पैदा करता है.

सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार ने लगातार घोषणा की कि राज्य सरकार सभी क़ब्रिस्तानों की पैमाइश कराकर उनकी घेराबंदी कराएगी. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले वर्ष राज्य सरकार ने क़ब्रिस्तानों की घेराबंदी में कुल 51.63 करोड़ रुपये की राशि ख़र्च की.

सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार ने लगातार घोषणा की कि राज्य सरकार सभी क़ब्रिस्तानों की पैमाइश कराकर उनकी घेराबंदी कराएगी. सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले वर्ष राज्य सरकार ने क़ब्रिस्तानों की घेराबंदी में कुल 51.63 करोड़ रुपये की राशि ख़र्च की. सूबे के कुल 8064 क़ब्रिस्तानों में से 1253 की घेराबंदी की जा चुकी है.

वर्ष 2010-11 के लिए 30.67 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. राजद का मानना है कि राज्य में छोटे-बड़े 15,000 क़ब्रिस्तान हैं और इस काम की गति को देखकर लगता है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है. सरकार कहती है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने मुसलमानों की बेहतरी के लिए कई योजनाएं चलाई हैं और उन पर काफी धन ख़र्च किया जा रहा है. लेकिन बिहार सरकार द्वारा 2005-06 से 2010-11 के बीच कुल योजना ख़र्च में अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी औसतन 0.20 प्रतिशत ही रही. जबकि राज्य में मुसलमानों की आबादी लगभग 16.53 प्रतिशत है. इसी तरह मल्टी सेक्ट्रोल डेवलपमेंट स्कीम के तहत बिहार के सात मुस्लिम बहुल ज़िले कटिहार, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, दरभंगा, सीतामढ़ी एवं पूर्वी चंपारण के लिए 525 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जिसमें से नीतीश सरकार ने मात्र 13.5 करोड़ रुपये ही ख़र्च किए. राजद का आरोप है कि बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम को नीतीश सरकार ने अपने कार्यकाल में अंशदान पूंजी के मद में एक पैसा भी नहीं दिया, जिसके कारण राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त निगम से आवंटन बंद है और अल्पसंख्यकों को रोज़गार के लिए क़र्ज़ नहीं मिल पा रहा है. राज्य के बुनकरों के लिए नीतीश कुमार ने भागलपुर, बिहार शरीफ और पटना के सिगोड़ी में कई वायदे किए, लेकिन एक पर भी अमल नहीं हुआ. बुनकरों के मान-सम्मान की प्रतीक बुनकर सहयोग समिति, बिहार शरीफ के भवन को मात्र आठ लाख रुपये के लिए राज्य सरकार ने नीलाम करा दिया.

इस मुख्यालय से पटना एवं मगध प्रमंडल के 11 ज़िलों का नियंत्रण होता था. इस तरह जो तस्वीर उभरती है, उससे पता चलता है कि वायदे तो बहुत हुए और उनका प्रचार भी बहुत हुआ, पर वे पूरी तरह ज़मीन पर नहीं उतर पाए. इस कारण सूबे का मुसलमान हाशिए पर खड़ा दिखाई पड़ता है.

feedback@chauthiduniya.com

मेरी दुनिया.... भारत-पाक बातचीत ...धीर

कराहती नदियां

सुरेंद्र अग्निहोत्री

कभी जीवनदायिनी रहीं हमारी पवित्र नदियां आज कूड़ा घर बन जाने से कराह रही हैं, दम तोड़ रही हैं. गंगा, यमुना, घाघरा, बेतवा, सरयू, गोमती, काली, आमी, राप्ती, केन एवं मंदाकिनी आदि नदियों के सामने ख़ुद का अस्तित्व बरकरार रखने की चिंता उत्पन्न हो गई है. बालू के नाम पर नदियों के तट पर क़ब्ज़ा करके बैठे माफ़ियाओं एवं उद्योगों ने नदियों की सुरम्यता को अशांत कर दिया है. प्रदूषण फैलाने और पर्यावरण को नष्ट करने वाले तत्वों को संरक्षण हासिल है. वे जलस्रोतों को पाट कर दिन-रात लूट के खेल में लगे हुए हैं. केंद्र ने भले ही उत्तर प्रदेश सरकार की सात हज़ार करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना अपर गंगा केनाल एक्सप्रेस-वे पर जांच पूरी होने तक तत्काल रोक लगाने के आदेश दे दिए हों, लेकिन नदियों के साथ छेड़छाड़ और अपने स्वार्थों के लिए उन्हें समाप्त करने की साजिश निरंतर चल रही है. गंगा एक्सप्रेस-वे से लेकर गंगा नदी के इर्द-गिर्द रहने वाले 50 हज़ार से ज़्यादा दुर्लभ पशु-पक्षियों के समाप्त हो जाने का ख़तरा भले ही केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की पहल पर रुक गया हो, लेकिन समाप्त नहीं हुआ. गंगा और यमुना के मैदानी भागों में माफ़ियाओं एवं सत्ताधीशों की मिलीभगत साफ दिखाई देती है. नदियों के मुहाने और पाट स्वार्थों की बलिवेदी पर नीलाम हो रहे हैं.

बड़ी मात्रा में रेत खनन के चलते जल जीवों के सामने संकट पैदा हो गया है. गंगा की औसत गहराई वर्ष 1996-97 में 15 मीटर थी, जो वर्ष 2004-2005 में घटकर 11 मीटर रह गई. जलस्तर में गिरावट निरंतर जारी है. आईआईटी कानपुर के एक शोध के अनुसार, पूरे प्रवाह में गंगा क़रीब चार मीटर उथली हो चुकी है. गाद सिल्ट के बोझ से बांधों की आयु घटती जा रही है. जीवनदायिनी और सदा नीरा गंगा कानपुर के पास दशक भर पूर्व 15 से 20 मीटर गहरी थी, जबकि पहाड़ी इलाक़ों में इसकी गहराई मात्र चार मीटर ही थी. जलवायु विशेषज्ञ परमेश्वर सिंह अपनी पुस्तक पर्यावरण के राष्ट्रीय आयाम में नदियों के घटते दायरे पर चिंता जता चुके हैं. वह कहते हैं, बात केवल गंगा तक ही सीमित नहीं है. पिछले एक दशक में बूढ़ी गंडक 6 से 4 मीटर, घाघरा 6 से 4 मीटर, बागमती 5 से 3 मीटर. राप्ती 4.5 एवं यमुना की औसत गहराई 3.5 से दो मीटर तक कम हो चुकी है. नदियों का पानी पीने लायक तक नहीं बचा है. कभी बेतवा नदी का पानी इतना साफ एवं स्वास्थ्यवर्द्धक होता था कि टीबी के मरीज़ इस जल का सेवन करके स्वस्थ हो जाते थे. आज बेतवा के किनारे स्थित बस्ती के लोग उसमें गंदगी डाल रहे हैं. बेतवा में नहाने वाले लोग चर्म रोग का शिकार हो रहे हैं. यमुना नदी में पुराने यमुना घाट से लेकर पुल तक बड़ी संख्या में शव प्रवाहित किए जा रहे हैं. हमीरपुर का गंदा पानी पुराने यमुना घाट पर नाले के ज़रिए नदी में डाला जा रहा है. नदी की सफाई करने वाली मछलियां, घोघे एवं कछुए समाप्त हो गए हैं. यहां लोग पानी का आचमन करने से भी डरते हैं.

डुमरियागंज से निकली आमी नदी रुधौली, बस्ती, संत कबीर नगर, मगहर एवं गोरखपुर ज़िले के क़रीब ढाई सौ गांवों से होकर बहती है. यह नदी कभी इन गांवों को हरा-भरा रखती थी. गोरख, कबीर, बुद्ध एवं नानक की तपोस्थली रही आमी आज बीमारी और मौत का पर्याय बन चुकी है. यह नदी 1990 के बाद तेज़ी से गंदी हुई. रुधौली, संत कबीर नगर एवं 93 में गीडा में स्थापित की गईं फैक्ट्रियों से आमी का जल तेज़ी से प्रदूषित हुआ. इन फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा सीधे आमी में गिरता है. आमी के प्रदूषित हो जाने के चलते इलाक़े से दलहन की फ़सल ही समाप्त हो गई. गेहूं और तिलहन का उत्पादन भी खासा प्रभावित हुआ है. पेयजल का भीषण संकट है. नदी तट से तीन-चार किमी तक हैडपंपों से काला बदबूदार पानी गिरता है.

आमी तट के गांव में जब महामारी आई तो सीएमओ की टीम ने अपनी जांच में पाया कि सभी बीमारियों की जड़ आमी का प्रदूषित जल है. आमी के प्रदूषण के चलते मगहर, सोहगौरा एवं कोपिया जैसे गांवों के अस्तित्व पर संकट आ गया है.

आमी का गंदा जल सोहगौरा के पास राप्ती नदी में मिलता है. सोहगौरा से कपरवार तक राप्ती का जल भी बिल्कुल काला हो गया है. कपरवार के पास राप्ती सरयू नदी में मिलती है. यहां सरयू का जल भी बिल्कुल काला नज़र आता है. बताते हैं कि राप्ती में सर्वाधिक कचरा नेपाल से आता है. उसे रोकने की आज तक कोई पहल नहीं हुई. पिछले दिनों राप्ती एवं सरयू के जल को इंसान के पीने के अयोग्य घोषित किया गया. यह पानी पशुओं के पीने के लायक तो माना गया, मगर इन नदियों के तट पर बसे गांवों के लोग पशुओं को यह जल नहीं पीने देते.

ऐसा लगता है कि अपनी दुर्दशा पर नदी संवाद करती हुई कहती है, मैं काली नदी

हूं. मानों तो काली मां. भूल तो नहीं गए! ऐसा इसलिए कि आजकल मेरे पास कोई आता कहां है. सभी ने मुझे अकेला छोड़ रखा है मरने के लिए. वैसे भी मैं ज़िंदा हूं कहां? मेरा पानी न पीने लायक है, न सिंचाई लायक. पर्यावरणविद् तो मुझे मुर्दा बता चुके हैं. मैं हूं ही ऐसी. किसी प्यासे को जीवन नहीं दे सकती. जिस ज़मीन को छू लूं, वह बंजर हो जाए. मेरी दशा हमेशा से ऐसी नहीं थी. मेरा भी बचपन था, जवानी थी...क्या दिन थे वे! ख़ूब बारिश होती थी. सारे ताल-तलैया और नाले लबालब हो उठते थे. धुआंधार बारिश के बीच ही क़रीब 150 साल पहले मुज़फ़्फ़रनगर के गांव उंटवारा में मेरा जन्म हुआ था. इसमें खतौली के पास स्थित गांवों निठारी एवं जंढेडी के योगदान को भला कैसे भूल सकती हूं. यहीं की बारिश का पानी मेरे लिए ऑक्सीजन देता था. यह न मिलता तो मेरा नामोनिशान कब का मिट चुका होता. यहां से शुरू हुआ मेरा सफर 374 किलोमीटर दूर तक पहुंचा. इस दौरान मेरे निकट 1200 गांव, क़स्बे और शहर आए. मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, कांशीराम नगर, एटा, फर्रुखाबाद और कन्नौज ने मुझे अपनाया, रास्ता दिया. शुरू में सभी का स्नेह मिला. किसानों ने सूखती फ़सलों को मेरा पानी दिया. वे लहलहा उठीं. मछलियां, कीड़े-मकोड़े सभी ख़ूब अठखेलियां करते, गोते लगाते. जलीय पौधे भी स्वस्थ रहते थे.लेकिन आज ख़ुद को देखती हूं तो हूक सी उठती है. मृत्युशैय्या पर पड़ी हूं, आख़िरी सांसें ले रही हूं. मेरा सब कुछ लुट चुका है. जलीय जीव-जंतु सब मर चुके हैं. मेरे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घटती चली गई. अलीगढ़ आने के पहले तक कुछ ज़िंदा रहने की गुंजाइश भी थी, लेकिन यहां अब दो मिलीग्राम प्रति लीटर डिसाल्व ऑक्सीजन में कैसे बचते जलीय जीव-जंतु? साधु आश्रम के पास मेरे पानी में ज़िंदा रहने लायक कुछ नहीं बचा. अब ख़ुद को ज़िंदा लाश न मानूं तो क्या करूं? किसी से कहूं भी तो क्या? जिन्हें ज़िंदगी भर बेटे की तरह माना, वही आस्तीन के सांप निकले. वे अपनी फैक्ट्रियों और सीवर का कचरा मेरे ऊपर उड़ेल रहे. इससे मेरी काया काली होती गई, पानी ज़हर बनता गया. पर्यावरणविद् मेरी प्रकृति को क्षारीय बता रहे हैं. कन्नौज में मेरा हाल एकदम सीवर

के पानी जैसा हो चुका है. मैं यह बोझ अब और नहीं झेल सकती. बड़ी मां गंगा ही मेरा उद्धार करेंगी, लेकिन सुना है कि मोक्षदायिनी मां गंगा भी मैली होती जा रही हैं. मैं तो आख़िरी सांसें गिन ही रही हूं. मेरे साथ जो सलूक किया, वैसा कम से कम मोक्षदायिनी गंगा मइया के साथ मत करना. यही मेरी अंतिम इच्छा है. क्या पूरी करेंगे आप सब?

प्रख्यात पर्यावरणविद् प्रो. वीरभद्र मिश्र को इस बात से थोड़ी तसल्ली ज़रूर है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह क्लीन गंगा मिशन में व्यक्तिगत रुचि ले रहे हैं, लेकिन पुराने अनुभव प्रो. मिश्र को आशंकाओं से मुक्त नहीं कर पा रहे. वह कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने 2020 तक गंगा में गिरने वाले नालों को पूरी तरह रोकने और सीवेज के ट्रीटमेंट का भरोसा दिलाया है, लेकिन इसके लिए प्रस्तावित उपायों का ख़ुलासा नहीं किया. फिर यह सवाल भी उठना लाज़िमी है कि तब तक केंद्र में किसकी सरकार होगी और उसका गंगा को लेकर नज़रिया क्या होगा? प्रो. मिश्र ने गंगा के मामले में सैद्धांतिक से कहीं ज़्यादा व्यवहारिक पक्ष को महत्व दिए जाने पर जोर दिया. राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के सदस्य प्रो. मिश्र ने कहा कि आज सबसे बड़ा संकल्प यह होना चाहिए कि गंगा में एक भी नाला नहीं गिरने दिया जाएगा. गंगा तट पर वाराणसी समेत 116 शहर बसे हैं, जिनकी आबादी एक लाख से ज़्यादा है. इन शहरों के नालों से गिरने वाली गंदगी ही गंगा के 95 फ़ीसदी प्रदूषण का कारण है. ज़रूरत इस बात की है कि नालों को डायवर्ट कर शोधन की त्रुटिविहीन व्यवहारिक व्यवस्था लागू की जाए. प्रो. मिश्र इस बात से पूरा इत्तेफ़ाक रखते हैं कि गंगा में पर्याप्त जल होना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल ज़्यादा पानी छोड़े जाने भर से प्रदूषण कम नहीं होगा. वह पर्यावरण असंतुलन के लिए प्राकृतिक चक्र में व्यवधान को कारण बताते हैं. उनका कहना है कि मनुष्य अपने फ़ायदे के लिए प्राकृतिक स्रोतों का ज़बरदस्त दोहन कर रहा है. यही वजह है कि कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा विनाशकारी साबित हो रहे हैं. प्रकृति में वेस्ट नामक कोई चीज नहीं रही. सब कुछ री-साइकिलिंग से नियंत्रित हो रहा है.

मानसून के बल पर सदनीरा बनने वाली नदियां वर्षा की बूंदों को अपने आंचल में छुपाकर एक लंबी यात्रा के साथ हमारे होंठो को तरलता देकर जीवन चक्र को गतिमान करती हैं. प्रकृति के इस विराट खेल का अंदाज़ा इसी बात से चल जाता है कि भारत के पश्चिमी तट पर क़रीब 75 अरब टन जल बरसता है. मैदानी इलाक़ा 15 लाख किमी के क्षेत्र में फैला है. इस क्षेत्र में 1.7 सेमी औसत दैनिक वर्षा का अर्थ हुआ कि पश्चिमी तट से भारत में प्रवेश करने वाली वाष्प का एक तिहाई भाग जल में परिवर्तित होता है. जल है तो कल है, का नारा लगाने वाले भारतीय मानसून नामक अरबी शब्द से अपनी सारी आशा-आकांक्षाएं प्रकट करते हैं. इस एक शब्द ने सदियों से लोगों को इतना प्रभावित किया है कि हमारी जीवनशैली एवं संस्कृति मानसून और नदियों के इर्द-गिर्द सिमट गई है. गंगा और यमुना का मैदानी भाग दुनिया का सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है. लेकिन अब गंगा ही नहीं, बेतवा, केन, शहजाद, सजनाम, जामुनी, बढ़ार, बंडई, मंदाकिनी एवं नारायन जैसी अनेक छोटी-बड़ी नदियों के सामने संकट खड़ा हो गया है. ललितपुर में बीच शहर से निकलने वाली शहजाद नदी का हाल बेहाल है. प्रदूषण की शिकार इस नदी को लोगों ने अपने आशियाने के रूप में इस्तेमाल करने के लिए आधे से ज़्यादा पाट दिया हैं. यही हाल इससे मिलने वाले नालों का है. उन पर आलीशान मकान खड़े हो गए हैं. बंडई नदी मड़ावरा ब्लॉक में जंगली नदी के रूप में बहती है. इससे जंगली जानवरों के लिए पीने का पानी सुलभ होता है. इसकी भी असमय मौत हो रही है. चित्रकूट में बहने वाली मंदाकिनी नदी के सामने प्रदूषण का ख़तरा मंडरा रहा है. नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अनाप-शनाप पैसा फूंक रही हैं. गोमती नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 285.6857 करोड़ रुपये अवमुक्त हो चुके हैं, लेकिन गोमती का हाल ज्यों-का-त्यों बना हुआ है. बेशक़ीमती प्रकृति स्रोत प्रदान करने वाली नदियों-नालों के साथ हो रही छेड़छाड़ ने संकट खड़ा कर दिया है. कराहती नदियां अपनी पीड़ा कहें तो किससे कहें? कौन सुनेगा उनकी अकाल मृत्यु की शोक गाथा! कौन मनाएगा मातम!

feedback@chauthiduniya.com

गंगा को प्रदूषित करते शहर

आबादी में छोटे एवं मंझोले शहरों की श्रेणी में आने वाले छह शहर ऐसे हैं, जिनके नालों का गंदा पानी परोक्ष रूप से गंगा में मिलकर उसे मैला करता है और उसे साफ करने के लिए सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) लगाए जाने की कोई भावी योजना भी नहीं है. इनमें बबराला, उझेनी एवं गुन्नौर (बदायूं), सोरों (एटा) और बिल्हौर (कानपुर) शामिल हैं. गंगा की निगरानी कर रही उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इकाई ने इन्हें चिन्हित करते हुए इनमें एसटीपी के लिए कोई योजना न बनाए जाने पर चिंता जताई है.

दरअसल, हाल में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के गठन के बाद गंगा नदी में पर्यावरण की दृष्टि से विकास की शर्त रखी गई है. बोर्ड अब तक गंगा में सीधे गिर रहे सीवेज पर ही नज़र रखता था. बोर्ड की मुख्य पर्यावरण अधिकारी डॉ. मधु भारद्वाज ने बताया कि छोटे एवं मंझोले शहरों के पुनरुत्थान के लिए बनी यूआईडीएसएसएमटी के तहत फर्रुखाबाद, मिर्ज़ापुर, मुगलसराय, गाज़ीपुर, सैदपुर, गढ़मुक्तेश्वर, बिजनौर, अनूपशहर एवं चुनार आदि में गंगा में सीधे गिर रहे सीवेज प्रबंधन के लिए योजनाएं बनकर स्वीकृत हैं. रिपोर्ट के मुताबिक़, बबराला (बदायूं) के दो नालों का दो मिलियन लीटर गंदा पानी (एमएलडी) प्रतिदिन वरद्धमार नदी में सीधे गिरता है, जो आगे चलकर गंगा में मिलती है. उझेनी (बदायूं) का आठ एमएलडी गंदा पानी गंगा से तीस किमी दूर स्थित तालाब में गिरता है, जो आगे नालों में मिलता है. गुन्नौर (बदायूं) के दो नालों का तीन एमएलडी गंदा पानी एक तालाब में गिरता है, जो आगे चलकर वरद्धमार नदी से होता हुआ गंगा में मिलता है. सोरों (एटा) के तीन नालों का चार एमएलडी गंदा पानी गंगा में सीधे नहीं गिरता, पर आगे चलकर उसमें ही मिलता है. बिल्हौर (कानपुर) के नालों का तीन एमएलडी सीवेज ईशान नदी में सीधे गिरता है. यह भी आगे चलकर गंगा में ही मिलता है.

सिब्बल बदलते परिवेश में इस तरह की व्यवस्था करना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को समय-समय पर बड़े भाई की तरह दिशा निर्देशित करने का काम करे.

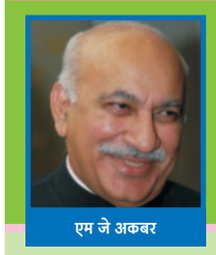

एम जे अकबर

देश की हालत की चिंता किसे है

रोमन साम्राज्य के सम्राट बस दो ही चीज़ों से डरते थे, असभ्य एवं अशिष्ट जनता और रोम के अंदर खाद्य पदार्थों की कमी. जनता पर नकेल कसने के लिए सेना की मदद ली जाती थी तो खाद्यान्नों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए ख़ुद राजा चौकन्ना रहता था. राजा को पता था कि भूखी जनता उसके शासन के लिए ख़तरनाक हो सकती है.

ईसा पूर्व 23 में रोम में खाने-पीने की चीज़ों की ज़बरदस्त कमी हो गई. इस दौरान अगस्ता ने अपने व्यक्तिगत कोष से खाद्यान्न ख़रीद कर लाखों रोमवासियों के बीच बांटा था. पहले से ही मशहूर रहे अगस्ता को इसके बाद रोमवासी और भी ज़्यादा भगवान की तरह मानने लगे. अगस्ता के उत्तराधिकारी तिबेरियस को आर्थिक मामलों की समझ कहीं ज़्यादा थी. ईस्वी सन् 19 में अन्न की कमी के चलते रोम में दंगे होने लगे तो तिबेरियस ने मूल्य वृद्धि पर रोक लगा दी और व्यापारियों को घाटे की भरपाई के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराई. लेकिन शरद पवार का मामला जरा अलग है. पवार की तरह किसी अन्य राजा ने अब तक ऐसा नहीं कहा है कि वह खाद्यान्नों के वितरण की समस्याओं से आजिज आ चुका है और इससे अच्छा काम तो आईसीसी (इंपीरियल कॉलेजियम सर्कस) को चलाना है. यह सही भी है, क्योंकि टी-20 की लगातार बढ़ती लोकप्रियता के बीच सट्टेबाज ज़्यादा से ज्यादा पैसा लगाने के लिए उतावले हो रहे हैं. क्रिकेट के इस सर्कस में आधे-अधूरे कपड़े पहने चीयरगर्ल्स हर गेंद के बाद अपनी भाव भंगिमाओं से मोहित करने की कोशिश में लगी रहती हैं, तो प्रायोजक मनमानी कीमतों पर मीटिंग के आयोजन के लिए हर समय तैयार रहते हैं.

सत्ता से चिपके रहकर अपनी जिम्मेदारियों से भागना सुखद स्थिति नहीं है. बढ़ते असंतोष के बीच यह लापरवाही चौंकाने वाली है. अपने दोबारा निर्वाचन को लेकर निश्चिंत रहने वाले नेता ही यह ख़तरा मोल ले सकते हैं. जनता को भरमाने के लिए विकास की तेज़ गति उनके लिए एक हथियार का काम करती है. पवार और

मुरली देवड़ा इन चिंताओं से दूर रहते हुए अपने पद पर बने रह सकते हैं. अगले चुनावों में अभी भी चार साल का समय बाकी है और यह बात तय है कि साल 2014 के मई महीने में जब मतदाता वोट देने के लिए बूथों पर जाएंगे तो तेल और अनाज की बढ़ी कीमतें उनके जेहन से दूर जा चुकी होंगी. नदी के आने से पहले उसे पार करने की चिंता का भला औचित्य क्या है?

रोमन साम्राज्य के राजा इतने हठीले नहीं थे. सिद्धांत रूप में वे मृत्युपर्यंत अपने पद पर बने रहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि मृत्यु कभी भी आ सकती है. किसी अंजाने दुश्मन का खंजर उनकी जीवन लीला को कभी भी समाप्त कर सकता है. वे यह भी जानते थे कि यदि शासन करने में सक्षम न हों तो राजा नहीं बने रह सकते. लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह विचारधारा पूरी तरह उल्टी हो गई है. यदि आप सत्ता में रहते हुए शक्तिहीन होने का कोई सामयिक उदाहरण देखना चाहते हैं तो श्रीनगर के हालत पर ग़ौर कीजिए. तेल की कीमतों में हुई वृद्धि के चलते दिल्ली में आयोजित बंद और श्रीनगर में कर्फ्यू के बीच क्या कोई समानता है? दोनों के हालात अलग-अलग हैं, लेकिन समस्या एक जैसी है, सरकार लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही.

ऐसा लगता है, जैसे सरकारें एक अहम पहलू से पूरी तरह बेख़बर हो चुकी हैं. यह पहलू है ख़रीदारों के पश्चाताप का. मतदाताओं के पास यह विकल्प तो नहीं है कि वे अपनी ख़रीदी हुई चीज लौटा दें, लेकिन उनका पश्चाताप सत्ता की साख में सुराख कर सकता है. पिछले साल जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल दोबारा अपने पद पर निर्वाचित हुईं. उनकी जीत इतनी ज़बरदस्त थी कि विपक्षी पार्टियां हाशिए पर चली गईं, लेकिन केवल नौ महीने के अंदर ही स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं. मर्केल का यूनाइटेड फ्रंट पंगु हो चुका है और 77 प्रतिशत से ज़्यादा जर्मन जनता को लगता है कि सत्ता पर सरकार का नियंत्रण ख़त्म हो चुका है. सत्ता का सूत्र बस एक वाक्य में ही छिपा है, स्थिति आपके नियंत्रण में है या कहीं आप ही तो स्थितियों से नियंत्रित नहीं हो रहे.

1971 में इंदिरा गांधी ने भारत के चुनावी इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल की. साल के अंत तक पाकिस्तान के साथ युद्ध में मिली जीत के बाद उन्हें देवी का अवतार घोषित कर दिया गया, लेकिन 1973 की गर्मियां आते-आते हालात आश्चर्यजनक रूप से बदल चुके थे. करिश्माई जॉर्ज फर्नांडीस ने देशव्यापी रेल हड़ताल कर पूरे देश को अस्थिर कर दिया, जबकि संन्यास से वापस लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण कौतूहल पैदा कर रहे थे. और यह तो सबको पता है कि लोगों के पश्चाताप का सबसे बड़ा कारण महंगाई ही था. लंगड़ाती हुई इंदिरा सरकार ने यह सोचकर आपातकाल का सहारा लिया कि विपक्ष पहले ही नेस्तनाबूद हो चुका है. लेकिन वह यह भूल गई थी कि सबसे ख़तरनाक विपक्ष राजनीतिक पार्टियां नहीं, बल्कि जनता का होता है.

यह बात अब क़रीब चार दशक पुरानी हो चुकी है, आतंकवादी हमारे दरवाज़े पर खड़े हैं, नक्सलवाद हमारे घर-आंगन तक पहुंच चुका है, महंगाई के चलते रसोई संकट में है और पाकिस्तान के साथ हमारा विवाद पूर्ववत बना हुआ है. नीरो सम्राट भले न हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि कृषि और खाद्य आपूर्ति का ज़िम्मा उसी के हाथों में है. शरद पवार पहले ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं, जिन्होंने यह सार्वजनिक रूप से क़बूल किया कि वह एक चुकी हुई शक्ति हैं. गनीमत यह है कि वह एक लंबी पारी खेल चुके हैं, लेकिन युवा नेताओं की नई पीढ़ी को उनसे सबक लेना होगा. यदि वे नहीं चेते तो गोदाम में ही सड़ते रह जाएंगे.

भारत की मौजूदा हालत बाज़ार के बीचोबीच स्थित किसी मल्टीप्लेक्स से मिलती-जुलती लगती है, जिसमें एक साथ कई फिल्में चल रही हैं. कश्मीर में हिंसक नाटक तो दिल्ली में उबाऊ तमाशा, तमिलनाडु में फैमिली सोप ओपेरा, जिसे देखकर बरबस ही आंसू निकल पड़ें तो पंजाब में यही फैमिली ड्रामा दूसरे अंदाज़ में चल रहा है, गुजरात में पुरानी फिल्मों की सीडी चल रही है तो बंगाल में डेविड और गोलिएथ की पौराणिक कहानी का नकली रूपांतरण चल रहा है, उत्तर पूर्व में कहानियों की कोई पटकथा ही नहीं है. सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश के कई हिस्सों में इस मल्टीप्लेक्स को चलाने वाले लोग ही बत्तियां बुझाकर चादर तान कर सो गए हैं. लेकिन इसकी फ़िक्र किसे है?

feedback@chauthiduniya.com

प्रयोग की जगह कमियों को दूर करने की पहल ज़रूरी

नए प्रयोग के ख़तरों के प्रति चिंता स्वाभाविक है. शिक्षा के मामले में ऐसे ख़तरे और भी संवेदनशील हो जाते हैं, लेकिन इन ख़तरों से अनभिज्ञ केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्री कपिल सिब्बल शिक्षा के क्षेत्र में विगत एक वर्ष से अपने प्रयोगों को जारी रखे हुए हैं. उनके लगातार सुधारात्मक प्रयोगों के लिहाज से नया शगूफा है आईआईटी की प्रतियोगिता परीक्षा में बदलाव लाना. वह चाहते हैं कि आईआईटी में दाख़िले के लिए 12वीं और राष्ट्रीय एप्टीट्यूड परीक्षा को आधार बनाया जाए. इसके तहत 70 फ़ीसदी मान 12वीं की परीक्षा का होगा और 30 फ़ीसदी राष्ट्रीय एप्टीट्यूड परीक्षा का. इस परिवर्तन को अमलीजामा पहनाने के लिए सिब्बल ने पहल कर दी है, लेकिन इस मुद्दे पर आईआईटी द्वारा गठित समिति की सिफ़ारिश आनी अभी बाक़ी है. इस बदलाव के पीछे सिब्बल का मक़सद कैपिटेशन फीस और कोचिंग के रैकेट को ख़त्म करना है.

इस कवायद का परिणाम सकारात्मक हो या नकारात्मक, किंतु इसके मूल में समस्या यह है कि फ़िलहाल सभी राज्यों में 12वीं के लिए एक समान सिलेबस नहीं हैं. ऐसे में सिब्बल का यह प्रयोग ख्याली पुलाव साबित हो सकता है, क्योंकि सभी राज्यों में 12वीं में एक समान सिलेबस लागू करना आसान काम नहीं है. इस बाबत एनसीआरटी के सिलेबस को लागू किया जा सकता है, लेकिन जब तक यह सिलेबस रोज़गारपरक नहीं होगा, तब तक इस मुद्दे पर राज्यों के बीच आम सहमति बनना आसान नहीं होगा. इसी क्रम में सिब्बल जल्द ही विदेशी संस्थान विधेयक भी लाने जा रहे हैं. उनका मानना है कि विदेशी संस्थान रोज़गारपरक शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. उनका इरादा 12वीं में वोकेशनल कोर्स की शुरुआत करने का भी है.

सिब्बल बदलते परिवेश में इस तरह की व्यवस्था करना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को समय-समय पर बड़े भाई की तरह दिशा निर्देशित करने का काम करे. इस संबंध में सार्वजनिक संपत्तियों का व्यवसायिक इस्तेमाल करके उसका उपयोग शिक्षा के प्रचार-प्रसार में करना सबसे अहम् मुद्दा है. चूंकि हर राज्य की अलग-अलग विशेषता होती है. इसलिए हर राज्य के लिए यह

प्रयोग अलग तरीक़े से किया जाना चाहिए, ताकि संसाधनों का अधिकतम दोहन किया जा सके. सिब्बल की अगुवाई में स्कूल-कॉलेजों में शिक्षण का कार्य सत्रों में करने की भी तैयारी चल रही है. दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में यह व्यवस्था लागू भी कर दी गई है. शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हमेशा से ही मांगपरक मुद्दा रहा है. बावजूद इसके हमारे लिए सुधार के साथ-साथ सभी को शिक्षित करना सबसे महत्वपूर्ण विषय होना चाहिए. अभी भी भारत में साक्षरता दर बहुत कम है. इसलिए हमें शहरों के साथ-साथ गांवों पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा.

वर्तमान में भारत में सकल नामांकन अनुपात मात्र 12.4 फ़ीसदी है. जबकि इसी संदर्भ में विश्व का औसत 25 फ़ीसदी और विकसित देशों का 50 फ़ीसदी है. पिछड़े देशों में यह औसत 6 फ़ीसदी है. इस तरह से देखा जाए तो इस मामले में हमारी स्थिति पिछड़े देशों के आसपास है.

लिहाज़ा आज देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि हमारे घर का हर बच्चा स्कूल जाए. फिलवक़्त भारतीय शिक्षा जगत कुशल और प्रशिक्षित अध्यापकों की भारी कमी से दो-चार हो रहा है. इस समय सरकारी स्कूलों में तक़रीबन 18 लाख शिक्षकों की ज़रूरत है. कुछ राज्यों में संविदा के आधार पर अध्यापकों को अवश्य बहाल किया गया है, परंतु संविदा पर नियुक्त शिक्षकों की तनख्वाह इतनी कम है कि वे चाहकर भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं.

हो सकता है कि राज्य सरकारें धन की कमी से जूझ रही हों, लेकिन शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता है और इसकी राह में हम धन की कमी को अड़चन नहीं बना सकते हैं. सर्वशिक्षा अभियान में केंद्र और राज्य सरकार को बिना किसी लाग-लपेट के एक-दूसरे का सहयोग करना चाहिए. तभी 100 प्रतिशत साक्षरता का संकल्प मूर्त्त रूप ले सकता है. हाल में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 6000 मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की थी. 6000 में से 3500 स्कूलों को अति पिछड़े इलाक़ों में खोलने का प्रस्ताव है और 2500 स्कूल कम पिछड़े इलाक़ों में. 2500 स्कूलों को सरकार निजी क्षेत्र के सहयोग से खोलेगी. इस व्यवस्था के अंतर्गत 1000 छात्रों को सरकार वज़ीफ़ा देगी और 1500 छात्रों को निजी निवेशक.

इसमें दो राय नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र का योगदान सकारात्मक रहा है फ़िलहाल अजीम प्रेमजी एवं भारती मित्तल शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. फिर भी इस दिशा में बहुत सारे सुधारों की ज़रूरत है. निजी स्कूलों की सबसे बड़ी समस्या है उनके द्वारा वसूल की जाने वाली फीस और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव. भारत में ग़रीबी का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है. लिहाज़ा शत-प्रतिशत साक्षरता का हमारा सपना तब तक साकार नहीं हो सकता, जब तक शिक्षा सर्वसुलभ न बन जाए. हमारा उद्देश्य नित नए प्रयोग करने के बजाय वर्तमान में चल रही समस्याओं से शिक्षा जगत को मुक्त कराना होना चाहिए. सरकार को ऐसी योजनाएं लागू करनी चाहिए, जिनसे सभी बच्चे स्कूल जाने के लिए प्रेरित हों. नए प्रयोगों से बच्चों की उलझन के पेंच और भी उलझ सकते हैं.

सतीश सिंह
feedback@chauthiduniya.com

मुद्दों पर चिंतन ज़रूरी

केंद्र और राज्यों में गठबंधन सरकारों का अब तक का अनुभव अच्छा नहीं रहा, लेकिन अब समय आ गया है कि मिली-जुली सरकारों का गठन हो, ताकि स्थायी तौर पर कम से कम पांच सालों तक सरकार काम करती रहे और बार-बार के उपचुनावों का बोझ जनता को न सहना पड़े. पक्ष और प्रतिपक्ष मिल-बैठकर देश की नीति और विकास की तरफ ध्यान दे सकेंगे. भ्रष्टाचार और दूसरे मुद्दों पर भी चिंतन हो, न कि एक-दूसरे पर कीचड़ उछाला जाए.

-शैलांचली, *ई-मेल से.*

पैसा कहां गया

पच्चीस सालों से भोपाल गैसकांड के शिकार परिवार अकेले लड़ाई लड़ रहे थे. कोई राजनीतिक दल उनके साथ नहीं खड़ा था. भाजपा तो बिल्कुल नहीं. अब भाजपाई मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वह गैस पीड़ितों के हितों की रक्षा करेंगे, पर भाजपा की सरकार तो पहले भी मध्य प्रदेश में रही है. उसने न ज्यादा मुआवजा दिलवाने या देने का फैसला लिया और न प्रभावित परिवार को मदद पहुंचाने का. आज दिल्ली में प्रकाश जावड़ेकर और भोपाल में शिवराज सिंह चौहान गैस पीड़ितों के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि कांग्रेस के मुकाबले भाजपा को राजनीतिक फायदा कैसे पहुंचे, इसके रास्ते तलाशते नजर आ रहे हैं. लेकिन पाप का घड़ा एक दिन फूटता जरूर है. भारत का कानून भले ही अंधा हो, किंतु विधाता की आंखें सब कुछ देख रही हैं. वही सबका मालिक है और उसका क़ानून अंधा नहीं है.

-महेश चंद्र वर्मा, *पत्रकार, इंदौर, मध्य प्रदेश.*

आश्चर्य है और ख़ुशी भी

कवर स्टोरी-देश के लोगों पर गोली नहीं चलाएंगे, पढ़कर आश्चर्य हुआ और खुशी भी. आश्चर्य इस बात पर कि देश में पुलिस की हालत इतनी खस्ता हो गई है कि आंतरिक समस्याओं से निपटने के लिए सेना की मदद की जरूरत पड़ रही है. खुशी की बात यह है कि सेना ने अपने विवेक से काम लेते हुए इसे अस्वीकार कर दिया. आख़िर सही भी है, जो सेना अपने देश के नागरिकों की रक्षा के लिए सीमा पर ज़िंदगी और मौत से लड़ती है, वह अपने ही देश के नागरिकों पर गोली कैसे चला सकती है.

-शेखर कुमार, *धौलपुर, राजस्थान.*

विषय चयन उम्दा

विषय चयन के लिहाज़ से अख़बार का कोई जवाब नहीं है. राजनीतिक खबरों से लेकर साहित्य, खेल और सिनेमा सभी कुछ मैं नियमित रूप से पढ़ता हूं. संपादकीय के विषय में विविधता रहती है. आशा है, आगे भी ऐसा ही अखबार पढ़ने को मिलता रहेगा.

-बृजेंद्र नाथ शुक्ला, *आगरा, उत्तर प्रदेश.*

प्रयास प्रशंसनीय

मैं आपके अख़बार का नियमित पाठक हूं. आपका प्रयास प्रशंसनीय है. आग्रह यह है कि राजनीति के अलावा बच्चों, युवाओं और कृषकों के बारे में भी आलेख छापिए, जिससे उन्हें अपनी बेहतरी के लिए मार्गदर्शन मिल सके. साथ ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पारित नए क़ानूनों की भी जानकारी दी जाए.

-अजहर हुसैन अंसारी, *मोतिहारी, बिहार.*

गद्दारों को फ़ांसी मिले

आज हमारे देश की सुरक्षा को सीधा ख़तरा बाहरी दुश्मनों से कम, अंदर के दुश्मनों से ज़्यादा है. अविवाहित आईएफएस अधिकारी माधुरी गुप्ता के ट्रैक रिकॉर्ड की पड़ताल किए बगैर उसे पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश में तैनात करने का क्या तुक था? गुप्त एवं संवेदनशील सैन्य ठिकानों की अहम जानकारियां कैसे लीक हो गईं? देश के गद्दारों को सीधे फ़ांसी पर चढ़ा देना चाहिए.

-अक्षय कुमार मिश्रा, *पुटकी बाज़ार, धनबाद, झारखंड.*

ईमानदार प्रयास के लिए बधाई

संतोष जी, सच्चाई का दामन मत छोड़िएगा, एक दिन आपकी जीत होगी.

-आशीष श्रीवास्तव, *ई-मेल से.*

हौसले को सलाम

चौथी दुनिया ने पिछले एक साल में समाज के नक़ाबपोशों को बेनक़ाब करने का जो काम किया है, वह क़ाबिलेतारीफ़ है. आपके हौसले को सलाम. उम्मीद है कि आपकी ईमानदारी और पारदर्शिता आगे भी बरक़रार रहेगी.

-सोनू सिंह, *बलिया, उत्तर प्रदेश.*

आप अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इसी पते पर भेजें.
संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

भाजपा को कौरव सभा बनने से बचाइए

आपको एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं, यह इतिहास का पन्ना है जिसका ज्ञान नितिन गडकरी को नहीं है. आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस छोड़ चुके थे और उन्होंने प्रजा समाजवादी पार्टी बनाई थी. पंडित संपूर्णानंद कांग्रेस में थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे. सवाल आया प्रजा समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र लिखने का. सभी को अंदाज़ा था कि आचार्य जी इसे स्वयं लिखेंगे. आचार्य जी की तबियत थोड़ी ख़राब थी. कुछ दिनों बाद आचार्य जी से उनके साथियों ने पूछा कि घोषणा पत्र लिखने का काम कहां तक पहुंचा तो आचार्य जी ने कहा कि उन्होंने संपूर्णानंद से कहा है और वह घोषणा पत्र लिख रहे हैं. आचार्य जी के साथी थोड़े चिंतित हुए, पर किसी ने आचार्य जी के फ़ैसले पर उंगली नहीं उठाई. तीन महीनों के बाद हाथ से लिखा काग़ज़ों का बंडल आचार्य जी के पास आया, जिसे पं. संपूर्णानंद ने भेजा था. आचार्य जी ने उसे देखा भी नहीं और सीधे प्रेस में छपने भिजवा दिया.

आचार्य जी के साथी चिंतित होकर उनके पास गए और कहा कि कम से कम एक बार देख तो लीजिए कि लिखा क्या है? आचार्य जी ने मुस्कराते हुए कहा कि संपूर्णानंद ने लिखा है, सब सही होगा और वही लिखा होगा, जो मैं लिखता. फिर ध्यान दिला दूं कि आचार्य नरेंद्र देव जी ने प्रजा समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र लिखने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संपूर्णानंद जी को सौंपा, जिसे उन्होंने स्वीकार किया और जो उन्होंने लिखा उसे बिना देखे, बिना कामा-फुलस्टाप बदले आचार्य जी ने छपने भेज दिया, जबकि दोनों राजनीतिक तौर पर परस्पर विरोधी दलों में थे.

अगर आज नितिन गडकरी से, जो संयोग से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, उनका कोई दोस्त अगर किसी दूसरी पार्टी में हो और ऐसा ही आग्रह करे तो नितिन गडकरी क्या करेंगे? आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए. एक तरफ आचार्य जी और संपूर्णानंद जी का राजनैतिक उदाहरण और दूसरी तरफ नितिन गडकरी का आज का उदाहरण. नितिन गडकरी की जानकारी के लिए इतिहास का एक और पन्ना उन्हें दिखाते हैं और ऐसे पन्नों की भरमार है, जिससे नितिन गडकरी अंजान हैं. श्री चंद्रभानु गुप्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे. उनके ख़िलाफ़ चंद्रशेखर और उनके साथियों ने लखनऊ में प्रदर्शन किया. नारे लगे, सी वी गुप्ता चोर है, गली-गली में शोर है. यूपी में हैं तीन चोर, मुंशी गुप्ता जुगल किशोर. शाम हुई, लगभग दस हज़ार प्रदर्शनकारी लखनऊ में थे और किसी के खाने का इंतजाम नहीं था. चंद्रशेखर अपने कुछ साथियों के साथ गुप्ता जी से मिलने गए. गुप्ता जी ने कहा, आओ भूखे-नंगे लोगों, इनको ले तो आए, अब क्या लखनऊ में भूखा रखोगे. चंद्रशेखर जी ने कहा कि आपका राज्य है, जैसा चाहें कीजिए. गुप्ता जी खीज गए, लेकिन कहा कि मैंने कह दिया है पूड़ी-सब्जी पहुंचती होगी. मैंने पहले ही समझ लिया था कि बुला तो लोगे, लेकिन खाने का इंतजाम नहीं कर पाओगे.

यह थी उस समय की राजनैतिक शिष्टता. अपने ख़िलाफ़ प्रदर्शन करने वालों को भी खाना खिलाने की शिष्टता. दल कोई भी हो, लेकिन राजनीति में रहने के कारण एक-दूसरे की इज़्ज़त. पर अब नितिन गडकरी ने एक नई शुरुआत कर दी है, भाषा की सभ्यता और भाषा की शिष्टता समाप्त कर दी है. शायद यह तो मोहन भागवत, एम जी वैद्य सहित संघ के नेता नहीं चाहते होंगे. संघ के लोगों ने नितिन गडकरी को अध्यक्ष बनाने के लिए दबाव डाला ज़रूर था, पर संघ का शिष्टाचार मशहूर है. बाला साहब देवरस और भाऊ देवरस से मुझे कई बार मिलने का मौक़ा मिला. निश्चल व्यक्तित्व था भाऊ देवरस का. बोलते थे तो लगता था कि निर्मल जल बह रहा है. आडवाणी जी को जानता हूं, अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद, सुशील मोदी की शिष्टता, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, सुषमा स्वराज का व्यवहार और मुरली मनोहर जोशी का आत्मीयपन नितिन गडकरी की भाषा से शर्मसार हो गया होगा. मुझे पूरा भरोसा है कि नितिन गडकरी की भाषा का अनुसरण ये सब कोशिश करके भी नहीं कर पाएंगे.

अटल जी, आडवाणी जी, जोशी जी और राजनाथ सिंह के बारे में मैं दावे से कह सकता हूं कि ये राजा भोज के समान हैं. इनके बारे में मैंने काफ़ी सख्त रिपोर्ट और टिप्पणियां लिखीं, लेकिन ये जब भी मिले, मुस्करा कर और अपनेपन से. अटल जी प्रधानमंत्री थे और बिहार चुनाव पर मेरी भाजपा को लेकर सख़्त रिपोर्ट छप रही थीं. अटल जी पटना में एक होटल की लॉबी में मिल गए, अपने आप मेरी ओर चलकर आए और मुस्करा कर कहा कि मैं आपकी रिपोर्ट बहुत ध्यान से पढ़ रहा हूं.

क्या नितिन गडकरी को इस बात का एहसास है कि उन्हें किसकी विरासत मिली है. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, कुशाभाऊ ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की परंपरा में उन्हें अध्यक्ष पद मिला है. उनसे पहले के चार अध्यक्षों को मैं जानता हूं. अटल जी, आडवाणी जी, जोशी जी और राजनाथ सिंह के बारे में मैं दावे से कह सकता हूं कि ये राजा भोज के समान हैं. इनके बारे में मैंने काफ़ी सख्त रिपोर्ट और टिप्पणियां लिखीं, लेकिन ये जब भी मिले, मुस्करा कर और अपनेपन से. अटल जी प्रधानमंत्री थे और बिहार चुनाव पर मेरी भाजपा को लेकर सख्त रिपोर्ट छप रही थीं. अटल जी पटना में एक होटल की लॉबी में मिल गए, अपने आप मेरी ओर चलकर आए और मुस्करा कर कहा कि मैं आपकी रिपोर्ट बहुत ध्यान से पढ़ रहा हूं.

भाजपा के ये सारे नाम राजनैतिक शिष्टता और स्नेह के उदाहरण हैं. शायद नितिन गडकरी को इनमें से किसी के पास बैठने का या राजनैतिक परंपरा जानने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन अभी वक़्त है कि वह जान लें. भारत जैसे बड़े देश की विपक्षी पार्टी का अध्यक्ष पद कितना गरिमामय और महत्वपूर्ण होता है, इसका अंदाज़ा उन्हें नहीं है. उन्होंने अपनी राजनैतिक समझ की कमी से झारखंड में भाजपा को इस हाल में पहुंचा दिया कि कहना पड़ गया कि भाजपा ने प्याज भी खाए और जूते भी. अब अपनी भाषा और व्यवहार व पब्लिक एपियरेंस से नितिन गडकरी भाजपा को आने वाले चुनावों में हाशिए की ओर ले जाने का काम करेंगे.

इसमें कोई दोराय नहीं कि नितिन गडकरी की भाषा से आकर्षित होकर असामाजिक तत्व और अशालीन वर्ग भाजपा की ओर आकर्षित होगा और चुनाव में दबंगई भी करेगा, पर क्या यही अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और मोहन भागवत का सपना है. हो सकता है आज मोहन भागवत और लालकृष्ण आडवाणी को पछतावा हो रहा हो, पर नितिन गडकरी के सिर चमेली का तेल महक रहा है. अभी शुरुआत है, मोहन भागवत, आडवाणी जी और जोशी जी को अभी हस्तक्षेप करना चाहिए, वरना भाजपा पर यह कलंक लगते देर नहीं लगेगी कि उसने राष्ट्रीय राजनीति में सहनशीलता, शिष्टता और सभ्यता के ख़ात्मे की शुरुआत करने में पहला क़दम रखा. भाजपा को कौरव सभा बनने से अपने को रोकना चाहिए, क्योंकि भाजपा कौरव सभा बने, यह हम कभी नहीं चाहेंगे. भारतीय राजनीति का यह सबसे दुखद दिन होगा, अगर भाजपा की तस्वीर कौरव सभा की तस्वीर में बदल जाती है.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

यूरोप में महिलाओं पर अत्याचार

अफ़्फ़ाफ़ अज़हर

बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, यूरोप और अमेरिका में रहने वाले दक्षिणी एशियाई ख़ानदानों में सैकड़ों महिलाएं ऐसी हैं, जिन्हें गुलामों की तरह रखा जाता है. हाल के दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें पर्दे में रहने वाली मुस्लिम महिलाओं को ब्याह कर पाकिस्तान लाया गया और गुलामों की ज़िंदगी जीने पर विवश किया गया. घर से बाहर निकलने पर पाबंदी, किसी से बातचीत पर पाबंदी, भाषा और समाज से बेख़बर रखकर सारे अधिकार छीन लिए गए. इतना ही नहीं, उन्हें उनके शौहर और ससुरालवालों की मारपीट भी सहन करने पर मजबूर कर दिया गया. कुछ साल इसी तरह गुज़ारने के बाद घर से भागने का मौक़ा मिलते ही हमदर्दों की मदद से मामला पुलिस की जानकारी में आया और पश्चिमी समाज में रहने वाली इस एशियाई महिला की अपमानजनक ज़िंदगी ने हर इंसान को हैरत में डाल दिया. बीबीसी की ओर से प्रकाशित दक्षिण एशियन संगठनों की विशेष रिपोर्ट के अनुसार, यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि आज भी सैकड़ों महिलाएं पश्चिमी देशों में रहते हुए भी पाकिस्तानी समाज की तरह अपने अधिकारों से वंचित और अत्याचार सहने पर मजबूर हैं और बेबसी-लाचारी की ज़िंदगी गुज़ार रही हैं.

महिलाओं पर हाथ उठाते हैं और ख़ुद को मर्द कहते हैं, ऐसे मर्दों को तो न कभी शर्म आई है और न कभी आएगी, मगर हर वह कोख ज़रूर शर्मिंदा होगी, जो ऐसे नामर्दों को धरती पर जन्म देने की ग़लती दोहराती चली आ रही है. यह किसी एक महिला की तौहीन नहीं, बल्कि हव्वा की बेटियों की तौहीन है. यह औरत की तौहीन है. जो रिश्तों का मतलब तक नहीं जानते, मगर रिश्तों पर हक़ जमाना चाहते हैं. औरत सिर्फ़ बीवी नहीं, किसी की मां, किसी की बेटी और किसी की बहन और सबसे बढ़कर एक औरत है. वह औरत, जो हमेशा सहमी रहे, हमेशा बेइज़्ज़त होती रहे और पति परमेश्वर का रूप लिए मर्द उसे कुचलता रहे, उसकी आवाज़ दबाता रहे, पैरों की जूती समझता रहे और औरत बदले में अंधा प्यार लुटाती रहे, मर्द को पूजती रहे. यही औरत है, जिसने ऐसे नामर्दों को ख़ुदा बना डाला है, जो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हैं.

मुस्लिम मर्द तो औरत के अधिकारों की सुरक्षा करने वाले माने जाते थे, मगर आज वही मुस्लिम मर्द औरत के अधिकारों पर काले नाग बनकर बैठ गए हैं. वे यह भूल गए हैं कि एक औरत जब प्यार लुटाने पर आती है तो ममता का रूप लेकर धरती पर छा जाती है, मगर जब वह अपने लुटे हुए अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने पर उतर आए तो उसे रज़िया सुल्ताना का रूप धरने में ज़्यादा देर नहीं लगती. औरत अगर मर्द की शक्ल में शैतान को जन्म दे सकती है, तो वही औरत ऐसे शैतान नामर्दों से लड़ने का हौसला भी रखती है. औरतें, जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी, सदियों से सिर्फ़ कुचला ही गया हो, उनका अत्याचार के सामने खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है. लेकिन यह भी एक अटल सच्चाई है कि अगर औरत का हौसला और धैर्य बहते दरिया का रुख़ मोड़ सकता है तो वही औरत जब बदला लेने पर आ जाए तो वह नागिन से कहीं ज़्यादा ज़हरीली साबित होती है. अगर औरत अपने घर की ख़ातिर हर क़ुर्बानी दे सकती है तो वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए दुश्मनों के प्राण भी ले सकती है. अगर आज हर औरत स्वयं अपने अधिकारों की सुरक्षा करने वाली बन जाए तो उस पर हाथ उठाने, उसके अधिकार छीनने वाले नामर्दों को भागने के लिए यह धरती भी कम पड़ जाएगी. अगर एक दीया जल जाए तो उससे हज़ारों दीये जलाए जा सकते हैं.

इसी तरह अगर एक औरत अपने अधिकार पहचान कर उसकी रक्षक ख़ुद बन जाए तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदला जा सकता है. ऐसे मर्दों के आगे सिर झुकाकर ख़ामोशी से अधिकार लुटाने की बजाय सिर उठाने की हिम्मत पैदा करनी होगी. इतिहास गवाह है कि अगर औरत इरादा कर ले तो उसे बदलना असंभव होता है. आज अगर किसी औरत को घर में पीटा जाता है, क़ैदियों की तरह रखा जाता है तो कल यह किसी दूसरी औरत के साथ भी हो सकता है. यह सिर्फ़ औरत की ज़िल्लत का सवाल नहीं, बल्कि औरत से जुड़े हर रिश्ते की तौहीन है, जिसका समाधान हमारे समाज में सदियों से छिने हुए औरत के तमाम अधिकार वापस देकर ही मुमकिन होगा.

जब तक औरत ख़ुद नहीं जागेगी, उसे अत्याचार से छुटकारा नहीं मिलेगा. जब तक औरत हिंसा बर्दाश्त करना नहीं त्यागती, उस पर उठते हाथों को तोड़ा न जा सकेगा. अपने अधिकारों की पहचान की छोटी सी चिंगारी ही काफ़ी है, ऐसे मर्दों के तख्त को जलाने के लिए. ज़रा सोचिए कि आज एक औरत किसी न किसी तरह भाग कर ज़ुल्म से बच गई, मगर उन औरतों का क्या होगा, जो आज भी ऐसे ही पिट रही हैं, वंचित हो रही हैं, चूल्हों में भस्म हो रही हैं. ग़ैरत और इज़्ज़त के नाम पर कट-मर रही हैं, बदले में कुर्बान हो रही हैं. रस्मोरिवाज के नाम पर सती की जा रही हैं, कौन बचाने आएगा इन्हें? जब तक औरत ख़ुद ऐसे अत्याचार पर ख़ामोशी की बजाय आवाज़ नहीं उठाएगी, यह सिलसिला बंद नहीं होगा. औरत कोई बच्चे पैदा करने वाली मशीन नहीं, दो वक़्त की रोटी तो किसी जानवर को भी मिल जाती है, लेकिन इस दो वक़्त की रोटी के लिए हमारे समाज की औरत कब तक ज़ुल्म की चक्की में पिसती रहेगी? आख़िर कब तक वह अत्याचार सहती रहेगी? क्या एक औरत को सम्मान के साथ जीने का कोई हक़ नहीं?

मैं भलीभांति जानती हूं कि एक औरत को हज़ारों तरह के ख़ौफ़ से दो-चार होना पड़ता है और एक डर यह भी होता है कि घर की चाहरदीवारी में कौन बचाने आएगा? बाद में उसका क्या होगा? मगर सच तो यही है कि यही डर, यही ख़ौफ़ एक औरत का सबसे बड़ा दुश्मन है. मार डालिए इस ख़ौफ़ को, कुचल डालिए ऐसी बुज़दिलाना सोच को. अगर औरत डरना और ख़ौफ़ज़दा होना छोड़ दे तो दुनिया की कोई ताक़त उसे डरा नहीं सकती. फिर ऐसे नामर्दों से क्या डरना, जो औरतों पर हाथ उठाएं, उनके अधिकार छीने. हमारे समाज में औरत सदियों से ज़ुल्म की चक्की में पिसती चली आ रही है, मगर उसमें आज भी इतना दम है कि वह ज़ालिमों को कुचल सके. हर वह हाथ तोड़ सके, जो उसके वजूद, उसकी इज़्ज़त पर उठे. अगर औरत मर्द को ख़ुदाई के तख्त पर बैठा सकती है तो वही उस तख्त की बुनियाद हिलाना भी जानती है.

बंद कीजिए यह तमाशे देखना और इस तरह एक तमाशा बनकर जीना. अगर आज भी पूर्व की औरतों ने अत्याचार के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई तो इस समाज में हव्वा की बेटियां इज़्ज़त और अधिकारों की जंग हारेंगी और आने वाली कई नस्लें अपना वजूद खो देंगी. ज़ुल्म करने से बड़ा गुनाह उस ज़ुल्म को ख़ामोशी से बर्दाश्त करना है और सदियों की इस गंभीर ख़ामोशी और बेकार के सब्र ने आज तक अत्याचार को बढ़ाया ही तो है!

दुनिया में उस सा कोई मुनाफ़िक़ नहीं कतील,
जो ज़ुल्म तो सहता है, बग़ावत नहीं करता.

मुस्लिम मर्द तो औरत के अधिकारों की सुरक्षा करने वाले माने जाते थे, मगर आज वही मुस्लिम मर्द औरत के अधिकारों पर काले नाग बनकर बैठ गए हैं. वे यह भूल गए हैं कि एक औरत जब प्यार लुटाने पर आती है तो ममता का रूप लेकर धरती पर छा जाती है, मगर जब वह अपने लुटे हुए अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने पर उतर आए तो उसे रज़िया सुल्ताना का रूप धरने में ज़्यादा देर नहीं लगती. औरत अगर मर्द की शक्ल में शैतान को जन्म दे सकती है, तो वही औरत ऐसे शैतान नामर्दों से लड़ने का हौसला भी रखती है. औरतें, जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी, सदियों से सिर्फ़ कुचला ही गया हो, उनका अत्याचार के सामने खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है. लेकिन यह भी एक अटल सच्चाई है कि अगर औरत का हौसला और धैर्य बहते दरिया का रुख़ मोड़ सकता है तो वही औरत जब बदला लेने पर आ जाए तो वह नागिन से कहीं ज़्यादा ज़हरीली साबित होती है.

feedback@chauthiduniya.com

क़रीब 150 वर्ष पुराने इस मंदिर की देखरेख कामेश्वर न्यास बोर्ड के अधीन है. कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना दरभंगा के राजा ने की थी.

आपके सवाल, हमारा सुझाव

चौथी दुनिया ने जगाई उम्मीद की किरण

मैं एक बीमार महिला हूं. मेरा बेटा झारखंड के जबल गोडा बीसीसीएल अस्पताल में डॉक्टर है. नाम है मज़हर अहमद ख़ां. वह इलाज की खातिर मुझे अस्पताल ले जाने के लिए महीने में दो बार आता है. हम लोग भुवनेश्वर में रहते हैं. बेटे ने बहुत कोशिश की कि उसे सरकारी क्वार्टर मिल जाए और वह मुझे अपने पास रखे, देखभाल करे, लेकिन डेढ़ साल हो गया, सरकारी क्वार्टर नहीं मिला. वह एक होटल में चार हज़ार रुपये प्रतिमाह किराया देकर रहता है. होटल से 15 किलोमीटर आने-जाने और ख़ासकर रात की पाली में बहुत परेशानी होती है. वह अपनी गाड़ी लेकर भी नहीं जा सकता, क्योंकि गाड़ी रखने की जगह नहीं है. इतनी परेशानी उठाने के बावजूद सरकारी क्वार्टर का किराया कट रहा है. अधिकारी पिछले छह माह से बिना क्वार्टर दिए किराया काट रहे हैं. आख़िर यह कहां का इंसाफ़ है? बेटा कहता है कि सभी अफसरों से कह चुका हूं, अर्जी दे चुका हूं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं. एक उम्मीद की किरण जागी है आपका आरटीआई कॉलम देखकर. क्या करूं, मुझे कोई रास्ता बताइए? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आरटीआई वाले न फॉर्म देते हैं और न कुछ सुनते हैं.

***डॉक्टर एम एस ख़ान की मां,** कनन विहार फेस-1, भुवनेश्वर, उड़ीसा.*

आपने हमारे अख़बार के प्रति जो विश्वास दिखाया है, उसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं. चौथी दुनिया आपको विश्वास दिलाता है कि आपके बेटे को इंसाफ़ ज़रूर मिलेगा. हमारी राय है कि सबसे पहले स्थानांतरण के संबंध में जो सरकारी नियम हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल करें. जैसे, क्या बीमार मां की देखभाल के नाम पर स्थानांतरण हो सकता है या नहीं? यदि हां, तो फिर आपके मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर आपका बेटा स्थानांतरण के लिए पहले एक साधारण आवेदन कर सकता है. उसके 10-15 दिनों बाद आरटीआई आवेदन के ज़रिए स्थानांतरण हेतु दिए गए आवेदन के बारे में सवाल पूछ सकता है. मसलन स्थानांतरण के आवेदन पर विभाग ने क्या कार्यवाही की है. इसके अलावा क्वार्टर आवंटित हुए बिना किराया काटे जाने के संबंध में भी अलग से आवेदन करके वांछित जानकारी हासिल की जा सकती है. आरटीआई के लिए किसी ख़ास फॉर्म की ज़रूरत नहीं होती. आप सादे काग़ज़ पर भी विभाग के लोक सूचना अधिकारी के नाम आवेदन कर सकते हैं. आपकी सहूलियत के लिए हम इस अंक में स्थानांतरण के संबंध में आरटीआई आवेदन का प्रारूप प्रकाशित कर रहे हैं. उम्मीद है, आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगी. आरटीआई क़ानून का इस्तेमाल करने के दौरान अगर आपके सामने किसी भी तरह की दिक़्क़त आए तो आप हमें ई-मेल, फोन या पत्र के ज़रिए बता सकती हैं. हम आपकी समस्या के समाधान के लिए पूरी कोशिश करेंगे.

एआईईई में ओबीसी सर्टिफिकेट

मेरा एआईईई में ऑल इंडिया रैंक 21217 है. दाख़िले के समय एसडीओ द्वारा जारी ओबीसी सर्टिफिकेट की मांग की गई. मैंने अंचलाधिकारी द्वारा जारी सर्टिफिकेट जमा किया, लेकिन मुझे दूसरे राउंड में भी कोई सीट नहीं मिली. मुझे एसडीओ से सर्टिफिकेट बनवाने के लिए समय तक नहीं दिया गया. अब मुझे क्या करना चाहिए?

***धनंजय,** ई-मेल से.*

सबसे पहले तो आप ख़ुद यह स्पष्ट कर लें कि प्रवेश प्रक्रिया के लिए जो भी नियम हैं, क्या इनके मुताबिक़ सिर्फ़ एसडीओ द्वारा जारी ओबीसी सर्टिफिकेट ही मान्य है या अंचलाधिकारी की भी चर्चा उक्त नियम में है या इस संबंध में कोई स्पष्ट नियम है ही नहीं. अगर साफतौर पर एसडीओ द्वारा जारी सर्टिफिकेट की मांग की जा रही है, तब तो कुछ ख़ास नहीं किया जा सकता. अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है तो आप इस संबंध में आरटीआई क़ानून का इस्तेमाल कर एआईईई से संबंधित अधिकारियों से इसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं. इसके अलावा आप यह भी पूछ सकते हैं कि क्या ऐसी परिस्थितियों में अभ्यर्थी को अतिरिक्त समय दिया जा सकता है या नहीं.

आंगनवाड़ी में नियुक्ति

मैंने आंगनवाड़ी सेविका की नियुक्ति के संबंध में कुछ सवाल पूछे थे और 7 दिसंबर 2009 को अपना आरटीआई आवेदन लोक सूचना अधिकारी के पास जमा कराया था, लेकिन मुझे अब तक कोई सूचना नहीं मिली. इसके आगे अब मुझे क्या करना चाहिए?

***पंकज कुमार,** रोसड़ा, समस्तीपुर.*

ऐसी स्थिति में प्रथम अपील ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन आपने काफी देर कर दी है. आरटीआई क़ानून के मुताबिक़ प्रथम अपील आवेदन करने के 30 दिनों के बाद और 60 दिनों के भीतर ही दाख़िल की जा सकती है. चूंकि समय सीमा ख़त्म हो चुकी है, ऐसे में सुझाव यह है कि आप एक बार फिर से अपना आरटीआई आवेदन उक्त लोक सूचना अधिकारी के पास जमा करें. इसके बाद 30 दिनों तक इंतज़ार करें. अगर कोई जवाब नहीं मिलता है तो तुरंत प्रथम अपील करें. हमने चौथी दुनिया के पिछले अंक में प्रथम अपील का प्रारूप प्रकाशित किया था. आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. वैसे हर विभाग में जहां लोक सूचना अधिकारी होता है, वहीं एक वरिष्ठ अधिकारी प्रथम अपील अधिकारी के रूप में भी नियुक्त होता है. आप अपनी अपील वहीं जमा कर सकते हैं.

डॉक्टर नहीं आता

मैं थाना परसौनी, ज़िला सीतामढ़ी का निवासी हूं. मेरे यहां के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर का कोई अता-पता नहीं रहता. अगर कभी वह मिलते भी हैं तो दवा नहीं देते और इनका बर्ताव भी ठीक नहीं रहता. वह मरीज को अपने क्लीनिक का पता बताने लगते हैं. कृपया मेरे नाम का खुलासा न करें.

सीतामढ़ी से एक पाठक.

सबसे पहले आपको बहुत-बहुत बधाई, क्योंकि आपने एक जागरूक पाठक और ज़िम्मेदार नागरिक का फ़र्ज़ निभाते हुए चौथी दुनिया पर विश्वास करके यह जानकारी दी. ऐसे डॉक्टरों के इलाज के लिए सबसे बेहतरीन दवा आरटीआई है. आप अपने नाम से न सही, किसी अन्य के नाम से एक आरटीआई आवेदन देकर (मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन कार्यालय में) उक्त डॉक्टर के संबंध में कुछ सवाल पूछें. मसलन अस्पताल में उपस्थिति रजिस्टर, इनके अवकाश, दवा वितरण एवं टीकाकरण के संबंध में सवाल पूछे जा सकते हैं. हमें उम्मीद है कि डॉक्टर साहब को जैसे ही इस आवेदन के बारे में पता चलेगा, वह न सिर्फ़ नियमित रूप से समय पर अस्पताल आना शुरू कर देंगे, बल्कि इनका व्यवहार भी सुधर जाएगा. कोशिश करें कि इस तरह के 5-10 आवेदन अलग-अलग लोग अपने नाम से जमा कराएं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा
(गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

आरटीआई आवेदन का प्रारूप (स्थानांतरण के लिए)

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय का नाम...
पता...

दिनांक...

विषय : सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत आवेदन

महोदय,

मैंने अपने स्थानांतरण के संबंध में एक आवेदन पत्र आपके विभाग में जमा कराया था (पूर्व में आपने जो साधारण आवेदन किया था, उसकी एक प्रति संलग्न करें), लेकिन अब तक उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. कृपया इस संबंध में मुझे निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं :

1. मेरे आवेदन पत्र पर हुई कार्रवाई की दैनिक प्रगति रिपोर्ट की
   एक सत्यापित प्रति उपलब्ध कराएं.
2. उन अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम और पदनाम बताएं, जिनके पास मेरा आवेदन इस दौरान रहा. कृपया यह बताएं कि किन-किन अधिकारियों /कर्मचारियों के पास कितने वक्त तक मेरा आवेदन रहा और उन अधिकारियों/ कर्मचारियों ने उस पर क्या कार्रवाई की?
3. मेरा आवेदन एक अधिकारी/कर्मचारी से दूसरे अधिकारी /कर्मचारी को जब-जब प्रेषित किया गया या प्राप्त किया गया, उसका प्रमाण उपलब्ध कराएं.
4. आपके विभाग के नियम/कानून/आदेश/दिशानिर्देश के मुताबिक ऐसे मामलों का निपटारा कितने दिनों के भीतर हो जाना चाहिए. उस नियम/ कानून /आदेश/ दिशानिर्देश की एक सत्यापित प्रति उपलब्ध कराएं.
5. यदि अधिकारियों/कर्मचारियों ने मेरे आवेदन का निपटारा उक्त नियम/कानून/आदेश/दिशानिर्देश के तहत नियत समय के भीतर नहीं किया है तो क्या उक्त अधिकारी/कर्मचारी संबंधित नियम/ कानून/ आदेश/ दिशानिर्देश के उल्लंघन के लिए दोषी हैं?
6. उन अधिकारियों/कर्मचारियों के रवैये की वजह से मुझे मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा. क्या उक्त अधिकारी/कर्मचारी मेरे मानसिक शोषण के लिए दोषी हैं?
7. उन अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने उक्त सभी नियम/ कानून/ आदेश/ दिशानिर्देश का उल्लंघन किया है और जिसकी वजह से मुझे मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा? कब तक उन अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी?
8. मेरे आवेदन का निपटारा कब तक हो जाएगा?

मैं इस आवेदन के साथ दस रुपये का आवेदन शुल्क जमा कर रहा/रही हूं.

भवदीय
हस्ताक्षर...
नाम...
पता...

ज़रा हट के

थूको और पुरस्कार पाओ

अमेरिका में एक दंपत्ति बहुत दूर तक थूकने के लिए मशहूर है. दूर तक थूकने वाली प्रतियोगिता में वह कई बार विजेता भी बन चुका है. यह एक ऐसा अनोखा मुक़ाबला है, जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसी भी प्रतियोगिताएं होती हैं. भारत में भले ही इस तरह की प्रतियोगिता नहीं होती, लेकिन विदेशों में ख़ूब होती है. मिशीगन में आयोजित दूर तक थूकने वाले इस मुक़ाबले में मियां-बीवी ने एक बार फिर सबको पीछे छोड़ दिया. इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को पहले फल खिलाया जाता है, उसके बाद उससे फल के बीज को थूकने के लिए कहा जाता है.

इस दंपत्ति ने फल खाने के बाद बीज 51 फुट दूर थूक दिया. दूर तक थूकने के मुक़ाबले में रिक और उनकी पत्नी मारलेना ने दो ट्रॉफियां हासिल कीं. प्रतियोगिता को चेरी पिट स्पिटिंग यानी चेरी फल की गुठली थूकने का मुक़ाबला कहा जाता है. पुरुषों के मुक़ाबले में रिक ने चेरी खाई और गुठली 51 फुट तीन इंच दूर थूकी. यानी क़रीब 16 मीटर दूर. लंबी दूरी तक थूकने के लिए मशहूर हो चुके रिक की यह 16वीं खिताबी जीत है. रिक की पत्नी मारलेना ने भी कोई कम कमाल नहीं दिखाया. महिलाओं के वर्ग में उन्होंने चेरी की गुठली 34 फुट छह इंच दूर थूकी. मारलेना की यह सातवीं खिताबी जीत रही. पहली बार यह प्रतियोगिता 37 साल पहले हुई थी. तबसे हर साल इसका आयोजन होता है. वर्तमान में यह मुक़ाबला अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड समेत कई देशों में लोकप्रिय हो रहा है. मौजमस्ती और ठीकठाक पुरस्कार मिलने की वजह से लोग बड़ी संख्या में इसकी तरफ़ आकर्षित हो रहे हैं.

भगवान के आगे अर्जी!

बिहार के दरभंगा ज़िले में एक ऐसा मंदिर है, जहां लोग वहां की दीवारों पर अपनी दिक़्क़तें एवं मनोकामना लिख आते हैं और भगवान उनकी इस अर्जी पर सुनवाई भी करते हैं. लोगों के इस अटूट विश्वास के कारण मंदिर की दीवारें अर्जियों से हमेशा पटी रहती हैं. दरभंगा के मोतीमहल के वाजाबाद क्षेत्र में स्थित महावीर मंदिर के बारे में मान्यता है कि जो लोग यहां की दीवारों पर लिखकर अपनी मनोकामना या परेशानी ईश्वर को बताते हैं, उस पर वह ज़रूर सुनवाई करते हैं. इसलिए लोग इसे मनोकामना मंदिर भी कहते हैं.

क़रीब 150 वर्ष पुराने इस मंदिर की देखरेख कामेश्वर न्यास बोर्ड के अधीन है. कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना दरभंगा के राजा ने की थी. मंदिर के पुजारी ध्रुवकांत झा ने बताया कि यहां प्रतिदिन 300 से ज़्यादा लोग सिर्फ़ अपनी मनोकामना लिखने के लिए आते हैं. महावीर जयंती एवं रामनवमी के अलावा प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को आने वाले भक्तों की संख्या काफी अधिक होती है. वह बताते हैं कि यहां भक्त सभी तरह की मनोकामनाओं के लिए आते हैं, लेकिन विवाह से संबंधित और पुत्र की चाह रखने वाले लोगों की संख्या अधिक होती है. मनोकामना पूरी होने के बाद वे पुन: महावीर मंदिर आते और श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं. दरभंगा के प्रकाश कुमार बताते हैं कि इस मंदिर में मांगी गई मुराद कभी अधूरी नहीं रहती.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

दिल्ली, 26 जुलाई -1 अगस्त 2010

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
दिल से जुड़े मामले में ख़ुशी एवं शांति मिलेगी. पार्टनर से जुड़ी कोई ख़बर आपको खुश कर देगी. स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतने की ज़रूरत है. जमीन-जायदाद से जुड़े मामले स्वास्थ्य पर असर डालेंगे. सप्ताह शुरू होने के साथ ही यात्रा से जुड़े मामले सुलझने लगेंगे.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
व्यवसायिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार आएगा. वित्तीय प्रगति अच्छी रहेगी और आपको कई फ़ायदे देगी. स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा. अचानक कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है. दांपत्य संबंधों में सुधार होगा. कुछ समय से पड़े कार्य पूरे हो जाएंगे, जिससे आपको ख़ुशी होगी.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
व्यवसाय में बदलाव आएंगे और आप निवेश की दिशा में नई योजना बनाएंगे. यात्रा फ़ायदे से भरपूर रहेगी और आपका स्टेट्स बढ़ाएगी. पूंजी निवेश से हानि की आशंका है. मानसिक तनाव एवं शारीरिक कष्ट महसूस करेंगे.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
इस सप्ताह महत्वपूर्ण कार्यों में बाधाएं एवं रुकावटें आएंगी. परिवार में तनाव उत्पन्न हो सकता है. आर्थिक क्षेत्र में किया जा रहा प्रयास सफल साबित होगा. पेट संबंधी शिक़ायत हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान अवश्य दें.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
किसी यात्रा पर जाएंगे तो वह आपके लिए सफल साबित होगी. अपने सामान के प्रति सचेत रहें. मांगलिक कार्यों के लिए किया जा रहा प्रयास सफल होगा. संतान के संबंध में कोई सुखद समाचार मिल सकता है. सुख-सुविधा का सामान ख़रीद सकते हैं.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
शांति की चाहत में आप मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं. किसी विवाद के चलते कोई महत्वपूर्ण योजना छोड़नी पड़ सकती है. यात्रा के दौरान उम्मीद से थोड़ा कम फ़ायदा होगा. पारिवारिक समस्याओं के समाधान में सभी का सहयोग मिलेगा.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
आपके काम और काबिलियत की सराहना होगी. कई चीजों पर ज़्यादा ख़र्च होगा. किसी अधीनस्थ कर्मचारी या सहयोगी का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत हो सकती है. व्यय पर नियंत्रण बनाए रखें.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
व्यवसायिक मामलों में यह एक्शन लेने का समय है, जो आपके लिए कई ख़ुशियां लाएगा. आप कुछ पैसा जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों पर भी ख़र्च करेंगे. बिना वजह की बातों पर ध्यान न देने से आपसी झगड़े निपटाने में मदद मिलेगी.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
ये सप्ताह आगे बढ़ने के साथ व्यवसायिक स्थिति में सुधार आएगा. कई नए अवसर मिलेंगे. जायदाद से जुड़े मामलों पर ख़र्च होगा. किसी नज़दीकी शख़्स का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
व्यवसायिक जीवन में धीरे-धीरे सुधार आएगा. आप दूसरे के विचारों को सुनेंगे, लेकिन अपने दिल की आवाज़ पर भी ध्यान देंगे. आपको कई ऐसी जगहों से मदद मिलेगी, जो आपकी कल्पना से बाहर की होंगी.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
ग़लतफहमी से आप कुछ दिक़्क़तों हो सकते हैं. ईमानदारी के रास्ते पर चलने से आपको मेहनत का फल मिलेगा. पिता समान किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का कारण बनेगा. कड़ी मेहनत के साथ-साथ आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
आप विरोधियों को मात देने में कामयाब रहेंगे, लेकिन चौकन्ना रहें. इस हफ्ते दो प्रोजेक्ट आपके लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं. परिवार के किसी छोटे सदस्य पर ख़र्च हो सकता है. भावनात्मक समस्याओं के चलते परिवार में झगड़ा हो सकता है.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

आज़ादी के बाद से ही भारत और पाकिस्तान की जनता दोनों सरकारों को सुन रही है. दिल्ली से कहा जाता है कि पाकिस्तान आतंकियों को भारत विरोधी गतिविधियों में मदद कर रहा है.

भारत-पाक वार्ता

बातचीत का यह कैसा तरीक़ा है

मनीष कुमार

यह अजीबोग़रीब स्थिति है कि एक आतंकी की वजह से न्यूक्लियर शक्ति से लैस दो देश आपस में अपने रिश्ते ख़राब करने पर आमादा हैं. यह किस तरह की डिप्लोमेसी है कि दोनों देश के महान राजनयिक उसी निर्णय पर पहुंच जाते हैं, जो दोनों देशों में आतंक फ़ैलाने वाले आतंकी चाहते हैं. लश्कर-ए-तैय्यबा हो या फिर अलक़ायदा, दोनों ही संगठन यह चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान आपस में लड़ते रहें. आतंक के ख़िलाफ़ कभी एक दूसरे से हाथ न मिला सकें. हाल में हुई भारत-पाकिस्तान वार्ता का असफल होना इस बात का सबूत है कि दोनों देशों की सरकारों की प्राथमिकता रिश्ते सुधारना नहीं है. अब सवाल यह है कि क्या हाफ़िज़ सईद इतना महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से परमाणु हथियारों से लैस दो देश संवादहीनता की स्थिति में आ जाएं. पाकिस्तान की मज़बूरियां जगज़ाहिर हैं. सरकार का दायरा सिमट चुका है. पाकिस्तान का ज़्यादातर इलाक़ा, वहां चल रहे आतंकी संगठन सरकार की पहुंच से बाहर हैं. इसके बावजूद अगर भारत अपनी जगह पर अड़ा रहता है तो इसका क्या मतलब है?

भारत के विदेश मंत्री एस एम कृष्णा जब पाकिस्तान के लिए रवाना हुए तो उनके सामने एक लक्ष्य था, भारत-पाकिस्तान के बीच परस्पर विश्वास को बढ़ाना, दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की बातचीत को आधार बनाकर रिश्तों में आए तनाव को कम करना. विदेश मंत्री के साथ विदेश मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी भी थे. पाकिस्तान जाने से पहले विदेश मंत्री एस एम कृष्णा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गृहमंत्री पी चिदंबरम और रक्षा मंत्री ए के एंटनी के बीच बातचीत हुई. इस बैठक में यह तय हुआ कि अलग-अलग मुद्दों पर भारत का स्टैंड क्या होगा. इस बैठक का ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि बातचीत असफल हो गई. दोनों देश अपना-अपना राग अलापते रहे और हालत यह हो गई कि प्रेस कांफ्रेंस में दोनों देशों के महान विदेश मंत्री दुनिया के सामने आपस में ही लड़ते नज़र आए.

भारत-पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की वार्ता का सिर्फ़ एक ही नतीजा निकाला जा सकता है कि दोनों देशों की सरकारों ने यह फ़ैसला कर लिया है कि रिश्ते सुधरें या न सुधरें, हम सिर्फ़ बातचीत करने के लिए बातचीत करते रहेंगे. कभी इस्लामाबाद में तो कभी नई दिल्ली में. दोनों देशों के राजनयिकों के बीच सात घंटे तक बातचीत हुई. जब वे बाहर निकले तो अपने-अपने देशों के मीडिया को गोपनीय जानकारियां देने में जुट गए. देश की जनता के सामने इस बातचीत की पूरी सच्चाई सामने आ गई. दोनों देशों के राजनयिक वार्ता के असफल होने की ज़िम्मेदारी एक दूसरे पर मढ़ने लगे. क़ैदियों, ख़ासकर मछुआरों का मामला हो या फिर पीपुल-टू-पीपुल कांटैक्ट, वीजा, कश्मीर के दोनों हिस्सों के बीच व्यापार, बस और रेल सेवाएं आदि मुद्दों को इस बातचीत के दौरान भुला दिया गया. जो जनता से जुड़े मुद्दे थे, उन विषयों पर दोनों पक्षों के राजनयिकों ने चुप्पी साध ली. बातचीत के बाद दोनों विदेश मंत्रियों ने मिलकर प्रेस कांफ्रेंस की. उसे देखकर यह लगा कि ये कोई राजनयिक नहीं, बल्कि भारत-पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जो मैच के आख़िरी ओवरों में उत्तेजित और व्याकुल नज़र आते हैं.

वार्ता के दौरान पाकिस्तान ने आतंकवाद के ख़िलाफ़ संयुक्त मोर्चे पर फिर से बातचीत शुरू करने की पेशकश की, जिसे मुंबई हमले के बाद बंद कर दिया गया था. भारत का मानना है कि वह सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन पहले पाकिस्तान की सरकार को हाफ़िज़ सईद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी होगी.

भारत का मानना है कि मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैय्यबा के संस्थापक हाफ़िज़ सईद को सज़ा दिए बग़ैर रिश्ते नहीं सुधर सकते. भारत कई बार कह चुका है कि हाफ़िज़ सईद पाकिस्तान में बैठकर भारत के ख़िलाफ़ ज़हर उगलता है, लेकिन सरकार उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करती. इस वार्ता के दौरान भी हाफ़िज़ सईद का मुद्दा उठा, लेकिन पाकिस्तान का जो जवाब आया, वह चौंकाने वाला था. पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत के गृह सचिव जी के पिल्लई की तुलना हाफ़िज़ सईद से कर दी. उन्होंने कहा कि जिस तरह हाफ़िज़ सईद बयान देते हैं, वैसा ही बयान जी के पिल्लई ने भी दिया कि भारत में आतंकवादी हमलों में पाकिस्तान की ख़ुफ़िया एजेंसी आईएसआई का हाथ है. हैरानी की बात यह है कि यह सब दुनिया भर के मीडिया के सामने हुआ. इस प्रेस कांफ्रेंस को टीवी पर लाइव दिखाया जा रहा था. दोनों राजनयिकों ने इसकी भी परवाह नहीं की और दुनिया के सामने आपस में सवाल-जवाब करने लग गए. दोनों के हाव-भाव बदल गए. एक ही झटके में भारत-पाकिस्तान के बीच अमन की आशा का गला घोंट दिया गया.

बातचीत विफल इसलिए भी हुई, क्योंकि पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर के मुद्दे को उठाया. पाकिस्तान का मानना है कि कश्मीर में जिस तरह सेना कार्रवाई कर रही है और जिस तरह मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, उससे वह चिंतित है. जबकि भारत का कहना है कि यह भारत का आंतरिक मामला है, इस पर पाकिस्तान को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. भारत-पाकिस्तान वार्ता का तीसरा विवादित मुद्दा मुंबई में हुआ आतंकवादी हमला रहा. भारत हमले में शामिल रहे पाकिस्तानी आरोपियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए समय निर्धारित करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि उनकी न्यायिक प्रक्रिया स्वतंत्र है, इसलिए कोई समय तय नहीं किया जा सकता है. पाकिस्तान की अदालत अपने हिसाब से अपने नियम-क़ानून के तहत यह काम करेगी. चौथा विवादित मुद्दा बलूचिस्तान के रूप में उभरा. पाकिस्तान इस बात को साबित करने की चेष्टा कर रहा है कि बलूचिस्तान में भारत आंदोलनकारियों को सहायता कर रहा है. इस पर भारत के विदेश मंत्री ने दो टूक कहा कि पाकिस्तान अब तक कोई सबूत पेश नहीं कर सका है. बातचीत विफल होने की पांचवी और आख़िरी वजह यह थी कि दोनों देशों ने एक दूसरे पर अड़ियल और ज़िद्दी होने का आरोप लगाया. पाकिस्तान का मानना है कि उससे जुड़े मामलों पर भारत ज़रा भी नरमी बरतने को तैयार नहीं है. जबकि भारत का मानना है कि पाकिस्तान आपसी मसलों को सुलझाने का इच्छुक ही नहीं है, क्योंकि वह हर बार अपने गोलपोस्ट का ही स्थान बदल देता है. इतना सब कुछ होने के बावजूद एक अच्छी बात यह हुई कि दोनों देशों ने बातचीत को जारी रखने का फ़ैसला किया है. लेकिन सवाल तो यह है कि दोनों देशों के बीच इस बार जिस तरह से बातचीत हुई है, उस तरह की वार्ताओं से कोई हल नहीं निकलने वाला है. पाकिस्तान में फ़िलहाल प्रजातंत्र है, जनता की चुनी हुई सरकार है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहां फिर से सेना दस्तक दे रही है. भारतवासियों की तरह ही आम पाकिस्तानी भी अमन और शांति चाहता है, लेकिन सरकार की अपनी मजबूरी है. पाकिस्तान की सरकार एक कमज़ोर सरकार है. सेना और आईएसआई उसकी पकड़ से बाहर हैं. यह ऐसी ख़तरनाक स्थिति है, जिससे निपटने में ही सरकार उलझ गई है. सरकार को इस बात का डर है कि आतंकियों के ख़िलाफ़ कोई क़दम उठाए जाने से पाकिस्तान के अंदर गृहयुद्ध जैसा माहौल बन सकता है. अगर भारत पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहता है तो पाकिस्तान की हक़ीक़त को नजरअंदाज़ करके शांति स्थापना की उम्मीद कैसे की जा सकती है. इसी तरह भारत भी आतंकियों के निशाने पर है. इन आतंकी संगठनों का संचालन पाकिस्तान से हो रहा है. भारत की जनता आतंक से निजात चाहती है. पाकिस्तान को भी यह समझना पड़ेगा कि जब तक हिंदुस्तान में बम धमाके होते रहेंगे, तब तक रिश्ते नहीं सुधर सकते. जब तक कश्मीर के आतंकी संगठनों को पाकिस्तान मदद करता रहेगा, तब तक किसी बातचीत से कोई भी हल नहीं निकल सकता है. बातचीत का मुद्दा दोनों के बीच विश्वास बढ़ाने का होना चाहिए. अगर दोनों ही देश एक दूसरे की दिक्कतों, मजबूरियों और परेशानियों को नज़रअंदाज़ करेंगे तो हर बातचीत का नतीजा वही निकलेगा, जो इस बार निकला है.

आज़ादी के बाद से ही भारत और पाकिस्तान की जनता दोनों सरकारों को सुन रही है. दिल्ली से कहा जाता है कि पाकिस्तान आतंकियों को भारत विरोधी गतिविधियों में मदद कर रहा है. उधर इस्लामाबाद से यह कहा जाता है कि भारत में लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं. दोनों देशों में इस तरह के लोग हैं, जो शांति नहीं चाहते, क्योंकि इसमें उनका नुकसान है. हालांकि ऐसे लोग बहुत कम हैं. दोनों देशों के बीच रिश्ता कैसा हो, यह मामला दोनों देशों की सरकारों के पास है. दोनों देशों की जनता अमन चाहती है, दोस्ती चाहती है, लेकिन सरकार तो सरकार होती है, जनता की पसंद और नापसंद से भला उसे क्या मतलब. पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी ने कहा कि हम लोग राजनीतिज्ञ हैं और राजनीतिज्ञ बातचीत में विश्वास रखते हैं. चारों ओर निराशा के माहौल के बीच भी आशा की किरण ढूंढ़ लेते हैं. कुरैशी साहब ने यह तो सही ही कहा. दोनों देशों की जनता भी यह समझ रही है कि आप लोग राजनीतिज्ञ हैं और राजनीतिज्ञ सिर्फ़ बातचीत में ही विश्वास रखते हैं.

manish@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी

तीन महीने में रचा इतिहास

- हिन्दी की सबसे पॉपुलर वेबसाइट
- हर महीने 12,00,000 से ज़्यादा पाठक
- हर दिन 40,000 से ज़्यादा पाठक
- स्पेशल प्रोग्राम-भारत का राजनीतिक इतिहास
- समाचार-राजनीति, खेल, पर्यावरण, मनोरंजन
- संगीत और फ़िल्मों पर विशेष कार्यक्रम
- साई की महिमा

www.chauthiduniya.tv

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301

पुंडलीक राव ने बाबा के चरण पकड़ कर अपना अपराध स्वीकार करते हुए क्षमा याचना की.

बाबा का निमंत्रण...

कृष्ण की नगरी वृंदावन में निर्मित किए जा रहे साई मंदिर की एक-एक ईंट देश-विदेश के कोने-कोने से साई भक्तों द्धारा आ रही है. पांच सौ रुपये की एक ईंट का दान करते ही साई भक्त महसूस करता है कि यह मंदिर उसका अपना है. ग़रीबनवाज़ बाबा का हर भक्त चाहता है कि वह बाबा के लिए कुछ करे.

कनु प्रिया

शिरडी के साई बाबा कलयुग के अंतिम देवदूत माने जाते हैं. वह परमात्मा का पैग़ाम लाए श्रद्धा और सबूरी. सबका मालिक एक की माला गिनता यह फ़क़ीर कब और कहां से आया, कोई नहीं जानता. बाबा न सिर्फ़ अपने जीवनकाल में, बल्कि शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मस्वरूप में अपने भक्तों, शिष्यों एवं दर्द से तड़पती आत्माओं को जीवनदान देते रहे और स्वस्थ करते रहे. साई बाबा का नाम आते ही हर कोई ऐसा महसूस करता है, जैसे किसी बहुत नज़दीकी प्रियजन का नाम लिया गया हो. बाबा के जीवनकाल की कई ऐसी घटनाएं हैं, जो चकित करने के साथ-साथ भक्तों के प्रति उनके प्रेम और दया को दर्शाती हैं. आज भी आत्मस्वरूप बाबा की प्रेरणा से समय-समय पर ऐसे लोग आते हैं, जिनके माध्यम से बाबा अपना पैग़ाम भक्तों तक पहुंचाते हैं. साई भक्त परिवार की स्थापना भी बाबा की प्रेरणा से ही हुई. साई भक्त ऑसिम खेत्रपाल ने अपने जीवन में होते चमत्कारों को देखते हुए बाबा से प्रेरणा ली और बाबा के काम को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया. इस तरह से फाउंडेशन की स्थापना हुई. एक ऐसे परिवार की स्थापना, जिससे जुड़कर आम आदमी ने बाबा की मौजूदगी को महसूस किया. आज के टूटते परिवारों के दौर में अकेले होते आदमी को एक मार्गदर्शक के अलावा हर क़दम पर रास्ता दिखाने वाले एक आध्यात्मिक सद्गुरु की ज़रूरत है.

फाउंडेशन से अब तक जुड़े लगभग दस हज़ार लोगों ने अनुभव किया है कि बाबा के प्यार और उनकी दुआओं से जीवन के हर दर्द से मुक्ति मिली है.

बाबा के जीवन में ईंट का आध्यात्मिक महत्व था. कहते हैं, इस युग पुरुष के प्राण ईंट में थे, जिसे साधारण जीवन जीता फ़क़ीर अपने सिर के नीचे तकिए के रूप में रखकर सोता था. बाबा के प्राण त्यागने से पहले यही ईंट टूटकर दो टुकड़ों में बंट गई और बाबा को पता चल गया कि समय आ गया लौटने और देह के बंधन से मुक्त होने का. उन्हीं की प्रेरणा से ईंटदान शुरू हुआ. फाउंडेशन द्वारा कृष्ण की नगरी वृंदावन में निर्मित किए जा रहे साई मंदिर की एक-एक ईंट देश-विदेश के कोने-कोने से साई भक्तों द्वारा आ रही है. पांच सौ रुपये की एक ईंट का दान करते ही साई भक्त महसूस करता है कि यह मंदिर उसका अपना है. ग़रीबनवाज़ बाबा का हर भक्त चाहता है कि वह बाबा के लिए कुछ करे. अपने जीवनकाल में भी बाबा ज़बरदस्ती अपने भक्तों से दान कराते थे, ताकि उनके कर्मों का हिसाब-किताब हो जाए. बाबा आज भी जानते हैं कि एक ईंट दान करने वाला उनका हर भक्त अपने कितने ही कर्मों से मुक्त हो जाएगा. दूसरी तरफ फाउंडेशन से जुड़ा हर सदस्य अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है. इस परिवार में भक्तों को आत्मिक अनुभूति के साथ-साथ बाबा के प्रेम और प्रसाद स्वरूप अनेक तोहफ़े, जिनमें बाबा की विभूति से लेकर प्रतिमाएं, पादुकाएं, घड़ियां और बहुत कुछ शामिल है, मिलते हैं. फाउंडेशन से लगातार जाती फोन कॉल्स आपको बाबा का संदेश देती हैं, ओम साई राम...

यह आवाज़ सुनते ही हर भक्त को ऐसा महसूस होता है, जैसे उसे किसी अपने ने पुकारा हो. माया के जाल में फंसा वह व्यक्ति एकदम से किसी पवित्र सुगंधित वातावरण में पहुंच जाता है. रोज़मर्रा की दिक्कतों से जूझते उस व्यक्ति को बाबा का एक-एक वचन मरहम की तरह लगता है. बाबा के साई सच्चरित्र से मिलने वाले जवाब इतने सटीक होते हैं कि पूछने वाला हैरान रह जाता है. एक निमंत्रण हर तड़पती आत्मा को, इसका पैग़ाम प्राप्त करने का. बाबा का दरबार अपने प्रियजन के लिए सदा खुला है. ओम साई राम...

feedback@chauthiduniya.com

सच्चे गुरु थे साई बाबा

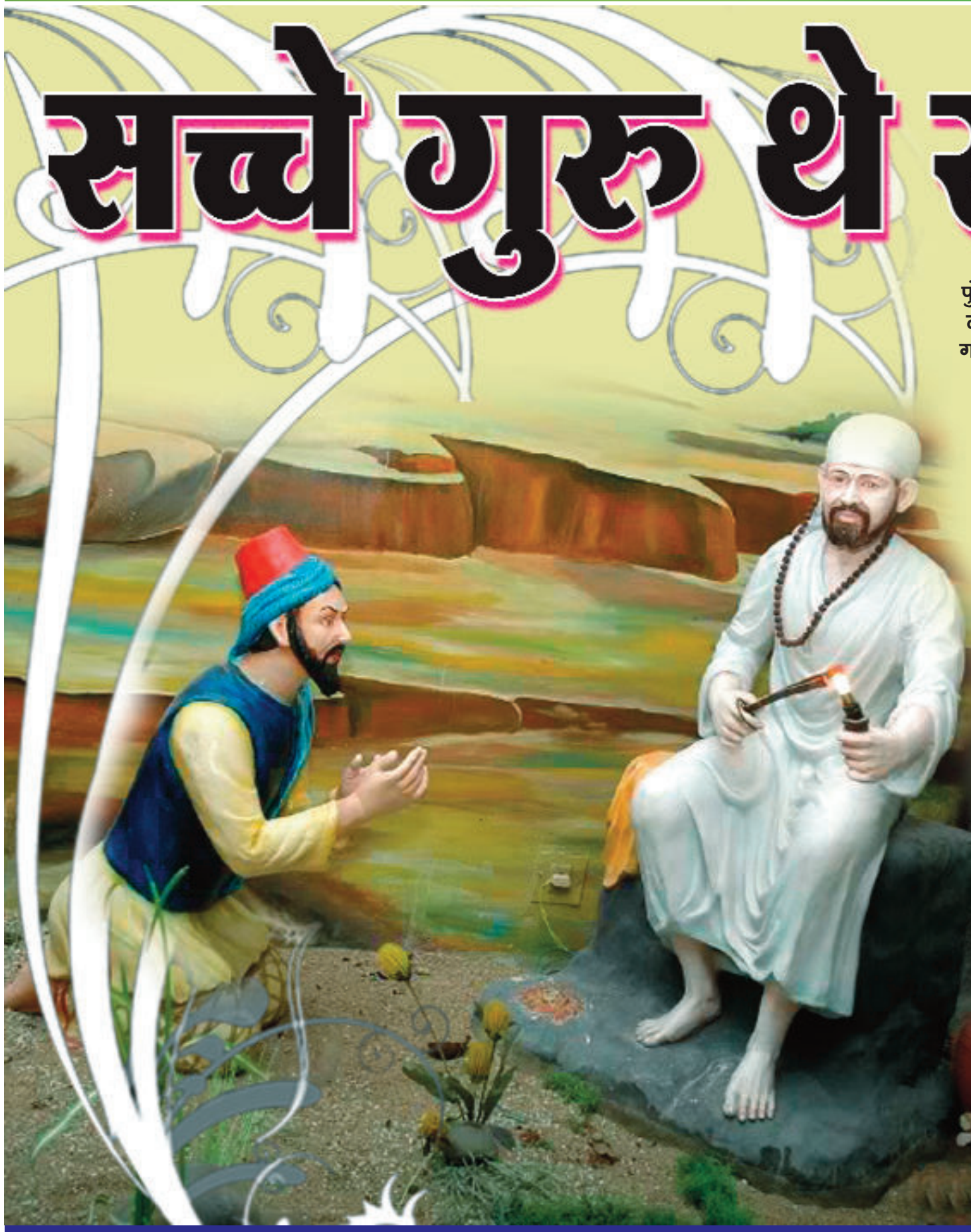

पुंडलीक राव अन्य मित्रों सहित श्रीफल लेकर शिरडी रवाना हुए. जब वह मनमाड पहुंचे तो उन्हें ज़ोरों की प्यास लगी. प्यास बुझाने के उद्देश्य से वह एक नाले पर पानी पीने गए. खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए, यह सोचकर उन्होंने कुछ चिवड़ा खाने के लिए निकाला. चिवड़ा खाने में कुछ अधिक तीखा प्रतीत हुआ.

एक बार वासुदेवानंद सरस्वती, जो टेंबेस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं, ने गोदावरी के किनारे रामहेंद्री में आकर डेरा डाला. वह भगवान दत्तात्रेय के कर्मकांडी, ज्ञानी, योगी भक्त थे. एक दिन नांदेड़ (निज़ाम स्टेट) के एक वक़ील अपने मित्रों सहित उनसे भेंट करने आए. इस दौरान वार्तालाप भी हुआ, जिसमें श्री साई बाबा की चर्चा निकल पड़ी. बाबा का नाम सुनकर स्वामी जी ने उन्हें प्रणाम किया और पुंडलीक राव (वक़ील) को एक श्रीफल देकर उन्होंने कहा कि तुम जाकर मेरे भ्राता श्री साई को प्रणाम कहना. साथ ही यह भी कहना कि वह मुझे भूल न जाएं और सदैव मुझ पर कृपादृष्टि रखें. उन्होंने यह भी बताया कि सामान्यतः एक स्वामी दूसरे को प्रणाम नहीं करता, परंतु यहां विशेष रूप से ऐसा किया गया है. पुंडलीक राव ने श्रीफल लेकर कहा कि मैं इसे बाबा को दे दूंगा. स्वामी ने बाबा को जो भाई शब्द से संबोधित किया था, वह बिल्कुल ही उचित था. उधर स्वामी जी अपनी कर्मकांडी पद्धति के अनुसार दिन-रात अग्नहोत्र प्रज्जवलित रखते थे और इधर बाबा की धूनी दिन-रात मस्जिद में जलती रहती थी. एक माह के पश्चात पुंडलीक राव अन्य मित्रों सहित श्रीफल लेकर शिरडी रवाना हुए. जब वह मनमाड पहुंचे तो उन्हें ज़ोरों की प्यास लगी. प्यास बुझाने के उद्देश्य से वह एक नाले पर पानी पीने गए. खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए, यह सोचकर उन्होंने कुछ चिवड़ा खाने के लिए निकाला. चिवड़ा खाने में कुछ अधिक तीखा प्रतीत हुआ. तीखापन कम करने के लिए किसी ने नारियल फोड़ कर उसमें खोपरा मिला दिया और इस तरह उन लोगों ने चिवड़े को स्वादिष्ट बनाकर खाया. दुर्भाग्यवश जो नारियल उनके हाथ से फूटा, वह वही था, जो स्वामी जी ने साई बाबा को भेंट में देने के लिए दिया था. शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्हें नारियल की याद आई. उन्हें यह जानकर बड़ा दुःख हुआ कि भेंट स्वरूप दिया जाने वाला नारियल ही फोड़ दिया गया. डरते-डरते और कांपते हुए वह शिरडी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने बाबा के दर्शन किए. बाबा को तो नारियल के संबंध में स्वामी से तार प्राप्त हो चुका था. इसलिए उन्होंने जाते ही पुंडलीक राव से कहा कि मेरे भाई की भेजी हुई वस्तु दो. पुंडलीक राव ने बाबा के चरण पकड़ कर अपना अपराध स्वीकार करते हुए क्षमायाचना की. वह उसके बदले में दूसरा नारियल देने को तैयार थे, परंतु बाबा ने यह कहते हुए उसे अस्वीकार कर दिया कि उस नारियल का मूल्य इस नारियल से कई गुना अधिक था. उसकी पूर्ति इस साधारण नारियल से नहीं हो सकती. फिर वह बोले कि अब तुम कोई चिंता न करो. मेरी ही इच्छा से वह नारियल तुम्हें दिया गया था और मार्ग में फोड़ा भी मेरी इच्छा से गया है. तुम स्वयं में कर्तापन की भावना क्यों लाते हो. कोई भी श्रेष्ठ या कनिष्ठ कर्म करते समय ख़ुद को कर्ता न जानकर अभिमान से परे होकर ही कार्य करो, तभी तुम्हारी प्रगति होगी. इस कथा से स्पष्ट होता है कि संत परस्पर एक-दूसरे को किस प्रकार भ्रातृवत प्रेम करते हैं. बाबा सही मायने में सच्चे गुरु थे. ॐ साई राम.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

सभी साई भक्तों को विनम्रता से सूचित किया जाता है कि आप अपने साई अनुभव, साई उत्सवों आदि की विस्तृत सूचना shirdisaibabafoundation@gmail.com पर मेल या 011-46567351/52 पर संपर्क कर सकते हैं.

नामग्याल भी स्वीकारते हैं कि बहिष्कार की भावना से बौद्ध–मुस्लिम संबंधों पर बुरा असर पड़ता है.

बेवफ़ाई का सुपर धमाका

अनंत विजय

हिंदी साहित्य में रवींद्र कालिया की ख्याति उपन्यासकार, कहानीकार और संस्मरण लेखक के अलावा एक ऐसे बेहतरीन संपादक के रूप में भी है, जो लगभग मृतप्राय: पत्रिकाओं में भी जान फूंक देते हैं. रवींद्र कालिया हिंदी के उन गिने–चुने संपादकों में से एक हैं, जिन्हें पाठकों की नब्ज़ और बाज़ार का खेल दोनों का पता है. धर्मयुग में जब रवींद्र कालिया थे तो पत्रिका के तेवर और कलेवर में उनका भी योगदान था. लेकिन जैसा कि आमतौर पर होता है कि हर बड़ी जीत का सेहरा टीम के कप्तान के सिर बंधता है. बाद के दिनों में जब कालिया जी की धर्मवीर भारती से खटपट हुई तो वह लौट कर इलाहाबाद चले आए. यह वही दौर था, जब कालिया जी ने काला रजिस्टर लिखा था. इलाहाबाद लौट कर रवींद्र कालिया ने जब गंगा–जमुना निकाला तो उसने भी साहित्य जगत में धूम मचा दी थी. हिंदी के पाठकों को 1991 में निकले वर्तमान साहित्य के दो कहानी महाविशेषांक अब भी याद होंगे. वर्तमान साहित्य के दो भारी–भरकम अंक अप्रैल और मई 1991 में प्रकाशित हुए थे. उस दौर में मैं कॉलेज का छात्र था और मुझे याद है कि जमालपुर के व्हीलर के स्टॉल चलाने वाले पांडे जी ने हमें वर्तमान साहित्य के वे अंक चुपके से इस तरह सौंपे थे, जैसे कोई बेहद क़ीमती चीज छुपाकर देता हो. उस वक़्त मुझे अजीब लगा था. कई दिनों बाद जब मैंने पांडे जी से पूछा तो उन्होंने बताया था कि उक्त अंकों की दस ही प्रतियां आई थीं और साहित्यानुरागी पांडे जी के मुताबिक़ उसके ज़्यादा ख़रीदार हो सकते थे. सो उन्होंने अपने चुनिंदा ग्राहकों को छुपाकर वर्तमान साहित्य का कहानी महाविशेषांक दिया था. यह हिंदी में पहली बार हुआ था, जब किसी भी विशेषांक को महाविशेषांक बताया गया हो. जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूं कि कालिया जी को पाठकों की रुचि के साथ–साथ बाज़ार की भी समझ है. वर्तमान साहित्य से पहले इस तरह का आयोजन 1958–60 में कहानी पत्रिका ने किया था, जिसके संपादक श्रीपत राय थे. कहानी के उन अंकों में अमरकांत की डिप्टी कलेक्टरी, कमलेश्वर की राजा निरवंसिया, मार्कंडेय की हंसा जाई अकेला जैसी बेहद प्रसिद्ध रचनाएं छपी थीं.

यही बात वर्तमान साहित्य के कहानी महाविशेषांक के साथ भी हुई. कालिया जी ने उन दो अंकों में लगभग संपूर्ण हिंदी साहित्य को समेट कर रख दिया था. कृष्णा सोबती की लंबी कहानी ए लड़की वर्तमान साहित्य के उस महाविशेषांक में ही छपी थी. बाद में स्पीड पोस्ट में उस पर तीन गंभीर टिप्पणियां छपने से कहानी को ख़ासी चर्चा मिली. बाद में यह उपन्यास के रूप में स्वतंत्र रूप से प्रकाशित हुई. साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त मशहूर लेखिका अलका सरावगी की पहली कहानी आपकी हंसी भी वर्तमान साहित्य के महाविशेषांक में ही प्रकाशित हुई थी. उस अंक में उपेंद्र नाथ अश्क का एक बेहद धमाकेदार लेख–महिला कथा लेखन की अर्धशती भी प्रकाशित हुआ था. किसी भी संपादक की दृष्टि पत्रिका को एक ऊंचाई देती है और कालिया ने इसे एक बार नहीं, कई बार साबित किया.

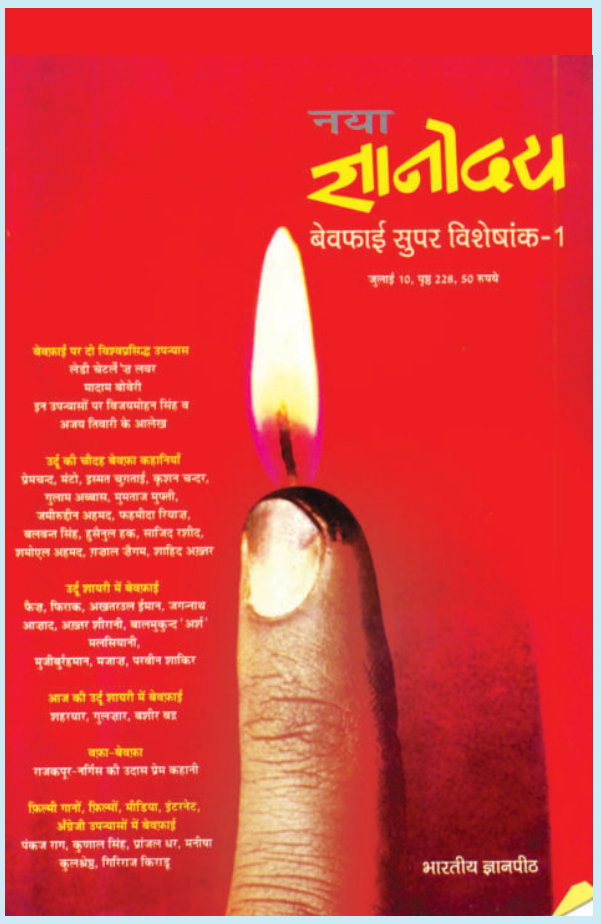

जब रवींद्र कालिया वागर्थ के संपादक होकर कोलकाता गए तो उन्होंने भारतीय भाषा परिषद की उस दम तोड़ती पत्रिका को भी न केवल खड़ा कर दिया, बल्कि हिंदी साहित्य की मुख्यधारा में लाकर उसे एक अहम पत्रिका बना दिया. वागर्थ का संपादन छोड़कर जब वह नया ज्ञानोदय आए तो इस पत्रिका का हाल भी बेहाल था और साहित्य के नाम पर बेहद ठंडी और विचारोत्तेजक सामग्री के अभाव में ज्ञानोदय एक सेठाश्रयी पत्रिका बनकर रह गई थी, जो इसलिए निकल पा रही थी, क्योंकि उसका प्रकाशन टाइम्स जैसे बड़े ग्रुप से हो रहा था. लेकिन कालिया ने संपादक का दायित्व संभालते ही ज्ञानोदय को हिंदी साहित्य की अनिवार्य पत्रिका बना दिया. रवींद्र कालिया के ज्ञानोदय के संपादक बनने के पहले हंस और उसके संपादक राजेंद्र यादव समकालीन हिंदी साहित्य का एजेंडा सेट किया करते थे, लेकिन जब मई 2007 में कालिया के संपादन में युवा पीढ़ी विशेषांक निकला तो पहली बार ऐसा लगा कि हंस के अलावा कोई और पत्रिका है, जो साहित्य का एजेंडा सेट कर सकती है. संपादक ने दावा किया कि 2007 में छपे युवा पीढ़ी विशेषांक की मांग इतनी ज़्यादा हुई थी कि उसे पुनर्मुद्रित करना पड़ा था. नया ज्ञानोदय के उक्त अंक को लेकर उस वक़्त अच्छा ख़ासा बवाल भी मचा था, लेकिन आख़िरकार रचना ही बची रहती है, सो उस अंक का एक स्थायी महत्व बना रहा. उन्होंने धीरे–धीरे पहले नवलेखन अंकों से कहानीकारों की एक नई फौज़ खड़ी कर दी. उसके बाद चार लगातार अंकों में प्रेम विशेषांक निकाल कर बिक्री के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले. संपादक के दावे के मुताबिक़, प्रेम विशेषांकों की कड़ी के पहले अंक को पाठकों की मांग पर कई बार प्रकाशित करना पड़ रहा है. आज जब हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाओं के संपादक पाठकों की कमी और बिक्री न होने का रोना रो रहे हैं, ऐसे में कालिया का यह दावा एक सुखद आश्चर्य की तरह है.

अब कालिया जी ने नया ज्ञानोदय का बेवफ़ाई सुपर विशेषांक–1 निकाला है. कहानी महाविशेषांक वह पहले ही निकाल चुके हैं. पाठकों को हर बार कोई नई चीज देनी होती है, लिहाज़ा अब सुपर विशेषांक. संपादकीय की पहली ही लाइन है, अगर वफ़ा का अस्तित्व न होता तो बेवफ़ाई नहीं होती. कई शायरों के मार्फ़त भी कालिया जी ने बेवफ़ाई को परिभाषित किया है. तक़रीबन सवा दौ सौ पन्नों के इस महाविशेषांक में वह हर रचना मौजूद है, जो पाठकों को न केवल बांधे रखेगी, बल्कि उसकी साहित्यिक वफ़ा को और मज़बूत करेगी. इस विशेषांक में प्रेमचंद, मंटो, इस्मत चुगताई से लेकर ओ हेनरी, मोपासां, हेमिंग्वे तक मौजूद हैं. बेवफ़ाई पर गुलज़ार ने जब ज्ञानोदय के संपादक को अपनी नज़्में भेजी तो लिखा, जनाब रवींद्र कालिया साहब. बे–पर कुछ नज़्में. मेरे यहां कुछ इल्ज़ाम और गिले–शिकवे नहीं हैं. मेरा ख्याल है, वह बे–भी नहीं. बस अलग हो गए. बे–कैसी. नज़्में ज़्यादा हैं, ताकि आप कुछ रद्द कर सकें. बे–को बस अलग हो गए मानने वाले गुलज़ार की नज़्म देखिए, और तुम ऐसे गई जैसे/कि बिजली चली जाए अचानक जैसे/मुझको/कमरे में बहुत देर तलक कुछ भी दिखाई नहीं दिया/तारीक़ी से मानूस हुई तो...फिर से दरवाजे का खाका सा नज़र आया.

सिर्फ़ गुलज़ार ही नहीं, बेवफ़ाई पर बशीर बद्र की नज़्में भी बेहतरीन हैं. इसके अलावा विदेशी उपन्यासों, मीडिया, फिल्मों और इंटरनेट की बेवफ़ाइयों पर भी अहम लेख हैं. कुल मिलाकर यह अंक पठनीय तो है ही, संग्रहणीय भी है. बेवफ़ाई सुपर विशेषांक–2 का भी ऐलान है, जिसमें नोवोकोब का प्रसिद्ध उपन्यास लोलिता भी प्रकाश्य है. आख़िरकार लोलिता भी तो अंत में बेवफ़ाई पर ही ख़त्म होती है. कालिया जी का यह प्रयोग क़ाबिले तारीफ़ है.

(लेखक आईबीएन–7 से जुड़े हैं)

feedback@chauthiduniya.com

पुस्तक अंश

मुन्नी मोबाइल

गतांक से आगे

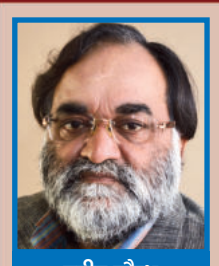

प्रदीप सौरभ

आनंद भारती को लगा कि जैसे मानसी ने हौले से उनके माथे को छुआ हो. उनकी नम आंखों को आहिस्ता से बंद किया हो और कहा हो...मैं हमेशा वहीं हूं, वहीं...जहां से दोस्ती का पाक रिश्ता शुरू होता है और रहता है...हमेशा–हमेशा.

पौ फटने को थी. कानपुर आने वाला था और इस उजाले की ओर बढ़ते सूरज को फिर से थाम लेने के लिए आनंद कुछ देर नींद की आगोश में चले गए. सुबह स्टेशन पर उनके परिचित मित्र उन्हें लेने आए थे. आनंद भारती बिल्कुल सामान्य दिख रहे थे, बेतकल्लुफी से बातें करते...कोई नहीं सोच सकता था कि बाहर से इतना बेफ़िक्र सा दिखने वाला यह व्यक्ति रात भर बेचैनी के किस तूफ़ान में डूबता–उतराता रहा है. तीन दिन के उस सेमिनार में आनंद भारती ने गर्मजोशी के साथ अपनी बात रखी. जमकर आलोचना–प्रत्यालोचना की. अख़बार ख़बरों से भरे रहे. आनंद भारती इलाहाबाद की सड़कों का हर इंच नापते रहे.

प्रवास के दौरान वह जब भी इलाहाबाद आते, दो काम उनके व्यक्तित्व में रचे–बसे थे, संगम किनारे जाना, कुछ देर लहरों को देखना और फिर ख़ामोश लौट जाना. दरअसल इलाहाबाद शहर की मिट्टी का अपना एक अलग सोंधापन है. इसकी धरती पर जिसने भी लंबा वक़्त बिताया है, उसके साथ किसी पवित्र रज सी यह जीवन भर यादों का तिलक बन मस्तक पर लगी रह जाती है. अमरूद के लिए मशहूर इस शहर में हर त्योहार का रंग यहां के मौसम में घुल–मिल जाता है. ख़ास चौक अपनी मिठाइयों, दालमोठ, समोसे, खस्ते और जलेबी की सुगंध के साथ–साथ सटी हुई दुकानों, तख्तों पर आसन बनाकर गद्दी पर टिके सेठों के लिए

चर्चित है. इसी तरह सिविल लाइंस का गोल गिरजाघर शहर के पुराने होने का एहसास कराता है. कटरा हो या कचहरी, हर इलाक़े की अपनी ख़ुशबू है और अपनी पहचान. तपती लू है तो जाड़े की ठंडक भी. यहां की छोटी–छोटी गलियों में भी रिश्तों की सुगंध बसी हुई है. रिक्शा, तांगे और इक्के सड़क पर अब भी मौजूद हैं. जगह–जगह पान की दुकानें हैं. पनवाड़ियों के यहां अड्डेबाज़ी आम है. लोग फुर्सत में दिखते हैं. पान खाना यहां के लोगों का धर्म है तो राजनीति की चर्चा इतनी सहज कि लगे मानों सबके सब ख़बरनवीस हैं या सांसद–विधायक. आनंद भारती ने शहर के चप्पे–चप्पे को जिया है. हर तरफ़ बेशक न जाएं, लेकिन गंगा तट पर जाना कभी नहीं भूलते. गंगा–जमुना के बीच एक अदृश्य, किंतु चमकती रेखा सूर्य की रोशनी में साफ–साफ दिखती है. दोनों के श्वेत–श्याम रंग अलग–अलग और पानी का हल्का और भारीपन भी दिखाई देता है. गंगा की गंदगी देखकर वह कुपित भी होते. शहर के लोगों ने गंगा की गंदगी पर एक जुमला भी बना दिया है, गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, बम्बे तब स्नानार्थ मुक्ति.

संगम का यह किनारा उन्हें जितना शांत बनाता, विश्वविद्यालय का परिसर उन्हें उतना ही बेचैन करता. पर उनके दूसरे काम का यह अनिवार्य हिस्सा था. हर बार की तरह इस बार भी वह आख़िरी दिन विश्वविद्यालय परिसर के सीनेट हॉल के सामने खड़े थे. इस हॉल में लगी घड़ी की आवाज़ उन्हें विशेष प्रिय है. इंग्लैंड से आई यह घड़ी आज भी सही समय बताती है. एक घंटे का समय पूरा करने पर वह विशेष तरह का संगीत सुनाती है. पर अब यह घड़ी उन्हें चिढ़ाने लगी है, समय के आगे भागने या फिर समय के साथ न चल पाने के लिए. मूल में समय का सम्मान ही छिपा है. आनंद भारती के लिए विश्वविद्यालय का यह हिस्सा उन्हें विशेष प्रिय था. वह कुछ देर वहां खड़े रहे. भावुकता का ज्वार एक बार फिर उन्हें अपने में सराबोर करना चाहता था.

अगले अंक में जारी...

विभिन्न धर्मों पर बुद्ध का समाधान

योगी सिकंद

लेह स्थित चोगलमसर के पास है केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान यानी सीआईबीएस. यह भारत के प्रमुख बौद्धिक अनुसंधान और शैक्षिक संस्थानों में से एक है. इसके प्रमुख डॉ. ताशी पालजोर हैं. वह मूलत: हिमाचल प्रदेश के लाहौल से हैं, लेकिन कई सालों से लद्दाख़ में ही रहते हैं. उन्हें लद्दाख़ी बौद्ध धर्म का विशेषज्ञ माना जाता है. पालजोर सभी धर्मों के बीच हो रहे विवाद का समाधान बौद्ध धर्म किस तरीक़े से कर सकता है, के बारे में मुझे बताते हैं. वह कहते हैं कि बुद्ध का कहना है कि सभी प्राणियों को अपनी मां के समान ही समझना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बीते जीवन में वह हमारी मां रही हो. दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि ख़ुद हमारे भीतर है. अगर इच्छा, जलन और द्वेष रूपी इन दुश्मनों को हम अपने भीतर से निकाल देते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं. फिर कोई दुश्मन नहीं बचता. उनका तर्क है कि इसके लिए धर्म परिवर्तन की कोई ज़रूरत ही नहीं है. हर किसी को अपने धर्म में ही रहना चाहिए. दूसरे धर्मों के अच्छे विचारों को ग्रहण करने में संकोच नहीं करना चाहिए. बुद्ध द्वारा अपनाई संवेदना (करुणा) की राह पर चलते हुए हर किसी को सभी जाति के लोगों के साथ समान रूप से और सभी प्राणियों से सहानुभूति रखनी चाहिए और सबके सुख–दु:ख में काम आना चाहिए. उनका मानना है कि इस रास्ते पर चलकर ही समूची मानव जाति सुखमय हो सकती है. यही वह मूलमंत्र है, जिससे हम ख़ुद के अहम और आत्मा की मरीचिका पर क़ाबू पा सकते हैं, जो हमारी इच्छाओं और ख़ुद की सभी समस्याओं की जड़ है. विभिन्न जीवों के बीच अंत:संबंध और परस्पर निर्भरता के सिद्धांत को अनुभव करने से ही विभिन्न धर्मों के प्रति सम्मान बढ़ता है.

मैंने उनसे कहा कि सैद्धांतिक तौर पर तो यह सब ठीक है, लेकिन लद्धाख़ में क्या हालात हैं? बौद्धों और मुसलमानों के बीच संबंध कैसे हैं? पालजोर बताते हैं कि बहुत सारे मुसलमान बौद्ध धर्म के अनुयायियों को ग़ैर मुसलमान, अल्लाह का विरोधी या अधर्म का समर्थक मानते हैं. अफ़सोस जताते हुए वह कहते हैं कि बेहतर संबंध न होने के पीछे यही सबसे बड़ी समस्या है. हालांकि वह यह भी बताते हैं कि सुधार हो रहा है. अब लेह के पास अपना स्वायत्त हिल काउंसिल है, बौद्धों और मुसलमानों के संबंध फिर से सामान्य हो रहे हैं, लेकिन पालजोर यह भी मानते हैं कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कश्मीर सरकार काउंसिल की शक्तियों को कमज़ोर करने की कोशिश नहीं करेगी. वह कहते हैं कि इसी वजह से एलबीए समेत बहुत सारे लद्दाख़ी बौद्ध अनुयायी अब लेह को केंद्र शासित क्षेत्र का दर्ज़ा देने की मांग कर रहे हैं. पालजोर ने मेरा परिचय गेशी कोंचोक नामग्याल से कराया, जो सीआईबीएस में बौद्ध दर्शनशास्त्र पढ़ाते हैं. नामग्याल लद्दाख़ में बौद्ध एवं मुस्लिम संबंधों का वर्णन एक यूनिक मॉडल के रूप में करते हैं और कहते हैं कि बहिष्कार के दौर को अलग कर दिया जाए तो बीते दिनों में वहां दोनों संप्रदायों के बीच कोई विवाद नहीं रहा. वह बताते हैं कि यह सच है कि पहले लद्दाख़ी बौद्ध राजाओं की लड़ाई स्कारडू और बलतिस्तान के शिया शासकों के साथ होती थी, लेकिन यह कोई सांप्रदायिक दंगा या धार्मिक युद्ध नहीं होता था. वह पूरे संप्रदाय को नहीं, बल्कि केवल पेशेवर सेनाओं को

शामिल करते थे. बहुत से बौद्ध राजाओं की फौज़ में मुस्लिम भी हुआ करते थे. यहां तक कि बहुतों की पत्नियां भी मुस्लिम होती थीं. उसी तरह बहुत सारे शिया शासकों ने बौद्ध लड़कियों से शादी की. नामग्याल बताते हैं कि आज भी करगिल के दाह–हानु जैसे कुछ सुदूर इलाक़ों में ऐसे कई परिवार हैं, जिनमें एक भाई मुसलमान है तो दूसरा बौद्ध.

नामग्याल भी स्वीकारते हैं कि बहिष्कार की भावना से बौद्ध–मुस्लिम संबंधों पर बुरा असर पड़ता है. वह कहते हैं कि एक पूरे संप्रदाय का बहिष्कार करना ग़लत था, लेकिन वह दलील देते हैं कि बौद्धों की शिकायत जायज़ थी, जिसकी वजह से जनभावना नियंत्रण के बाहर चली गई. लेह में स्वायत्त हिल काउंसिल को स्वीकृति दी गई, जिसमें मुसलमानों का भी प्रतिनिधित्व है. नामग्याल के अनुसार, अब बहिष्कार की घटना नहीं होगी, लेकिन वह कहते हैं कि धार्मिक नेताओं को बौद्ध और मुसलमानों के बीच बेहतर संबंध के लिए उचित भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि यह ऐसा विषय नहीं है, जिसे केवल राजनीतिज्ञों पर छोड़ा जा सकता है. वह कहते हैं कि सीआईबीएस मुस्लिम नेताओं को दलाई लामा के स्वागत जैसे कई समारोहों में आमंत्रित कर चुका है. बदले में मुस्लिम नेताओं ने भी कभी–कभी बौद्ध लामाओं को अपने समारोहों में आमंत्रित किया है. लेकिन वह स्वीकारते हैं कि यह संगठित रूप से नहीं किया गया. महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर ने चोगलमसर में तिब्बत शरणार्थियों के शिविर के पास काफ़ी बड़े क्षेत्र में अपना भवन बनाया है, जो लेह से ज़्यादा दूर नहीं है. यह केंद्र शिक्षा को बढ़ावा, स्वास्थ्य सेवा और एक–दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ाना आदि गतिविधियां संचालित करता है. समला फूंटसोग हाल में खुले महाबोधि करुणा हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं. वह ऑक्सफोर्ड स्थित इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर रिलिजियस फ्रीडम (आईएआरएफ) के लेह खंड के सचिव भी हैं.

वह कहते हैं कि लद्दाख़ में मुस्लिम और बौद्धों के बीच में धर्म पारंपरिक तौर पर सामंजस्यपूर्ण रहा है. वह बहिष्कार का वर्णन एक भूल और राजनैतिक तौर पर करते हैं. तो भी वह ज़ोर देकर कहते हैं कि आपसी विश्वास को बढ़ावा देने के लिए संगठित प्रयत्न करना चाहिए. ख़ासकर तब, जब युवा बड़ों द्वारा बताई राह से भटक रहे हों. फूंटसोग मुझे सूचना पत्रों का एक बंडल थमाते हैं, जिसमें उनके केंद्र और लेह में सांप्रदायिक सामंजस्य को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी है. यह केंद्र आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए कई सभाएं कर चुका है. हाल में भी इस तरह की एक सभा हुई थी, जो आईएआरएफ द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें सुन्नी, शिया, बौद्ध और ईसाई धर्म के नेताओं ने अपने–अपने धर्म के दृष्टिकोण के आधार पर शांति और सामंजस्य के महत्व का वर्णन किया. सभा के बाद लेह में शांति यात्रा भी आयोजित की गई. पिछले साल भी स्थानीय शिया और सुन्नी समुदाय द्वारा संयुक्त रूप से इसी तरह की सभा आयोजित की गई थी.

विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग एक साथ कैसे रह सकते हैं, जैसे सवाल के जवाब में फूंटसोग कहते हैं कि जियो और जीने दो. हालांकि कोई भी ऐसा नहीं सोचता है. उन्हें ख़ुद के विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए और दूसरों की भी स्वतंत्रता का ख्याल रखना चाहिए. वह मुझे इस केंद्र के कई मुस्लिम कामगारों और छात्रों के बारे में बताते हैं. उनका कहना है कि हम सब इस केंद्र में साथ मिलकर रहते हैं और हमें कभी कोई समस्या नहीं होती. फूंटसोग कहते हैं कि रोज़ सुबह बौद्ध प्रार्थना में इस आशय की व्याख्या की जाती है कि सभी संवेदनशील प्राणी ख़ुश और दु:खों से दूर रहें. सबका भला हो.

feedback@chauthiduniya.com

भारतीय बाज़ार में उतरने के बाद कंपनी का जोर ग्रामीण इलाक़ों की ज़रूरतों एवं मांग के मद्देनज़र उत्पाद मुहैया कराने पर रहेगा.

फंकी ज्वेलरी का ज़माना

अगर आप इस बार रक्षाबंधन कुछ ख़ास अंदाज़ में मनाना चाहते हैं तो अपनी बहन को एक ख़ास उपहार दें. उसे ख़ुश करने के लिए आप दे सकते हैं ट्रेंडी बॉबल्स के नए कलेक्शन के फैशन एक्सेसरीज. वैसे भी आजकल की फैशनेबुल कुड़ियों को स्टाइलिश और फंकी चीजें ही लुभाती हैं, चाहे उनकी ड्रेसेज हों या ड्रेस के साथ पहने जाने वाले एक्सेसरीज. लड़कियों को भारी-भरकम ज्वेलरी के बजाय हल्के-फुल्के स्टइस एवं एक्सेसरीज ही पसंद आते हैं. ड्रेस चाहे एथनिक हो या वेस्टर्न, सोबर हो या मॉडर्न, जंक ज्वेलरी हर ड्रेस पर ख़ूब जंचती है. यह सुंदर और स्टाइलिश होने के साथ-साथ भाइयों की जेब के लिहाज़ से भी उपयुक्त है. यह ज्वेलरी क्राफ्ट से बनी है. इसके नए कलेक्शन में पेंडेंट, इयररिंग्स, हुप्स और ब्रेसलेट आदि हैं. इन ज्वेलरीज में विभिन्न प्रकार के स्टोंस लगे हैं, जो सुंदर और ग्लैमरस लुक देते हैं. विभिन्न रंगों में अलग-अलग टेक्सचर और मैटेरियल से बने ब्रेसलेट, नेकलेस, इयररिंग एवं पेंडेंट ख़ास स्टाइल स्टेटमेंट बनाते हैं. मॉडर्न लड़की के हर रूप जैसे हिपस्टर, टॉम ब्वॉय, अपटाउन गर्ल, डिवा या चिक के लिए ट्रेंडी बॉबल्स के एक्सेसरीज बेस्ट सूटेड हैं. इन दिनों मिक्स एंड मैच के फैशन का जादू चल रहा है. इसी ट्रेंड पर मिक्स एंड मैच एक्सेसरीज भी है. ट्रेंडी बॉबल्स की परफेक्ट चिक ज्वेलरी लड़कियों की पर्सनालिटी में निख़ार ला देते हैं. ये एक्सेसरीज बदलते फैशन ट्रेंड को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं. इन्हें पहन कर लड़कियां अपने लुक को टफ बना सकेंगी और अपनी हिप-हॉप इमेज भी बरकरार रख सकेंगी. आधुनिक युवतियों को लुभाने के लिए ट्रेंडी बॉबल्स की ज्वेलरी इन दिनों बतौर एक्सेसरी ख़ूब चल रही है. इस ब्रांड में बोल्ड और मॉडर्न पैटर्न के साथ अलग-अलग शेप भी उपलब्ध हैं.

आमतौर पर देखा जाता है कि ज़्यादा उम्र की महिलाओं के लिए इस तरह की फंकी ज्वेलरी बाज़ार में उपलब्ध नहीं होती, लेकिन ट्रेंडी बॉबल्स न सिर्फ़ युवा लड़कियों के लिए हैं, बल्कि इन्हें बनाते समय आधुनिक विचारों वाली उम्रदराज़ औरतों को भी ध्यान में रखा गया है. अगर इन ख़ूबसूरत गहनों के दाम की बात करें तो ये काफ़ी किफ़ायती हैं और 69 रुपये से लेकर 799 रुपये तक की रेंज में उपलब्ध हैं.

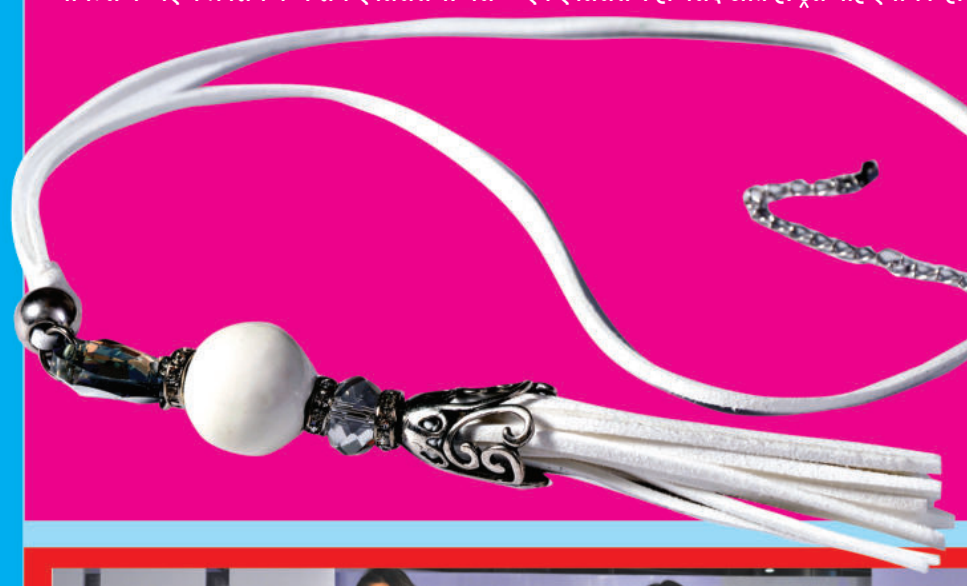

दिल्ली में 45वें इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर के दौरान आयोजित फैशन शो

यादों का जहां बनाएं

कुछ लोगों के जीने का अंदाज़ ही अलग होता है. उन्हें अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजें इकट्ठा करने का शौक़ होता है, जो बहुमूल्य होती हैं. जैसे कुछ बेहतरीन लम्हों की यादें. ऐसे ही लोगों के लिए स्टर्लिंग ने एक ख़ास प्रोडक्ट्स बाज़ार में उतारा है. कुछ यादें ऐसी होती हैं, जिन्हें आप हमेशा अपने दिल के क़रीब रखना चाहते हैं. ऐसी ही सुनहरी यादों को सुरक्षित रखने के लिए कैप्चर्स लाइफ ने मेमोरी बुक ईज़ाद की है. यह मेमोरी बुक उन यादों को सुरक्षित रखने के लिए परफेक्ट है, जिन्हें आप भूलना नहीं चाहते. यह टाइटल बेस्ड है, जिन पर आप अपनी यादगार बातों-पलों को लिख सकते हैं और समय-समय पर उन्हें पढ़कर ख़ुश हो सकते हैं. यह क्रिस्टल की चमकीली मेमोरी बुक है, जो बेहद सुरक्षित तरीक़े से आपकी यादों को संजोती है. यह आपके लिखे हुए को खुले पन्नों पर हाईलाइट करेगी, जिससे आते-जाते उन ख़ूबसूरत लम्हों की यादें ताज़ा हो जाएंगी और आप बेहद अच्छा महसूस करेंगे. यह दूसरों को तोहफ़े के तौर पर देने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है. स्टर्लिंग के इस प्रोडक्ट को आप शादी, एनिवर्सरी और जन्मदिन के मौक़े पर उपहार स्वरूप दे सकते हैं. इसके अलावा अगर आप अपने घर पर किसी विशेष मेहमान को बुलाना चाहते हैं और उसके आगमन की अमूल्य यादों को संजोना चाहते हैं तो स्टर्लिंग लाए हैं एक सुंदर सिग्नेचर बाउल, जिस पर आप अपने विशेष मेहमान का ऑटोग्राफ ले सकते हैं और उसे आजीवन संभाल कर रख सकते हैं. इस बाउल के साथ हीरे की निब वाली एक कलम भी है, जिससे ग्लास पर आसानी और सफ़ाई से लिखा जा सकता है. यही नहीं, एक कार्ड भी है, जिसे देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कलम कहां और कैसे रख सकते हैं. यादें संजोने का यह विभिन्न प्रकार का कलेक्शन सोएमी नगर साउथ दिल्ली स्थित द राइट एड्रेस बुटिक में उपलब्ध है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

शान की सवारी विंटो

शालीन गाड़ियों की निर्माता कंपनी वॉक्स वैगन ने भारतीय बाज़ार में अपनी नई कार वॉक्स वैगन वेंटो लांच की है. डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन में उपलब्ध इस कार के नए मॉडल में कुछ ख़ास बदलाव करके भारतीय ग्राहकों को लुभाने की कोशिश की गई है. भारत में काफ़ी लोकप्रिय रही हुंडई वेर्ना और होंडा सिटी की स्वीकार्यता को देखते हुए इन गाड़ियों के परिवर्तित रूप को वॉक्स वैगन ने विंटो मॉडल में प्रस्तुत किया है. वॉक्स वैगन विंटो पोलो प्लेटफॉर्म पर आधारित है. यह पोलो से 50 मिमी अधिक लंबी है. विंटो की सीट बेहद आरामदायक है. भारत में उतारा गया वॉक्स वैगन विंटो में यहां के शोफर्स यानी चालकों की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया गया है. इस कार में विशेष तौर पर हेडरूम और लेगरूम को आरामदेह बनाया गया है. यह कार ट्रेंडलाइन और हाईलाइन ट्रीम्स में उपलब्ध होगी. कार की ट्रेंडलाइन में चालक के बगल में एक एयरबैग, एबीएस और बिना चाबी के डिजिटल तरीक़े से खुलने वाले आधुनिक लॉक की विशेष सुविधा दी गई है. भारत में लांच के लिए विंटो के पूरे इंटीरियर रूम में बदलाव किया गया है. साथ ही इसके एयरकंडीशनर को और भी पावरफुल बनाया गया है. कार के हॉर्न को ज़्यादा तेज़ बनाया गया है और देश के वातावरण के हिसाब से सस्पेंशन सेटिंग्स डाली गई हैं. वेंटो का इंजन 1.6 लीटर डीजल और 1.6 लीटर पेट्रोल में 104 बीएचपी का पावर देता है. कार के इंटीरियर फ्लैश रेड और कैंडी व्हाइट कलर्स में उपलब्ध होंगे, जबकि कार शैडो ब्लू मेटालिक, डीप ब्लैक पर्ल, टेरा बैश मेटालिक और रिफलेक्स सिल्वर मेटालिक रंगों में उपलब्ध होगी. अभी तक कंपनी ने भारतीय बाज़ार में इन कारों की क़ीमत की कोई घोषणा नहीं की है. रॉयल कार वॉक्स वैगन विंटो शहर की सड़कों की शान दीवाली के आसपास बढ़ाएगी.

फोटो- सुनील मल्होत्रा

विदेशी मोबाइल का जलवा

सिंगापुर की कंपनी पाइन मोबाइल्स भारतीय दूरसंचार बाज़ार में क़दम रखने के लिए तैयार है. भारतीय ग्राहकों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा स्थानीय नज़रिया अपना कर कंपनी ने यहां अपनी पैठ बनाने की योजना बनाई है. कंपनी अत्यंत मुफ़ीद क़ीमतों पर तमाम बेहतरीन ख़ूबियों से लैस सुविधा और तकनीक मुहैया कराने जा रही है. कंपनी ने भारतीय बाज़ार में किंग, एग्जीक्यूटिव, ए-1, बी और ट्रायो जैसे कई विशेष मोबाइल मॉडल उतारे हैं. क्वर्टी की-पैड, बढ़िया म्यूज़िक, अच्छी क्वालिटी की पिक्चर देने वाला कैमरा आदि ख़ूबियों के साथ-साथ पाइन मोबाइल ने ई-मेल, 3-सिम तकनीक जैसी कई ख़ूबियों के मामलों में पहल की है. कंपनी के ट्रायो मोबाइल मॉडल में ट्रिपल सिम कार्ड का विकल्प दिया गया है, जबकि इसी रेंज के बाकी हैंडसेट्स में डुअल सिम कार्ड का विकल्प दिया गया है. ख़ूबसूरत डिजाइन, कंफर्टेबल की-पैड एवं स्टाइलिश लुक के साथ-साथ एंट्री लेवल के फोन में भी वीडियो का विकल्प दिया गया है. पाइन मोबाइल के एक्सक्लूसिव हैंडसेट रेंज की क़ीमत 1800 से 4000 रुपये तक है.

भारतीय बाज़ार में उतरने के बाद कंपनी का ज़ोर ग्रामीण इलाक़ों की ज़रूरतों एवं मांग के मद्देनज़र उत्पाद मुहैया कराने पर रहेगा. इस नज़रिए के साथ कंपनी ने पूर्वोत्तर और उड़ीसा जैसे राज्य में पहले प्रवेश किया है और अब कंपनी दक्षिण भारत, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, बिहार, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड में क़दम रखने जा रही है. एक्सक्लूसिव रेंज के लांच के मौक़े पर कंपनी के सीईओ रोहित अग्रवाल ने कहा कि कंपनी इन-स्टोर ब्रांडिंग और रिटेलर्स से समझौते करने पर ज़ोर दे रही है. कंपनी पहली तिमाही केअंत तक 5000 काउंटरों पर अपनी पहुंच बनाने का लक्ष्य सामने रखकर चल रही है. इन काउंटरों के जरिए कुल ख़ुदरा बिक्री का 70 फ़ीसदी क़ारोबार होता है.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

कुल मिलाकर सभी के सितारे डूब गए. अगर इतनी मेहनत ये क्रिकेट के लिए करते तो शायद इनका करियर यादगार बन जाता.

वर्ल्ड कप पर भारी बाबा पॉल

राजेश एस कुमार

स्पेन फीफा विश्व कप 2010 का चैंपियन भले ही बना हो, पर स्टार बनकर उभरा ऑक्टोपस पॉल. आलम यह रहा कि दुनिया भर के मीडिया ने मैच की सटीक भविष्यवाणियों के लिए ऑक्टोपस पॉल की जितनी चर्चा की, उतनी तो किसी खिलाड़ी, टीम या उसके प्रदर्शन को लेकर भी नहीं की. मैच ख़त्म होते ही ऑक्टोपस बाबा का गुणगान कुछ यूं हुआ, जैसे जीत के असली हक़दार खिलाड़ी न होकर ऑक्टोपस बाबा हों. प्रिंट मीडिया और टीवी चैनलों के अलावा कई बड़ी हस्तियां भी बाबा के जयगान में शामिल हुईं. सब के सब यही बता रहे थे कि बाबा ने 100 फ़ीसदी सही कहा था. बहुत ही कम लोग स्पेन की मेहनत और संघर्ष को जीत का श्रेय देते हुए दिखे. इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑक्टोपस पॉल की लगभग सभी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं, लेकिन उसकी एक भविष्यवाणी ग़लत भी साबित हुई. इससे इतना तो साबित होता ही है कि भविष्यवाणियां सिर्फ़ अंदाज़ की गणित पर चलती हैं. कभी-कभी यह गणित कुछ ज़्यादा ही सटीक बैठ जाती है, लेकिन इसे सार्वभौमिक सत्य मान लेना बेवकूफी से ज़्यादा कुछ और नहीं है. बाबा की इन भविष्यवाणियों के चलते मैच के कई ट्विस्ट और बेहतरीन मूवमेंट अनदेखे कर दिए गए.

स्पेन 12 साल के लंबे अंतराल के बाद विश्व कप चैंपियन बना. रविवार की रात मैच शुरू होने से पहले मेजबान देश दक्षिण अफ़्रीका की आज़ादी के महानायक नेल्सन मंडेला की मौजूदगी में दर्शकों का ज़ोश देखते ही बन रहा था. उनके ज़ोश और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच स्पेन ने अपनी बादशाहत दुनिया भर के सामने रख दी. यूरो चैंपियन स्पेन ने अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप प्रदर्शन करके हॉलैंड को अतिरिक्त समय में 1-0 से हराकर फुटबॉल का नया चैंपियन बनने का गौरव हासिल कर लिया. पहली बार चैंपियन बने स्पेन को इस जीत से तीन करोड़ डॉलर बतौर पुरस्कार राशि हासिल हुए, जबकि उप विजेता हॉलैंड को दो करोड़ 40 लाख डॉलर पर ही संतोष करना पड़ा. तीसरे स्थान पर रहे जर्मनी को दो करोड़ डॉलर की पुरस्कार राशि हासिल हुई.

मैच आख़िरी वक्त तक सस्पेंस के घेरे में रहा. हालांकि सट्टेबाजों और अंकशास्त्रियों की नज़र में स्पेन शुरू से ही खिताब का प्रबल दावेदार रहा, स्विट्जरलैंड के हाथों पहले मैच में मात खाने के बाद कुछ संशय ज़रूर हुआ, लेकिन स्पेन ने बहुत तेज़ी से वापसी की. फाइनल के दौरान नारंगी और नीली जर्सी पहने ये दोनों टीमें खेल रही थीं तो उनके जोश को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई भी टीम दूसरी टीम की रक्षा पंक्ति को तोड़कर गोल नहीं कर पाएंगी, लेकिन दूसरे अतिरिक्त पंद्रह मिनटों के दौरान स्पेन के आंद्रेस इनीइस्ता ने खेल के 116वें मिनट में गोल कर टीम का दामन खुशियों से भर दिया. इस मैच में रेफरी होवार्ड वेब ने कुल 14 येलो कार्ड दिखाए. यह किसी भी वर्ल्ड कप फाइनल में दिखाए गए सबसे ज़्यादा येलो कार्ड हैं. ऐसे ही कई दिलचस्प पहलुओं के साथ ख़त्म हुआ यह फाइनल मैच बाबा ऑक्टोपस की भविष्यवाणियों की चर्चा में धुंधला गया. अब कहा जा रहा है कि ऑक्टोपस बाबा संन्यास ले रहे हैं. यानी अब बाबा भविष्यवाणी नहीं करेंगे. आगे का तो पता नहीं, लेकिन इस दफ़ा बाबा वर्ल्ड कप पर ज़रूर भारी पड़ गए.

rajeshy@chauthiduniya.com

ट्रिक

यह जानने के लिए कि कौन सी टीम जीतेगी, ऑक्टोपस के जार में दो टीमों के फ्लैग वाले प्लास्टिक के बक्से उतारे जाते हैं. ऑक्टोपस दोनों बक्सों में से किसी एक में बैठ जाते हैं. बाबा जिस बक्से पर बैठते हैं, अंतत: वही टीम विजेता बनती है. यानी जिस बक्से में बाबा बैठे, समझो उसी को उनका आशीर्वाद मिल गया. अभी तक जिसे आशीर्वाद मिला है, वह टीम जीती है. सेमी फाइनल मुक़ाबले की भविष्यवाणी के लिए जब स्पेन और जर्मनी के झंडे वाले दो बक्सों को जार में उतारा गया तो ऑक्टोपस बाबा पहले दोनों बक्सों पर बैठ गए, पर अंत में फ़ैसला स्पेन के पक्ष में गया.

क्लीन बोल्ड

पॉल बाबा की भविष्यवाणी एक बार ग़लत भी साबित हो चुकी है. यूरो कप 2008 के फाइनल में ऑक्टोपस ने स्पेन के ख़िलाफ़ जर्मनी को विजेता बताया था, पर जर्मनी जीत नहीं सका.

सत्य वचन

स्पेन की जीत से पहले सर्बिया और जर्मनी के बीच ग्रुप मुक़ाबले में पॉल ने सर्बिया की जीत की भविष्यवाणी की थी. जर्मनी यह मैच 0-1 से हार गया था. शेष सभी मैचों में ऑक्टोपस ने जर्मनी की जीत की भविष्यवाणी की थी, जो सही साबित हुईं. पॉल बाबा ने खिताब के प्रबल दावेदार अर्जेंटीना के ख़िलाफ़ क्वार्टर फाइनल में भी जर्मनी की जीत की भविष्यवाणी की थी. लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि डिएगो माराडोना की टीम जिस धुरंधर फॉर्म में खेल रही थी, उसमें उसे हरा पाना काफी मुश्किल था, लेकिन जर्मनी ने एकतरफा मुक़ाबले में अर्जेंटीना को 4-0 से रौंदकर पॉल बाबा की भविष्यवाणी सच साबित कर दी.

फोटो – पीटीआई

पर्दे की चमक में अंधे खिलाड़ी

हाल ही में क्रिकेट से जुड़ी दो बड़ी ख़बरें सुर्ख़ियों में रहीं. पहली यह कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पहले संस्करण का ख़िताब जीतने वाली राजस्थान रॉयल्स टीम के छह खिलाड़ी सोनी पर प्रसारित होने वाले रिएलिटी शो इंडियन आयडल-5 में दिखेंगे. दूसरी यह कि निखिल आडवाणी की आगामी फिल्म पटियाला हाउस की शूटिंग के लिए कमेंटेटर संजय मांजरेकर एवं निखिल चोपड़ा समेत कई खिलाड़ी छुट्टी ले रहे हैं. ताज़ुब की बात यह है इन दोनों ख़बरों में सब कुछ था, सिवाय क्रिकेट के.

जबसे इस देश में आईपीएल और आईसीएल के बहाने क्रिकेट का व्यवसायीकरण हुआ है, तभी से इस खेल को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ लिया गया है. हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा अंडे पाने की चाह में मुर्गी को ही हलाल करने में जुटा है. खिलाड़ियों की बात करें तो इन्हें पैसे और ग्लैमर की चकाचौंध का ऐसा चस्का लगा है कि दिन-रात ये उसी में डूबे रहना चाहते हैं.

सीरीज़ से पहले चोटिल होकर मैदान से बाहर हो जाएंगे, लेकिन आराम के बजाय अधिक से अधिक पैसा कमाने की जुगत भिड़ाने में लग जाएंगे. विज्ञापन, कैंपेनिंग, लेटनाइट पार्टीज और टीवी तो इनका पुराना धंधा है, पर पिछले कुछ समय से इन्हें फिल्मी पर्दे पर दिखने का शौक़ चढ़ा है. कई खिलाड़ी फिल्में पर्दे पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को बेताब हैं. पटियाला हाउस में जहां कई खिलाड़ी मेहमान भूमिकाओं में नज़र आएंगे, वहीं सचिन के भी एक फिल्म में काम करने की ख़बरें आ रही हैं. सचिन से पहले भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान अनिल कुंबले भी मीरा बाई नॉट आउट में मेहमान भूमिका में नज़र आए थे. क्रिकेट खिलाड़ियों ने बेशक़ ऑफ़ द फील्ड फिल्मों में काम किया हो, लेकिन एकाध खिलाड़ी (सलिल अंकोला) की कामयाबी को अपवाद मान लिया जाए तो अधिकांश खिलाड़ियों का फिल्मों के चक्कर में करियर तक बर्बाद हो चुका है.

बहरहाल, क्रिकेटरों का फिल्मों के प्रति पहला प्यार सलीम अजीज दुर्रानी के रूप में 1973 में आई फिल्म इशारा में नज़र आया था. जब 1983 का विश्व कप जीतने का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था और उसी दौरान 1985 में फिल्म कभी अजनबी थे से संदीप पाटिल, सैयद किरमानी और लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर ने सिल्वर स्क्रीन पर पदार्पण किया. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ गई. इस फ़िल्म में क्लाइव लॉयड ने भी अतिथि भूमिका निभाई थी. गावस्कर ने कभी अजनबी थे के अलावा मराठी फ़िल्म सावली प्रेमाची एवं जाकोल और हिंदी फिल्म मालामाल में असफल पारी खेली. इसी तरह का फ्लॉप शो अनर्थ में सचिन के दोस्त विनोद कांबली ने दिखाया. मैच फिक्सिंग की सज़ा भुगत रहे हरफनमौला जडेजा को सुनील शेट्टी की होम प्रोडक्शन फिल्म खेल में मौका मिला, लेकिन हाल वही ढाक के तीन पात. फिल्म मुझसे शादी करोगी में हरभजन सिंह, जवागल श्रीनाथ, पार्थिव पटेल एवं आशीष नेहरा ने भी अतिथि भूमिकाएं निभाई थीं. कुल मिलाकर सभी के सितारे डूब गए. अगर इतनी मेहनत ये क्रिकेट के लिए करते तो शायद इनका करियर यादगार बन जाता. भारतीय क्रिकेटरों के अलावा पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहसिन ख़ान भी बॉलीवुड में हाथ आज़मा चुके हैं. मोहसिन जे पी दत्ता की फिल्म बंटवारा और महेश भट्ट की फिल्म साथी में नज़र आए. कुछ समय पहले निर्माता संघमित्रा चौधरी की फ़िल्म मैं और मेरी हिम्मत में रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर द्वारा काम करने की ख़बरों ने सबका ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन उन्होंने लंबी कवायद के बावजूद एक्टिंग नहीं की. फ़िलहाल उनकी जगह डोपिंग में फंसे पाक स्पीड स्टार मोहम्मद आसिफ इस फ़िल्म में अभिनय करने के कारण सुर्ख़ियों में हैं. ग़ौरतलब है कि दोनों का ही करियर ढलान पर है.

ब्रेट ली भी फिल्म विक्ट्री के जरिए सिल्वर स्क्रीन पर क़दम रख चुके हैं. इसमें उनके अलावा कई और दिग्गज क्रिकेटर मसलन स्टुअर्ट क्लार्क, जेसन गिलेस्पी, माइकल हसी, साइमन केटिच एवं एलन बॉर्डर, इंग्लैंड के साइमन जोंस एवं साजिद महमूद, न्यूजीलैंड के क्रेग मैकमिलन, डेरेल टफी, नाथन एसतल एवं मार्टिन क्रो के अलावा प्रवीन कुमार, आर पी सिंह, दिनेश कार्तिक, पंकज सिंह सहित कई जाने-पहचाने भारतीय युवा क्रिकेटर फिल्मों में काम कर चुके हैं. जबकि फ़िल्म में अंपायर का किरदार ऑस्ट्रेलिया के डेरेल हार्पर ने निभाया. इसी तरह ज़्यादातर खिलाड़ियों को जब अभ्यास सत्र में शामिल होकर प्रैक्टिस करनी चाहिए, वे फिल्मों में लगे रहते हैं. नतीजतन हमारी टीम के खेल में निरंतरता का अभाव रहता है. कोई भी खिलाड़ी आज सेंचुरी बना लेता या टीम को हारने से बचा लेता है तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वह अगली पारी में भी अच्छा खेलेगा. पर यह बात पक्की है कि वह कल किसी टीवी कार्यक्रम, विज्ञापन या फिल्म में ज़रूर दिखाई देगा. पर्दे की चमक में अंधे ये खिलाड़ी सब कुछ करेंगे, सिवाय खेलने के.

राजेश एस कुमार
rajeshy@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 26 जुलाई–1 अगस्त 2010

अन्य नायिकाओं की तरह सयाली भी अपनी फिटनेस और बॉडी मेंटेनेंस को लेकर ख़बरों में हैं, लेकिन उनका ख़ुद को फिट रखने का तरीक़ा दूसरों से थोड़ा हटके है.

उपेक्षित है एनिमेशन फिल्मों का संसार

फिल्म हनुमान की अपार सफलता के बाद भारत में एनिमेटेड फिल्मों का द्वार खुल गया है. नॉस्कॉम के रिपोर्ट के अनुसार, भारत में एनिमेशन फिल्मों का कारोबार वर्ष 2008 में लगभग 460 मिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जो प्रति वर्ष 27 प्रतिशत के अनुपात से बढ़ रहा है. वर्ष 2012 तक इसके 1.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाने की संभावना है. आईटी और बीपीओ ट्रेड बॉडी नॉस्कॉम के 2009 के प्रोजेक्ट के अनुसार, भारतीय बाज़ार में एनिमेशन का कारोबार 950 मिलियन का है. नॉस्कॉम ने उम्मीद जताई है कि इस इंडस्ट्री में 35-40 प्रतिशत तक बढ़त निश्चित रूप से दर्ज की जा सकती है. नॉस्कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, 85 घरेलू एनिमेशन फिल्मों के नाम रिलीज के लिए घोषित किए गए हैं और 28 फिल्में प्रोडक्शन की प्रक्रिया में हैं. यानी भारत में लगभग एक सौ एनिमेशन फिल्में निर्माण की प्रक्रिया में हैं. नॉस्कॉम की उपाध्यक्ष संगीता गुप्ता ने माना कि पिछले दो सालों में घरेलू एनिमेशन इंडस्ट्री में आश्चर्यजनक रूप से उछाल देखी जा रही है. मुख्यधारा में बनने वाली फिल्मों में भी एनिमेशन और स्पेशल इफेक्ट डाला जा रहा है. उदाहरण के तौर पर फिल्म द्रोण, तारे जमीं पर, जोधा-अकबर और लव स्टोरी 2050 आदि प्रमुख हैं. लेकिन बाल मनोरंजन के दूसरे साधनों की तरह एनिमेशन फिल्मों का क्षेत्र भी दक्ष लोगों के अभाव से जूझ रहा है. इसलिए बाल फिल्मों के विकास का चक्र रुक सा गया है. कई प्रोडक्शन कंपनियों जैसे यूटीवी, यशराज फिल्मस, रिलायंस बिग इंटरटेनमेंट ने घोषणा की है कि वे इस सेक्टर की कुछ बड़ी कंपनियों जैसे ड्रीमवर्क, वाल्ट डिजनी एवं पिक्चर एनिमेशन के साथ ख़ुद को जोड़ेंगी और भारत में इसका प्रसार करेंगी. कंपनियों ने निर्माण की अनुमानित लागत 15-20 मिलियन डॉलर तय की है. हमारे देश के लिए यह अच्छी बात है कि श्रेष्ठ एनिमेशन फिल्मों के दर्शक हर वर्ग में मौजूद हैं. भारत में जबसे एनिमेटेड फिल्में बनती हैं तो समाज में प्रचलित कहानियां या महाकाव्य उनके विषय होते हैं, जो बच्चों पर उतना प्रभाव नहीं डालते, जितना हॉलीवुड में बनने वाली फिल्में डालती हैं. एनिमेशन फिल्मों का बाज़ार भारत में तेजी से बढ़ता जा रहा है. पिछले एक साल में लगभग 85 शो हुए. 2008 में यहां बहुत सी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुईं, जैसे-रोड साइड रोमियो, घटोत्कच, दशावतार और माई फ्रेंड गणेशा-2.

अब तक आई कुछ एनिमेटेड फिल्मों में रोड साइड रोमियो, टुनपूर का राजा, सुल्तान द वैरियर, एक खिलाड़ी एक हसीना, महायोद्धा राम एवं अर्जुन आदि प्रमुख हैं. उक्त सभी एनिमेशन फिल्में बड़े बज़ट की हैं. इन फिल्मों के निर्माण की अनुमानित लागत राशि 25 से 45 करोड़ है, जो एक बड़े स्टारकास्ट वाली फिल्म की बज़ट राशि के बराबर है. भारत में एनिमेशन फिल्में अभी तक प्राथमिक स्तर पर बाहरी स्रोतों पर निर्भर थीं. एनिमेशन में पहले किसी चरित्र का निर्माण करके फिर उसे गतिमान किया जाता है. इसकी निर्माण प्रक्रिया में आर्टिस्ट, क्राफ्ट्स मैन, कार्टूनिस्ट, इलस्ट्रेटर, फाइन आर्टिस्ट, स्क्रीन राइटर, संगीतकार, कैमरा ऑपरेटर एवं मोशन पिक्चर डायरेक्टर सभी समान रूप से अपना योगदान देते हैं. एनिमेशन में इसप्रकार का रेखाचित्र बनाया जाता है कि उसके सजीव होने का भ्रम पैदा हो. भारत में बनने वाली पहली एनिमेटेड फिल्में रामायण और द रीजन ऑफ प्रिंस राम हैं. इसके बाद लगभग दर्जन भर फिल्में भारत में बनीं, लेकिन वे अधिकतर अंग्रेजी में थीं, वहीं उनमें एनिमेशन की क्वालिटी भी निम्न थी. यही वजह थी कि उक्त फिल्में मीडिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाईं, जो कि उनके असफल होने का एक मुख्य कारण रहा. फिर भी पिछले दिनों प्रदर्शित फिल्म हनुमान की सफलता के बाद कुछ आशा जगी. हालांकि इसमें इस्तेमाल किया गया एनिमेशन भी बहुत उच्च क्वालिटी का नहीं था. सहारा वन मोशन पिक्चर्स एवं पेंटा मीडिया ग्राफिक्स लिमिटेड के संयुक्त सहयोग से अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में बनी फिल्म लीजेंड ऑफ बुद्धा को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया. द लायन किंग, अलादीन, द ब्यूटी एंड द बेस्ट और हनुमान आदि 2-डी फिल्में हैं. दूसरी श्रेणी 3-डी के अंतर्गत आने वाली फिल्मों में शेक-2, ट्वाय स्टोरी, फाइंडिंग नेमों, द इंक्रेडिबल्स एवं मेडागास्कर आदि को पूरी तरह से कंप्यूटर पर निर्मित किया गया. स्क्रिप्ट, स्टेज से लेकर स्क्रीन तक 2-डी एवं 3-डी फिल्मों के निर्माण में 22 से लेकर 24 महीने तक समय लगता है.

एनिमेशन फिल्म कार्टून नहीं है, बल्कि यह एक आर्ट है. इस तरह की फिल्मों के निर्माण में बहुत से विचारों और मेहनत का समन्वय होता है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस क्षेत्र में हमारे यहां दक्ष लोगों का अभाव है. माना जाता है कि भारत में इस कला क्षेत्र में माहिर एवं पारंगत लोगों की कमी है, जबकि प्रति वर्ष एनिमेशन की पढ़ाई करके निकलने वाले छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है. अपने देश में इस क्षेत्र के साथ हो रहे भेदभाव को देखते हुए उनमें से ज़्यादातर छात्र विदेशों की ओर रुख़ कर लेते हैं. एनिमेशन फिल्मों के लिए विषय की बात की जाए तो भारत में कई अच्छी कथाएं हैं, जो समाज में प्रचलित भी हैं. इनमें से किसी भी कथा कथा को एनिमेशन फिल्म के रूप में विकसित किया जा सकता है और एनिमेशन की क्वालिटी भी बढ़ाई जा सकती है. हमारे देश के मनोरंजन जगत में बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता. इससे एनिमेशन फिल्मों का क्षेत्र भी अछूता नहीं है. अगर ऐसा चलता रहा तो देश में ख़ासतौर से स्थापित की गई बाल चित्र समिति होने के बावजूद बच्चों के स्वस्थ मनोरंजन का अभाव बना रहेगा.

प्रियंका प्रियम तिवारी

priyanka@chauthiduniya.com

फिटनेस के लिए फ़िक्रमंद सयाली

अभिनेत्री सयाली भगत भले ही अभी तक कोई हिट फिल्म न दे पाई हों, पर आजकल वह सुर्ख़ियों में हैं. बॉलीवुड की हर दूसरी नायिकाओं की तरह सयाली भी अपनी फिटनेस और बॉडी मेंटेनेंस को लेकर ख़बरों में हैं, लेकिन उनका ख़ुद को फिट रखने का तरीक़ा दूसरों से थोड़ा हटके है. वह अपनी छरहरी काया को बनाए रखने के लिए फाइट, एक्शन और मार्शल आर्ट का सहारा ले रही हैं. अपने सुडौल बदन को मेंटेन रखने के लिए उन्होंने मशहूर ट्रेनर यजनीश शेट्टी की मदद ली है. सयाली मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग का अनुभव बताते हुए कहती हैं कि यह ट्रेनिंग अभी प्राथमिक स्तर पर है. वह ख़ुद को फिट रखने के लिए इस तरह की कठिन ट्रेनिंग इसलिए ले रही हैं, क्योंकि यह न सिर्फ़ फिट रखती है, बल्कि स्टेमिना भी बढ़ाती है. इससे एक्सरसाइज हो जाती है और शरीर भी सक्रिय रहता है. यजनीश को अपना ट्रेनर चुनने की वजह बताते हुए सयाली कहती हैं कि वह अनुभवी हैं. उन्होंने बॉलीवुड के कई कलाकारों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी है. सयाली बताती हैं कि वह अब इस बात पर ज़ोर दे रही हैं कि उनका खानपान नियोजित रहे, जो कि उन्हें स्वस्थ और फिट रखेगा. मार्शल आर्ट आज के समय में रहन-सहन के लिहाज़ से ख़ुद को मेंटेन करने का एक अच्छा तरीक़ा है. यह विभिन्न समस्याओं और रोगों से लड़ने की ताक़त देता है. सयाली कहती हैं कि हर शख़्स को कम से कम एक प्रकार की मार्शल आर्ट ज़रूर सीखनी चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ़ आत्मरक्षा की भावना मजबूत होती है, बल्कि ध्यान, दृढ़ संकल्प और संयम में भी वृद्धि होती है.

रानी का रंग निराला

बॉलीवुड की हड़िप्पा गर्ल रानी मुखर्जी इन दिनों सिल्वर स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन उनके प्रशंसकों में उन्हें नज़र भर देखने की ख्वाहिश कम नहीं हुई है. जब उनके डिजाइनर दोस्त सब्यसाची मुखर्जी ने अपने स्टोर के लांच पर उन्हें बुलाया तो उनके प्रशंसक वहां बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए. इस मौक़े पर रानी ने अपने डिसेंट लुक को बदल कर थोड़ा फंकी लुक अपना लिया था. उन्होंने ऑलिव ग्रीन जंप सूट के साथ स्पैगटी पहन रखा था और होठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक लगा रखी थी. शाम के फंक्शन के हिसाब से उन्होंने आंखों को स्मोकी लुक दे दिया था. रानी ने बताया कि आजकल वह अपनी अगली फिल्म नो वन किल्ड जेसिका की शूटिंग की तैयारियों में लगी हुई हैं, जिसमें उनकी को-स्टार विद्या बालन हैं. इस फिल्म से उन्हें काफ़ी उम्मीदें हैं. एक तो उनकी फिल्में ही कम आ रही हैं और जो आ भी रही हैं, वे बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो रही हैं. अपनी हालिया रिलीज फिल्म दिल बोले हड़िप्पा के लिए उन्होंने क्या-क्या नहीं किया. अपना लुक बदल लिया, बॉडी पर मेहनत की, लेकिन फिर भी फिल्म फ्लॉप हो गई. हालांकि यह फिल्म लीक से हटकर थी और वुमेन क्रिकेट पर आधारित थी, लेकिन जनता की पसंद का क्या भरोसा! ख़ैर, रानी की आने वाली फिल्म नो वन किल्ड जेसिका में उनके और विद्या बालन के लिए डिजाइनर सव्यसाची मुखर्जी ने ड्रेस डिजाइन की है. सव्यसाची इससे पहले भी विद्या के लिए फिल्म पा में ड्रेस डिजाइन कर चुके हैं.

पिपली लाइव

इंटेलीजेंट इडियट आमिर ख़ान का नाम हमेशा से वैसी फिल्मों से जुड़ा रहा, जिन्होंने समाज में चर्चा का एक विषय तैयार किया हो. चाहे वह देशभक्ति की भावना वाली फिल्म सरफरोश हो या फिर बच्चों पर केंद्रित तारे ज़मीन पर अथवा प्रेम की खुशबू से सराबोर फिल्म गजनी. आमिर ख़ान की अधिकतर फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखाया. साथ ही आमिर ने दर्शकों के बीच अपनी बुद्धि का लोहा भी मनवाया. इस बार आमिर ख़ान फिर से एक ज्वलंत मुद्दे को उठाती फिल्म के निर्माण में व्यस्त हैं. इसमें उनकी पत्नी किरण राव ने भी सहयोग किया है. उनकी आने वाली फिल्म पिपली लाइव का विषय ग़रीबी की वजह से देश के किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याएं हैं. फिल्म में देश के एक गांव पीपली में रहने वाला किसान नत्था सरकारी कर्ज़ अदा करने के चक्कर में अपनी ज़मीन खो बैठता है. इसके बाद वह दाने-दाने के लिए मोहताज़ हो जाता है. परिवार को ग़रीबी से बाहर निकालने के लिए नत्था का भाई उसे ऑनर किलिंग की तरफ धकेलता है. इसके पीछे मंशा यह होती है कि आत्महत्या करने वाले किसान के परिवार को सरकार की तरफ से मुआवज़ा मिलता है, लेकिन नत्था इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो पाता. ऐसे में क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारियों, मीडिया और आसपास के लोगों का रवैया किस प्रकार उनके अपने फ़ायदे के लिए लगातार बदलता रहता है, फिल्म की कहानी इसी के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में नत्था का किरदार ओंकार दास मणिकपुरी ने अदा किया है. उनके अलावा रघुवीर यादव, मलाइका शेनॉय, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शालिनी वत्स, नसीरुद्दीन शाह और ख़ुद आमिर ख़ान ने भी विभिन्न किरदार निभाए हैं. फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाक़ों में की गई है. आमिर ने इस फिल्म में बतौर एक्टर मध्य प्रदेश के कुछ स्थानीय आदिवासियों को भी लिया है. फिल्म की कहानीकार एवं निर्देशक अनुषा रिजवी हैं. सेंसर बोर्ड ने फिल्म को यूनिवर्सल की जगह एडल्ट का सर्टिफिकेट दिया है. इसके पीछे दलील यह है कि फिल्म में कुछ गालियों का भी इस्तेमाल हुआ है. फिल्म में उठाए गए मुद्दे को व्यंगात्मक तरीक़े से पेश करने में अनुषा कितनी सफल हो पाती हैं, यह देखने वाली बात होगी. फिल्म आगामी 13 अगस्त को रिलीज होगी.

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 26 जुलाई-1 अगस्त 2010

www.chauthiduniya.com

अगड़ी जातियों पर सियासी डोरे

विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियां तेज़ होती जा रही हैं. राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण वोटों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है. इस पेंच को सुलझाने के लिए हर दल रोज़ नई चाल चल रहा है, क्योंकि इन वोटों की ताक़त का अंदाज़ा सभी को है. हर दल इस कोशिश में है कि इन तीनों को किसी तरह अपने खेमे में शामिल कर चुनावी जंग जीत ली जाए.

नीतीश कुमार को आशीर्वाद देती आनंद मोहन की मां.

सरोज सिंह

बिहार की चुनावी जंग की कुछ तस्वीरें तो धीरे-धीरे साफ हो रही हैं, लेकिन कुछ धुंध बरकरार है. सियासत के बड़े खिलाड़ी चुनाव मैदान में उतरने से पहले यह स्पष्ट कर लेना चाहते हैं कि कौन किधर है, ताकि न तो जनता के मन में कोई भ्रम रहे और न ही पार्टी किसी गफ़लत का शिकार हो जाए. मसला राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण वोटों का है, जिसे लेकर फिलहाल असमंजस की स्थिति बनी हुई है. मौजूदा राजनीतिक हालात से पैदा हुए इस असमंजस को दूर करने के लिए हर दल रोज़ नई चाल चल रह रहा है. नहले पे दहला फेंकने का दौर जारी है, पर पेंच सुलझने के बजाय फंसता ही जा रहा है. मसला साफ़ ही नहीं हो रहा है. राजपूत, भूमिहार एवं ब्राह्मण वोटरों की राजनीतिक ताक़त का अंदाज़ा हर दल को है, इसलिए हर दल इस कोशिश में है कि किसी तरह इन तीनों को अपने खेमे में शामिल कर चुनावी जंग जीत ली जाए.

अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो उस बार राजपूत, भूमिहार एवं ब्राह्मण वोटरों को लेकर भ्रम की स्थिति नहीं थी. कुछ अपवादों को छोड़ दें तो राजपूत और भूमिहारों के ज़्यादातर वोट राजग के पाले में गिरे. वहीं ब्राह्मणों के बड़े तबके ने भी राजग का साथ दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव में तस्वीर बदल गई. दिग्विजय सिंह को बांका से जदयू का टिकट न देकर नीतीश कुमार ने राजपूतों को नाराज़ कर दिया. दिग्विजय सिंह बांका से निर्दलीय जीते और राजद ने जिन चार सीटों पर जीत दर्ज़ की, उनमें तीन पर राजपूत प्रत्याशियों की जीत हुई. मतलब यह कि विधानसभा चुनाव की तरह राजपूतों का पूरा सहयोग राजग को नहीं मिला. कहा जा सकता है कि राजपूत वोटों को लेकर लोकसभा चुनाव में ही भ्रम की बुनियाद पड़ गई थी. यही कहानी भूमिहार और ब्राह्मण वोटरों की है. लोकसभा चुनाव के बाद बिहार के राजनीतिक हालात कई कारणों से बहुत तेज़ी से बदले और इस वजह से जाति के आधार पर दलों में खेमेबंदी भी तेज़ हुई. लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद से नाराज़ यादवों के गुस्से में नरमी अब साफ़ देखी जा सकती है. इसी तरह पासवान बिरादरी रामविलास पासवान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती दिख रही है, लेकिन दिग्विजय सिंह एवं ललन सिंह प्रकरण ने राजग के आधार वोट बैंक को हिलाकर रख दिया है. पूरे जोश के साथ राजपूतों एवं भूमिहारों ने नीतीश को पिछले विधानसभा चुनाव में साथ दिया, पर आज के हालात में कोई यह नहीं कह सकता कि इन दोनों बिरादरी के वोट किस दल के पाले में जाएंगे. राजग को पता है कि नुक़सान होना तय है इसलिए भरपाई की कोशिश जारी है. दूसरी तरफ राजद, लोजपा और कांग्रेस की कोशिश इन नाराज़ वोटरों को अपनी तरफ करने की है, ताकि नीतीश कुमार से हिसाब चुकता किया जा सके.

शायद पहली बार सबसे ज़्यादा छीनाझपटी राजपूत वोटों को लेकर हो रही है. इस वोट बैंक के नए दावेदारों में कांग्रेस के अलावा लोजपा-राजद गठबंधन सबसे आगे है. जदयू-भाजपा गठबंधन की कोशिश केवल नुक़सान कम करने की है. दिग्विजय सिंह के बांका से चुनाव जीतने और उसके बाद बिहार की राजनीति में दिलचस्पी लेने से राजपूत समाज को लगने लगा था कि पहली बार इस समाज को सही नेता मिलने जा रहा है, लेकिन दादा के असामयिक निधन से राजपूत बिरादरी एक बार फिर असमंजस में पड़ गई है. सियासी दलों का आकलन है कि दिग्विजय सिंह के निधन से उभरी सहानुभूति इस समाज के बड़े तबके को एकजुट करने में सफल रही है. यही वजह है कि उनके दाह संस्कार से लेकर श्राद्ध कर्म तक परिजनों को शोक संवेदना देने वाले नेताओं का तांता लगा रहा. लालू, नीतीश एवं पासवान के अलावा भाजपा और कांग्रेस के कई बड़े नेता दादा की पत्नी पुतुल सिंह से मिले तथा उन्हें सहयोग का भरोसा दिया. बताया जा रहा है कि सभी बड़े दलों ने उन्हें बांका के उपचुनाव में अपना सिंबल ऑफर किया है. इसके अलावा दादा के भाई त्रिपुरारी सिंह को भी जमुई या फिर बांका लोकसभा में पड़ने वाले किसी उपयुक्त विधानसभा क्षेत्र से टिकट देने का प्रस्ताव कुछ पार्टियों ने दिया है. फ़ैसला अब पुतुल सिंह एवं त्रिपुरारी सिंह को करना है. यह तय है कि जिसके पक्ष में उनका फ़ैसला होगा, उस दल को राजपूत वोटों का बड़ा फ़ायदा होगा. नीतीश दो बार पुतुल सिंह से मिलने गए थे. लालू और पासवान भी लगे हैं, लेकिन सबसे गंभीर प्रयास कांग्रेस की तरफ से हो रहा है. कांग्रेस को बिहार में एक मजबूत राजपूत नेता की तलाश है और पुतुल सिंह को अपने पाले में लाकर पार्टी इस समाज को साफ संदेश देना चाहती है. इसके अलावा कांग्रेस ने सत्येंद्र बाबू के जयंती समारोह के बहाने भी राजपूतों के मन को टटोलने और उन्हें अपने साथ खड़ा करने की कोशिश की. दूसरी तरफ राजद-लोजपा गठबंधन की नज़र प्रभुनाथ सिंह पर टिकी है. सारण इलाक़े में राजपूतों के वोट बटोरने की उम्मीद लगाए लालू-पासवान की कई दौर की बातचीत प्रभुनाथ सिंह से हो चुकी है. जल्द ही प्रभुनाथ सिंह इस खेमे में शामिल हो सकते हैं. दूसरी तरफ नीतीश कुमार पुतुल सिंह को तो प्रस्ताव दे ही आए हैं, साथ ही आनंद मोहन की भतीजी को शादी के बाद आशीर्वाद देने के लिए पंचगछिया पहुंच कर उन्होंने अपने विरोधियों को चौंका दिया है. कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही लवली आनंद एवं आनंद मोहन नीतीश के साथ खड़े नज़र आएंगे. नीतीश कुमार सत्येंद्र बाबू के परिजनों से भी मिल आए हैं. जहां तक भूमिहार वोटरों का सवाल है तो ललन सिंह प्रकरण के बाद वे काफी आहत हैं और नीतीश को मजा चखाना चाहते हैं. इस समाज में ललन सिंह के प्रति सहानुभूति साफ़ देखी जा सकती है. जदयू ने इस नुक़सान की भरपाई के लिए पहले विजय चौधरी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया, फिर जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार को पार्टी में शामिल किया गया. जगदीश शर्मा का निलंबन वापस करके भी जदयू ने भूमिहारों को संदेश देने की कोशिश की है. दूसरी तरफ, कांग्रेस की पूरी कोशिश ललन सिंह को पार्टी में शामिल करने की है. लालू प्रसाद लगभग हर सभा में यह कह रहे हैं कि वह कभी भी अगड़ी जातियों के ख़िलाफ़ नहीं रहे हैं. केवल उन्हें बदनाम करने के लिए तरह-तरह की झूठी बातें कही गईं. पासवान अगड़ी जाति के ग़रीबों को भी आरक्षण देने की घोषणा कर रहे हैं.

अगर ब्राह्मणों की बात की जाए तो सभी दलों में ब्राह्मण वोटों को लेकर ज़ोर-आज़माइश तेज़ हो गई है. नीतीश मिश्र को मंत्री पद से हटाकर नीतीश कुमार ने जो इस समुदाय की नाराज़गी मोल ली थी, उसकी भरपाई जगन्नाथ मिश्र को कैबिनेट मंत्री का दर्ज़ा देकर करने की कोशिश की गई है. इसी तरह कांग्रेस भी ब्राह्मण बहुल इलाक़ों में जाकर इस समुदाय को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है. पासवान और लालू भी इस काम में लगे हैं. कुल मिलाकर सभी दल जल्द इस काम को पूरा कर चुनावी अखाड़े में कूदना चाहते हैं, ताकि सत्ता की चाबी हाथ में आ जाए.

feedback@chauthiduniya.com

ललन लखीसराय से चुनाव लड़ेंगे !

विधानसभा चुनाव में ललन सिंह भी अपनी पूरी ताक़त झोंक देना चाहते हैं. अंदर ही अंदर बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है. उन्होंने अपने खासमखास लोगों तक संदेश पहुंचा दिया है कि वे चुनावी अखाड़े में कूदने के लिए तैयार रहें. ललन सिंह लखीसराय में एक बड़ी रैली कर सोनिया गांधी के समक्ष कांग्रेस में शामिल होंगे और उसी सभा में संसद से इस्तीफ़ा देकर लखीसराय से चुनाव लड़ने का ऐलान करेंगे. सूत्रों पर भरोसा करें तो कांग्रेस भी ललन सिंह को पूरा सम्मान देना चाहती है. बताया जा रहा है कि ललन सिंह के कहने पर ही लखीसराय में सोनिया गांधी की सभा का कार्यक्रम बनाया जा रहा है. इसके अलावा भूमिहार बहुल इलाक़ों में ललन सिंह से आक्रामक चुनाव प्रचार भी कराया जाएगा. कांग्रेस चाहती है कि भूमिहार बिरादरी में ललन सिंह के प्रति जो सहानुभूति उपजी है, उसे कांग्रेस के पक्ष में बटोरा जाए. कांग्रेस जनता को बताएगी कि नीतीश ने अपने कार्यकाल में भूमिहारों का अनेक मौक़ों पर अपमान किया. इसके अलावा ललन सिंह के माध्यम से कांग्रेस नीतीश की राजनीतिक कमज़ोरियों से भी वाकिफ़ होना चाहती है, ताकि चुनावी फ़ायदा उठाया जा सके. ललन सिंह की रणनीति भी साफ है. दादा के निधन के बाद अब इनकी कोशिश उनकी पत्नी पुतुल सिंह को भी कांग्रेस में शामिल कराने की है, ताकि भूमिहार एवं राजपूतों का थोक वोट कांग्रेस के पाले में गिर सके.

धुरदह चंवर की भूमि से जुड़े दर्जनों गांवों के किसान आज जोत के अभाव में आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं.

बाबाधाम के पेड़े का स्वाद बिल्कुल निराला होता है, जिसे चखते ही लोग समझ जाते हैं कि यह देवघर का पेड़ा है.

अलौली में ज़मीन तलाशती कांग्रेस

राजेश सिन्हा

खगड़िया में चुनावी नगाड़ा अभी से बजने लगा है. कहीं इसकी आवाज़ हल्की है तो कहीं तेज़, लेकिन अलौली विधानसभा सीट (सुरक्षित) पर चुनाव की आहट साफ़ सुनाई दे रही है. टिकट पाने की चाहत में नेता पटना से दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं. वे अपने कामों का बखान करके पार्टी आलाकमान को रिझाने की कोशिश में लगे हैं, ताकि उन्हें टिकट मिल जाए. वैसे तो सभी दलों के दर्जनों नेता टिकट के लिए अपने-अपने आका की चौखट चूम रहे हैं, लेकिन कांग्रेसी नेताओं में टिकट के लिए कुछ ज़्यादा ही होड़ मची है. बिहार के अन्य विधानसभा क्षेत्रों की बातों को अगर थोड़ी देर के लिए दरकिनार भी कर दिया जाए तो खगड़िया के अलौली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के कई दिग्गज नेता टिकट के लिए साम, दाम, दंड और भेद की नीति अपना रहे हैं. पार्टी से किसे टिकट मिलेगा और कौन हाथ मलता रह जाएगा, यह कहना तो अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इस क्षेत्र से डॉक्टर विद्यानंद दास, चंद्रदेव रजक, अविनाश कुमार अविनाश, वकील चौधरी एवं भानु प्रताप उर्फ गुड्डू पासवान सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग अपना नाम उजागर करने से बच रहे हैं.

अविनाश कुमार अविनाश | विद्यानंद दास | भानु प्रताप

अभी तक जो स्थिति दिख रही है, उसके मुताबिक़ भावी प्रत्याशियों में डॉक्टर विद्यानंद दास को छोड़कर अन्य कोई भी चुनावी अखाड़े में नहीं कूदा है, लेकिन इस बार चुनाव में कूदने के लिए कई नेता बेताब दिख रहे हैं. लगभग 15 वर्षों से बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ से जुड़े डॉक्टर विद्यानंद पासवान इसके पूर्व भी अलौली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन तब वह हार गए थे. इस बार अपनी जीत के प्रति आश्वस्त विद्यानंद का कहना है कि उन्होंने लोगों के सुख-दु:ख में काफी साथ दिया है. 15 वर्षों से कांग्रेस से जुड़े रहकर उन्होंने समाज के लोगों का काफी भला किया. अगर उन्हें अलौली से टिकट मिला तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद भी उन्हें ही मिलेगा और वह कांग्रेस का परचम लहराएंगे. अगर अविनाश कुमार की बात की जाए तो उन्होंने भी सामाजिक कार्यों में खूब बढ़-चढ़कर भाग लिया. अविनाश को राजनीति विरासत में मिली है. उनके पिता स्वर्गीय बागेश्वर पासवान कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में 1985 में अलौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए. अविनाश का कहना है कि अलौली का कई वर्षों से प्रतिनिधित्व कर रहे पशुपति कुमार पारस ने आज तक क्षेत्र के विकास में रुचि नहीं दिखाई. अलौली आज भी वहीं का वहीं है. कहीं भी विकास नहीं दिख रहा है. मुसहर बाहुल्य इस क्षेत्र के लोग आज भी विकास के लिए तरस रहे हैं.

अलौली विधानसभा क्षेत्र के अहुना-धुसमुरी निवासी चंद्रदेव रजक लगभग 40 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं. मुखिया होने के बाद उन्होंने ग्रामीणों के लिए कई बेहतर काम किए हैं. लोगों का कहना है कि स्थानीय होने के साथ-साथ चंद्रदेव ने समाज के लिए जो काम किए हैं, उनसे यह प्रमाणित हो गया है कि अगर वह विधायक बन गए तो क्षेत्र का विकास तय है. चंद्रदेव का कहना है कि अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीने का आनंद ही कुछ और है. चुनाव जीतने के बाद वह सर्वप्रथम क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से सेवानिवृत्त हुए ओलापुर गंगौर निवासी वकील चौधरी का कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है, लेकिन उनके पिता बनारसी चौधरी ने अपने समय में समाज के लोगों की सेवा करके परिवार की जो साख बनाई है, उसका फ़ायदा उन्हें मिलेगा. जिस तरह उन्हें लोगों का समर्थन मिल रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि उनकी राह में कोई भी कांटा नहीं बन सकेगा. वकील चौधरी ने कहा कि उनका इरादा जनता की सेवा करना है.

वकील चौधरी | चंद्रदेव रजक

जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके भानु प्रताप उर्फ गुड्डू पासवान भी टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं. हालांकि उन्होंने यह कहकर सबको चौंका दिया है कि वह किसी भी स्थिति में सुरक्षित क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि अगर पार्टी से टिकट मिला तो उनकी जीत सुनिश्चित है. ऐसी परिस्थिति में यह कहना शायद ज़्यादा श्रेयस्कर होगा कि किसी चहेते को टिकट दिलाने की कोशिश में ही भानु अपनी दावेदारी से इंकार कर रहे हैं. बहरहाल किसे पार्टी प्रत्याशी बनाया जाएगा और कौन हाथ मलता रह जाएगा, यह तो टिकट बंटवारे के बाद ही स्पष्ट होगा. फिलहाल पार्टी में टिकट के लिए होड़ मची हुई है. सभी ख़ुद को प्रबल दावेदार बता रहे हैं.

feedback@chauthiduniya.com

श्रावणी मेला यानी करोड़ों का कारोबार

बाबा वैद्यनाथ धाम का नज़ारा इन दिनों देखते ही बनता है. रेलमपेल भीड़, कतारबद्ध दुकानें, आवाज़ लगाते दुकानदार और मोलभाव करते लोग. सब कुछ इतना अच्छा लगता है, मानो समय कुछ पल के लिए रुक गया हो. मेले के दौरान करोड़ों रुपये का कारोबार होता है. इस एक महीने की कमाई से व्यापारी साल भर बैठकर खाते हैं.

श्रावणी मेला शुरू हो और देवघर के पेड़े की चर्चा न हो, ऐसा हो नहीं सकता. मेले में मुख्य रूप से बिकने वाली वस्तुओं में बाबा धाम का प्रसाद पेड़ा, चूड़ा, इलायची दाना, सिंदूर, चूड़ी के साथ-साथ लोहे के बर्तन एवं खिलौने काफी प्रसिद्ध हैं. बाबा धाम के पेड़े का क्या कहना! इसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है. इसका नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आने लगता है. पेड़ा खाते ही लोग समझ जाते हैं कि यह देवघर का पेड़ा है. बाबा धाम आने वाले श्रद्धालु निश्चित रूप से पेड़े की ख़रीदारी करते हैं. प्रमुख दुकानदारों के अनुसार, पिछले वर्ष श्रावणी मेले के दौरान 18 से 20 करोड़ रुपये का पेड़ा बिका. दुकानदार पेड़ा बनाने के लिए उत्तर प्रदेश एवं बिहार से लाखों क्विंटल खोया मंगवाते हैं. इससे रेलवे को काफी आमदनी होती है. इसके अलावा इलायची दाना एवं पतला चूड़ा भी श्रद्धालु अवश्य ख़रीदते हैं. इलायची दाना एवं चूड़ा की कुल अनुमानित बिक्री छह से आठ करोड़ रुपये आंकी गई है. इसका उत्पादन स्थानीय लघु एवं कुटीर उद्योगों में होता है, जहां सैकड़ों मज़दूर दिन-रात काम में लगे रहते हैं. पूजा-अर्चना के बाद श्रद्धालु चूड़ी, लहठी एवं बाबा धाम का सिंदूर भी ख़रीदते हैं. चूड़ी, लहठी एवं सिंदूर की कुल अनुमानित बिक्री लगभग 15 करोड़ रुपये की है. चूड़ी व्यापारी महीनों पूर्व राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से चूड़ी ख़रीद कर लाते हैं. सिंदूर का उत्पादन भी स्थानीय कुटीर उद्योगों में होता है. व्यापारी सिंदूर के लिए कच्चा माल निकटवर्ती राज्य बिहार के लखीसराय से मंगाते हैं. सिंदूर उत्पादन में सैकड़ों मज़दूर तीन महीने तक दिन-रात लगे रहते हैं. वंदना, शिवम, बेलपत्र, शिव-पार्वती एवं घूंघट आदि सिंदूर के प्रमुख ब्रांड हैं.

परंपरानुसार काफी संख्या में श्रद्धालु बाबा धाम से लोहे के बर्तन भी ख़रीदते हैं, जिनमें कड़ाही, खल-मूसल एवं छलनी आदि शामिल हैं. व्यापारियों के अनुसार, मेले में लगभग दस करोड़ रुपये से अधिक के लोहे के बर्तन बिक जाते हैं. इसके अलावा खिलौने, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री एवं बच्चों के कपड़ों की भी अनुमानित बिक्री दो से तीन करोड़ रुपये है. हज़ारों स्थायी एवं अस्थायी दुकानें 24 घंटे श्रद्धालुओं के लिए खुली रहती हैं, जहां हज़ारों कर्मचारी एवं दुकान मालिक उनकी सेवा में लगे रहते हैं.

मेले में भोजनालय एवं विश्रामालय से भी 20 से 30 करोड़ रुपये की आमदनी होती है. इसके अलावा निजी बसों, छोटे चार पहिया-तिपहिया वाहनों का परिचालन भी 24 घंटे होता है. इनसे लगभग दस करोड़ रुपये की आमदनी होती है. राज्य पथ परिवहन को भी लाखों की कमाई होती है. पिछले वर्ष वैद्यनाथ धाम एवं जसीडीह रेलवे स्टेशनों पर पांच करोड़ रुपये से अधिक की टिकटें बिकीं. व्यापार जगत से जुड़े लोगों के मुताबिक़, व्यापारी सिर्फ़ श्रावणी मेले की कमाई से साल भर आराम से जीवनयापन करते हैं. श्रावणी मेले से जुड़ी आमदनी में बाबा के मंदिर से जुड़े पंडों को यजमानों से मिलने वाली दक्षिणा को नज़रअंदाज़ करना बेमानी होगी, क्योंकि पंडों को दक्षिणा स्वरूप करोड़ों रुपये की आमदनी होती है. श्रावणी मेले में अधिकांश व्यापारी स्थानीय होते हैं. कुछ बाहरी दुकानदार भी यहां अस्थायी दुकानें लगाते हैं. लगभग एक हज़ार रिक्शा एवं ठेला चालक भी मेले के दौरान सक्रिय रहते हैं.

रणजीत झा
feedback@chauthiduniya.com

कब और कैसे हुई नटवर लाल की मौत, रहस्य बरक़रार

नटवरलाल का पुश्तैनी घर. इनसेट में नटवरलाल के ग्रामीण.

सीवान ज़िला मुख्यालय से लगभग 15 किमी पश्चिम में स्थित रूईया बंगरा जीरादेई प्रखंड का एक गांव है, जो कई टोलों में बसा है. देशरत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद के पैतृक गांव से तीन किमी दक्षिण में बसा है नटवर लाल का गांव बंगरा, जिसके पश्चिम में है रूईया टोला. इस तरह गांव का पूरा नाम रूईया बंगरा है. दुनिया में महाठग नटवर लाल के नाम से प्रसिद्ध मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव की मौत आज भी रहस्यमय बनी हुई है. समय-समय पर उसके निधन की ख़बर सुनकर गांव के लोग हतप्रभ हो जाते हैं. मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ नटवर लाल बचपन से ही शरारती था. उसकी शरारत हिंसक न होकर ठगीपूर्ण होती थी. अपने विद्यार्थी जीवन में ही ठगी को अपराध न मानकर लोगों को ठगना और उन्हें अचंभित करना उसका शौक था, जिसने उसे इस विद्या में माहिर बना दिया. वह अनेक बार जेल गया. हर बार जेल जाने के दौरान वह फख्र से कहता कि देश ही नहीं, बल्कि दुनिया की किसी भी जेल की दीवार चंद दिनों से अधिक उसे कैद नहीं रख सकती!

बताया जाता है कि अंतिम बार वर्ष 1996 में जब वह गिरफ्तार हुआ था, तब उन्हें कानपुर जेल में रखा गया था. वृद्धावस्था के कारण जेल में बीमार होने के बाद इलाज के लिए अदालत के आदेश पर उसे एम्स ले जाया गया. उसके साथ एक डॉक्टर, दो हवलदार और एक सफाईकर्मी था, लेकिन वापसी के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नटवर लाल पुलिसकर्मियों को झांसा देकर नौ दो ग्यारह हो गया. तबसे उसकी कोई ख़बर पुलिस नहीं जुटा पाई है. मिथिलेश कुमार ठगी का बेताज बादशाह था. उसके नाम पर देश-विदेश में अनेक ठग हुए, लेकिन उसका कोई सच्चा शार्गिद नहीं बन पाया! इस महाठग के नाम पर देश-विदेश में अनेक फिल्में भी बनीं.

लगभग बारह सौ बीघा ज़मीन पर बसे बंगरा गांव के मध्य में नटवर लाल का पुश्तैनी घर था. गांववालों का कहना है कि क़रीब 20 साल पहले कुर्की-जब्ती के दौरान पुलिस ने उनके पुश्तैनी घर को खंडहर बना दिया. आज इस घर की केवल एक-डेढ़ कट्ठा ज़मीन ही शेष बची है, जहां अगल-बगल के लोग गोबर फेंकते हैं. यहां पर दो हज़ार से ज़्यादा आबादी है. इस गांव के गोरख राजभर, बनारसी यादव और भगरासन साह का कहना है कि नटवर लाल के मरने की ख़बर चार साल पहले भी हम लोगों ने सुनी थी, जिनका श्राद्धकर्म शायद रांची में हुआ. गोरख राजभर ने बताया कि उनके पिता रघुनाथ लाल प्रसाद अच्छे आदमी थे. उनके बड़े बेटे मिथिलेश श्रीवास्तव उर्फ नटवर लाल और दूसरे बेटे गंगा लाल श्रीवास्तव थे. गंगा लाल की उम्र 90 वर्ष से ज़्यादा ही होगी. वह अभी भी महीने में दो-चार बार यहां ज़रूर आते-जाते रहते हैं. दोनों भाइयों को एक-एक पुत्री है. नटवर लाल की पुत्री की शादी रांची में हुई, जबकि गंगा लाल की पुत्री की शादी गोपालगंज में हुई है. इन दोनों भाइयों के बीच गांव में क़रीब आठ बीघा पुश्तैनी ज़मीन थी, लेकिन गंगा लाल जी अधिकांश ज़मीन बेच दी है. अब कुछ ही ज़मीन उनके पास रह गई है. नटवरलाल के घर की ज़मीन को छोड़ कर गंगा लाल ने अपने हिस्से की सारी ज़मीन बेच दी.

नटवर लाल के साथ पले-बढ़े गोरख राजभर बताते हैं कि आज भी बुजुर्गों से गांव की चौपालों पर नटवर लाल के किस्से सुनने के लिए जवान और बच्चे उत्सुक रहते हैं. एक बार की बात है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद अपने गांव जीरादेई आए हुए थे. सूचना पाकर नटवर लाल भी उनसे मुलाकात करने पहुंच गए. राजेंद्र बाबू का एक हस्ताक्षर देखकर नटवर लाल ने हूबहू पांच हस्ताक्षर करके उनके सामने रख दिए. यह देखकर राजेंद्र बाबू आश्चर्यचकित रह गए. इतना ही नहीं, नटवर लाल ने उनसे कहा कि भइया, इजाजत दें तो मैं भारत का विदेशी क़र्ज़ चुकता करके उन देशों पर ही भारत का दोगुना क़र्ज़ लाद दूं. इस पर समझाते हुए राजेंद्र बाबू ने कहा, ...ई सब काम तू छोड़ द, चलअ तोहरा के कवनो नौकरी लगा देब... पर नटवर लाल को नौकरी कहां रास आनी थी. वह हंसते हुए प्रणाम करके चलता बना...दूसरी ओर सच्चाई यह है कि पुलिस के पास भी उनके निधन का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, जिसके कारण उनकी ठगी के मामलों की फाइलें अभी भी लंबित और खुली बताई जाती है.

धनंजय मिश्र
feedback@chauthiduniya.com

किसानों की उम्मीदों पर पानी

आज़ादी मिलने के 63 वर्षों के बाद भी कृषि आधारित सारण ज़िले के पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों में खेती करने वाले किसानों की ज़िंदगी फटेहाल है. सरकार के लाख दावों के बावजूद उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है. दशकों पूर्व मांझी विधानसभा क्षेत्र के अधीन एकमा, रसूलपुर, ताजपुर, पकवारइनार एवं दाऊदपुर आदि गांवों में लगाए गए सरकारी ट्यूबवेल बिजली के अभाव में बंद पड़े हैं, जिसके चलते एकमा से सटे विशाल धुरदह चंवर की हज़ारों हेक्टेयर भूमि जोत और पानी के अभाव में बंजर हो गई है. धुरदह चंवर की भूमि से जुड़े दर्जनों गांवों के किसान जोत के अभाव में आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं. उनके परिवार के समक्ष बेकारी की समस्या उत्पन्न हो गई है. धुरदह चंवर के जोतदार एवं किसान भुइली गांव निवासी सच्चिदानंद सिंह ने बताया कि सबसे ज़्यादा हरपुर, एकमा, मदनपुरा, चंदा टोला, विशुनपुरा, बढ़ेया छित्रवलिया, एकड़ीपुर, भुइली एवं परसेगढ़ के सैकड़ों किसान प्रभावित हुए हैं. उन्होंने बताया कि यहां कभी धान, गेहूं और दलहनी फसलों की खेती होती थी, मगर सारण नहर प्रमंडल की मुख्य नहर के निर्माण के बाद जलभराव के कारण यहां की भूमि बंजर हो गई है. चंवर से जल निकासी के लिए जनता पार्टी की सरकार में सिंचाई मंत्री रहे सच्चिदानंद सिंह ने एक कार्ययोजना तैयार कराई थी, जिसके परिणामस्वरूप चंवर से जल निकासी का कार्य संभव दिखने लगा था, लेकिन बाद में यह योजना भी नाकाम हो गई.

राजद शासनकाल के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को भी धुरदह चंवर के लोगों ने जल निकासी को लेकर एक ज्ञापन दिया था. उस समय लालू प्रसाद छित्रवलिया उच्च विद्यालय में प्रसिद्ध मार्क्सवादी नेता कामरेड अंबिका सिंह की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करने आए थे, मगर वर्षों बीत जाने के बाद भी लोगों को इस समस्या से निजात नहीं मिल सकी. अब भी स्थिति जस की तस बनी हुई है. वहीं दूसरी तरफ एकमा स्थित विद्युत पावर सबस्टेशन की लचर स्थिति के चलते सरकार द्वारा लगाए गए दर्जनों ट्यूबवेल बेकार पड़े हैं. बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की उदासीनता के चलते लोगों को परेशानी हो रही है. दाऊदपुर, एकमा, मांझी, ताजपुर, रसूलपुर एवं चैनवा आदि क्षेत्रों के लिए महज़ 331 केवी का विद्युत प्रवाह किया जा रहा है. जबकि पिछले वर्ष ही मांझी में नए विद्युत पावर सबस्टेशन का निर्माण किया गया है. इसके बाद भी लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा. समस्या जस की तस है. हालांकि क्षेत्रीय जनता की मांग और ज़रूरत को देखते हुए सारण यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पावर ग्रिड सबस्टेशन बनाने की घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हो सकी. अब तो स्थानीय लोगों का विश्वास जवाब देने लगा है.

स्थानीय विधायक एवं राज्य के गन्ना विकास राज्यमंत्री गौतम सिंह ने बताया कि एकमा में पावर ग्रिड सबस्टेशन बनाने की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है. अब बहुत जल्द इस पर काम शुरू हो जाएगा. इसके अलावा एकमा को अनुमंडल बनाने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, जो आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान जोर पकड़ सकती है. इस मामले को लेकर स्थानीय बुद्धिजीवियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के समक्ष अपनी आवाज बुलंद की है, लेकिन जन समस्याओं से जुड़े मुद्दे प्रशासनिक उदासीनता के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं.

विजयेंद्र कुमार
feedback@chauthiduniya.com

मुंगेर की अर्थव्यवस्था का आधार-अवैध हथियार

मुंगेर की पहचान जहां देश और दुनिया में योग नगरी के रूप में है, वहीं दूसरी ओर अवैध हथियार भी इसकी पहचान बनते जा रहे हैं. यहां हथियार निर्माण का इतिहास काफ़ी पुराना है, लेकिन आज यह अवैध और जोख़िम भरा काम रोज़गार के बेहतर विकल्प के रूप में सामने आ रहा है.

बरामद हथियार.

हथियार बनाता कारीगर.

चाहे दक्षिण के तमिलनाडु या कर्नाटक में हथियारों का जखीरा पकड़ा जाए अथवा मुंबई, जम्मू-कश्मीर और पश्चिम बंगाल में हथियारों की बरामदगी हो, मुंगेर का नाम ज़रूर आता है. देसी कट्टे, बंदूक एवं राइफल से लेकर अत्याधुनिक पिस्टल, कारबाइन और एके- 47 तक मुंगेर में बनाई जा रही हैं. मेड इन इंग्लैंड, मेड इन अमेरिका, मेड इन जापान अंकित इन अत्याधुनिक हथियारों की क्वॉलिटी ऐसी होती है कि असली और नकली में कोई फर्क नज़र नहीं आता. लिहाज़ा मुंगेर निर्मित हथियारों की मांग दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. यही वजह है कि अवैध हथियार मुंगेर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुके हैं. एक अनुमान के मुताबिक़, यहां प्रतिदिन अवैध हथियारों का कारोबार लगभग 22 से 25 लाख रुपये का होता है. मुंगेर मुख्यालय से दस किलोमीटर की परिधि में बड़े पैमाने पर अवैध अग्नेयास्त्रों का निर्माण किया जाता है. मुफस्सिल थाना क्षेत्र का बरधै, चुरंबा, बाकरपुर, सुदुरखाना आदि ऐसे गांव हैं, जहां की आधी आबादी अवैध हथियारों के निर्माण एवं तस्करी में लगी है. मुंगेर शहर के बिंदवारा, शर्मा टोली, मकसुसपुर, बारा, मनिया चौराहा, कासिम बाजार, पुरानीगंज, चुआबाग, शादीपुर एवं दलहट्टा आदि मुहल्लों में सैकड़ों की संख्या में अवैध मिनी गन फैक्ट्रियां चल रही हैं. इन फैक्ट्रियों में हथियार निर्माण से लेकर इसकी तस्करी तक के काम में लगभग आठ हज़ार लोग लगे हुए हैं, जिनमें बच्चे, बूढ़े और महिलाएं तक शामिल हैं.

यूं तो मुंगेर में हथियार निर्माण का इतिहास काफी पुराना है और यहां के हुनरमंद कारीगरों की क्षमता भी अद्भुत है. आजादी के पूर्व से ही मुंगेर में बंदूक निर्माण का कारोबार चलता आ रहा है. पहले यहां के हुनरबंद कारीगर अपने घरों में बंदूक निर्माण कर उसे सरकारी अधिकारी के पास जमा करते थे. उसके बाद आयुध कारखाने में उसकी जांच होती थी और तब उसकी बिक्री होती थी. लेकिन आज़ादी के बाद इस व्यवस्था को एक नया रूप दिया गया. किला परिसर में बंदूक कारखाने की स्थापना कर बंदूक निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई, जो आज तक सरकारी देखरेख में चल रही है. जब हुनरमंद कारीगरों को काम नहीं मिला और उनके समक्ष रोज़ी-रोटी की समस्या उत्पन्न हुई तो अवैध हथियारों का कारोबार सबसे बड़ा विकल्प बनकर सामने आया. कम लागत में अधिक आमदनी वाले इस रोज़गार से लोग जुड़ते गए. धीरे-धीरे यह कारोबार इतने व्यापक स्तर पर फैल गया कि आज इससे प्रति वर्ष करोड़ों रुपये की कमाई की जा रही है. गंगा का दियारा क्षेत्र इस कारोबार को फलने-फूलने में काफी मददगार साबित हुआ, जहां आसानी से हथियारों का निर्माण किया जाता है.

यूं तो मुंगेर में हथियार निर्माण का इतिहास काफ़ी पुराना है और यहां के हुनरमंद कारीगरों की क्षमता भी अद्भुत है. आज़ादी के पूर्व से ही मुंगेर में बंदूक निर्माण का कारोबार चलता आ रहा है. पहले यहां के हुनरबंद कारीगर अपने घरों में बंदूक निर्माण कर उसे सरकारी अधिकारी के पास जमा करते थे. उसके बाद आयुध कारखाने में उसकी जांच होती थी और तब उसकी बिक्री होती थी. लेकिन आज़ादी के बाद इस व्यवस्था को एक नया रूप दिया गया.

कारीगर अपने हुनर का इस्तेमाल कर बेहतरीन हथियार बनाते हैं और सफेदपोश लोग उनकी मार्केटिंग करते हैं. यहां निर्मित हथियारों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए महिलाओं और बच्चों को लगाया गया है. जिस हथियार की लागत दो हज़ार रुपये होती है, उसे मुंगेर में पांच हज़ार रुपये में बेचा जाता है. महानगरों में पहुंचते ही इन हथियारों की क़ीमत पांच-छह गुना बढ़ जाती है. अवैध हथियार निर्माण से लेकर उसकी मार्केटिंग तक के लिए एक बड़ा नेटवर्क है. इस अवैध कारोबार में सबका हिस्सा तय है. पुलिस को भी उसका हिस्सा मिल जाता है.

बेरोज़गारी की समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा. ऐसे में यह कारोबार उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है. कम समय में अधिक पैसे कमाने की ललक भी युवाओं को इस ओर खींच रही है. मुंगेर में देश के विभिन्न हिस्सों से हथियार के व्यापारी यहां पहुंचते हैं. वे यहां से कई तरह के हथियार ख़रीद कर ले जाते हैं. यही कारण है कि जहां कहीं भी हथियार पकड़े जाते हैं, मुंगेर का नाम एक बार ज़रूर आता है. नक्सली संगठनों के पास मौजूद अधिकांश हथियार मुंगेर निर्मित हैं. यहां अवैध हथियार निर्माण के काम ने कुटीर उद्योग का रूप धारण कर लिया है. मुंगेर के एक पूर्व पुलिस अधीक्षक ने राज्य सरकार के गृह विभाग को एक प्रस्ताव दिया था कि यहां बड़े पैमाने पर अवैध हथियारों का निर्माण होता है, जो तकनीकी दृष्टि से उत्तम होते हैं. यदि सरकार यहां हथियार निर्माण की वैध व्यवस्था करे तो उसे कम लागत में अच्छे हथियार मिल सकते हैं और हथियारों के अवैध कारोबार को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन उस प्रस्ताव पर आज तक कोई पहल नहीं की गई. मुंगेर में आज़ादी के बाद अब तक कोई उद्योग-धंधे की स्थापना नहीं की गई, जिसके चलते यहां के युवा रोज़गार के लिए दर-दर भटकते हैं. इसलिए अवैध हथियारों का निर्माण उन्हें एक बेहतर विकल्प लगता है, भले ही यह काम अवैध और जोख़िम भरा है.

कल्याणी सिंह
feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 26 जुलाई–1 अगस्त 2010

मीठे पानी के डॉल्फिन कई कारणों से ख़तरे में हैं. गंगा की डाल्फिनों को सबसे ज़्यादा ख़तरा बेरोकटोक चल रहे शिकार से है.

ख़तरे में गंगा की डॉल्फिन

गंगा की डॉल्फिन ख़तरे में है. सरकार ने इसे राष्ट्रीय जल जीव घोषित कर लोगों में जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की है. भारत सरकार इसकी रक्षा के लिए समर्थन जुटाना चाहती है. सरकार का मानना है कि इस क़दम से युवा पीढ़ी में डॉल्फिन के संरक्षण और उन्हें बचाए रखने की भावना जागेगी, मगर असलियत यह है कि जिन लोगों पर इसे बचाने और इसके संरक्षण की ज़िम्मेदारी है, वही अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे हैं.

बिमलेश कुमार

भागलपुर के पास बना विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य सुल्तान गंज से कहलगांव तक 50 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है. यह एशिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है, जहां गंगा की विलुप्त हो रही डॉल्फिनों को संरक्षित और बचाने की पहल की गई है. यह अभ्यारण्य वर्ल्ड वाइड फंड (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) सहित कई अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और भारतीय संगठनों का मिलाजुला प्रयास है. सरकारी दस्तावेजों में गंगा डॉल्फिन को बचाने की मुहिम तेज़ कर दी गई है, लेकिन डॉल्फिनों का शिकार बंद नहीं हो रहा है. हाल ही में बिहार में गंगा नदी के किनारे चार डॉल्फिनें मरी पाई गईं. शिकारियों ने इन्हें पहले जाल में फंसाया, फिर इन्हें तब तक पीटा, जब तक इनकी मौत नहीं हो गई. अवैध शिकार की वजह से भारत में इन डॉल्फिनों की संख्या सिर्फ़ 2000 रह गई है.

डॉल्फिन की एक प्रजाति गंगा नदी में रहती है, जिसे आमभाषा में सोंस कहा जाता है. गंगा नदी के किनारे रहने वाले भी इसके सही रूप को देख नहीं पाते, क्योंकि यह सिर्फ़ सांस लेने के लिए पानी से ऊपर आती है और तुरंत ग़ायब हो जाती है. स्वभाव से यह काफी शर्मीली होती है. इंसानों को देखते ही दूर चली जाती है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गंगा की डॉल्फिन देख नहीं सकती. यह अंधी होती है. अंधी होने के बाबजूद यह अच्छी तैराक भी होती है और गहरे पानी में रहना पसंद करती है. यह शिकार को पकड़ने और देखने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करती है. इसकी लंबाई 5 से 8 फीट के क़रीब होती है और इसका वज़न 90 किलोग्राम के आसपास होता है. गंगैटिक डॉल्फिन मछलियों, मेंढकों और कछुओं की विभिन्न प्रजातियों के साथ ही अन्य जलीय जंतुओं को खाती है. हालांकि मछली इसका मुख्य भोजन है. यह भोजन की तलाश में अक्सर नदी के किनारे अपना समय बिताती है.

इसे गंगैटिक डॉल्फिन इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि इस प्रजाति की डॉल्फिन को सबसे पहले गंगा में देखा गया. इसका वैज्ञानिक नाम पलतानिस्ता गंगैटिक है. इस डॉल्फिन को साउथ एशिया की कई नदियों में देखा जा सकता है. गंगा के अलावा यह डॉल्फिन ब्रह्मपुत्र, मेघना, कर्णफुली और संगू आदि नदियों में भी पाई जाती है. गंगा डॉल्फिन उन चार डॉल्फिनों में से है, जो सिर्फ़ मीठे पानी यानी नदियों और तालाबों में पाई जाती हैं. चीन में यांग्त्से नदी में बायजी डॉल्फिन, पाकिस्तान की सिंधु नदी में भुलन डॉल्फिन और दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी में बोटो डॉल्फिन पाई जाती हैं, जो ख़त्म होने की कगार पर हैं. भारत में 1972 के वन संरक्षण क़ानून में ही इन डॉल्फिनों को लुप्त होने वाले जीवों में शामिल किया गया. भारतीय उपमहाद्वीप में सिर्फ़ 2000 गंगा डॉल्फिन बची हैं.

मीठे पानी की डॉल्फिन कई कारणों से ख़तरे में है. गंगा की डॉल्फिनों को सबसे ज़्यादा ख़तरा बेरोकटोक चल रहे शिकार से है. पैसे के लालच में मछुआरे इसका शिकार करते हैं. यह अंधी होती है, इसलिए मछुआरों के जालों में फंस जाती है. मछुआरे अगर चाहें तो इन्हें जाल से निकाल कर वापस नदी में छोड़ सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करते. वे इसे मार कर बाज़ार में बेच देते हैं. नीम-हकीम डॉल्फिनों की चर्बी से निकाले गए तेल से इलाज करते हैं. इसके तेल को लकवा, गीठा जैसी बीमारियों के लिए अचूक माना जाता है. इसका तेल काफ़ी महंगा होता है. यही वजह है कि गंगा की डॉल्फिनों का शिकार किया जाता है. गंगा की डॉल्फिनों को दूसरा ख़तरा गंगा में चलने वाली नावों और जहाजों से होता है. जिन इलाक़ों में यह रहती है, वहां आज भी यातायात के लिए नावों का इस्तेमाल होता है. यह देख नहीं सकती, इसलिए नावों से टकरा जाती है या फिर मल्लाहों के चप्पुओं का शिकार हो जाती है. डॉल्फिनों की घटती संख्या का तीसरा कारण गंगा नदी का प्रदूषण है. यह साफ़ और मीठे पानी में रहने वाली जीव है, लेकिन जिस तरह से गंगा नदी में प्रदूषण बढ़ रहा है, उसमें इन डॉल्फिनों का जीना मुश्किल हो गया है. साथ ही नदी के किनारे बैराज बनने के कारण भी गंगैटिक डॉल्फिन की संख्या कम होती जा रही है. नदियों पर बांध बनाने की वजह से यह एक-दूसरे से अलग हो जाती हैं, जिससे प्रजनन नहीं हो पाता. यही वजह है कि इसकी संख्या दिनोंदिन कम होती जा रही है.

गंगा की डॉल्फिन लुप्त होने की कगार पर है. सरकार द्वारा इसे सिर्फ़ भारत का जल जीव घोषित कर देने से स्थिति में कोई बदलाव नहीं आने वाला. ज़रूरत इस बात की है कि मछुआरों और स्थानीय लोगों को गंगा की डॉल्फिनों के बारे में जागरूक किया जाए. सोचने वाली बात यह है कि अब तक ऐसा एक भी मामला सामने नहीं आया है, जिसमें डॉल्फिनों के हत्यारों को सज़ा मिली हो. जिन अधिकारियों को इसे बचाने का काम सौंपा गया हैं, उनकी ज़िम्मेदारी भी तय होनी चाहिए. मासूम डॉल्फिनें तो अंधी हैं, लेकिन आंखों वाले अधिकारियों ने इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया है. अगर यह सिलसिला नहीं रुका तो यह शर्मीली डॉल्फिन सिर्फ़ किताबों में सिमट कर रह जाएगी.

bimlesh@chauthiduniya.com

देर आए दुरुस्त आए

1993 में जयपुर क्वीन का ख़िताब जीतकर ग्लैमर की दुनिया में प्रवेश करने वाली भोजपुरी फिल्मों की सेक्सी बाला साधिका रंधावा आज एक सफल अभिनेत्री हैं. उनकी पिछली फिल्मों प्यार के बंधन और पूरब की रिकॉर्ड तोड़ सफलता ने उन्हें नंबर वन की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है.

वर्ष 1997 में रिलीज फिल्म सलमा पे दिल आ गया में अयूब ख़ान के अपोजिट कास्ट हुई साधिका रंधावा को मीडिया ने हाथोंहाथ लिया. उस वक़्त उन्हें बॉलीवुड की अगली सुपर स्टार भी बताया जाने लगा, लेकिन साधिका के करियर ने ऐसी पलटी खाई कि सुपर स्टार बनना तो दूर, उन्हें हिंदी की अच्छी फिल्में भी मिलनी बंद हो गईं. हालत यह हुई कि उन्होंने कुछ एक कम बजट और बी ग्रेड की फिल्में साइन कर लीं. इसी कड़ी में उन्होंने फिर तौबा-तौबा, मेरी नई पड़ोसन, रिवाज, बुलेट, हफ्ता वसूली, दो अक्टूबर, प्यासा एवं सनम हरजाई जैसी फिल्मों में काम किया. ग़ौरतलब है कि उक्त सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरीं. उसके बाद वह फिल्म सत्ता में एक आइटम नंबर में भी नज़र आईं, पर बात न बनते देख उन्होंने साउथ की कुछ फिल्मों के ऑफर स्वीकार कर लिए. वहां भी बात नहीं बनी. कुछ सालों के अंतराल के बाद साधिका ने भोजपुरी फिल्मों में किस्मत आज़माने का फ़ैसला किया. एक बार असफलता का मुंह देख चुकी साधिका के लिए ख़ुद को साबित करने का यह आख़िरी मौक़ा था. इस बार उनकी किस्मत ने साथ दिया और उन्हें भोजपुरी फिल्मों में ज़बरदस्त कामयाबी मिली.

1993 में जयपुर क्वीन का ख़िताब जीतकर ग्लैमर की दुनिया में प्रवेश करने वाली भोजपुरी फिल्मों की सेक्सी बाला साधिका रंधावा आज एक सफल अभिनेत्री हैं. उनकी पिछली फिल्मों प्यार के बंधन और पूरब की रिकॉर्ड तोड़ सफलता ने उन्हें नंबर वन की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है. साधिका कहती हैं कि उन्होंने अपने करियर में कई ग़लतियां की हैं, लेकिन अब वह संभल गई हैं और भोजपुरी फिल्मों में अपना पूरा ध्यान लगा रही है. मतलब यह कि अब उनके जलवे भोजपुरी फिल्मों में ही दिखाई देंगे. इस समय उनके खाते में कई बड़ी फिल्में हैं, जिनमें भोजपुरी सुपर स्टार रवि किशन एवं मनोज तिवारी के साथ जनम जनम का साथ और रवि किशन के साथ पांडव प्रमुख हैं. चलिए हम तो यही कहेंगे कि देर आए, लेकिन दुरुस्त आए.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com